

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 11, 2015/भाद्र 20, 1937 No. 237] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2015/BHADRA 20, 1937

वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध श्ल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2015

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हैवी और मीडियम कॉमर्शियल वाहनों के लिए अपेक्षित 'फ्रंट एक्सल बीम' और 'स्टीयरिंग नॅकॅल' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा ।

सं. 15/11/2014-डीजीएडी.—समय - समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद से इसे अधिनियम कहा गया है) और समय - समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद से इसे नियमावली कहा गया है), को ध्यान में रखते;

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. यत: हैवी और मीडियम कॉमिशियल वाहनों के लिए अपेक्षित 'फ्रंट एक्सल बीम' (एफ ए बी) और 'स्टीयिरंग नॅकॅल' (एस के) (इसके बाद से इसे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के कुछेक घरेलू उत्पादों द्वारा दाखिल याचिका के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 8 दिसंबर, 2008 की अधिसूचना सं. 14/19/2008 - डी जी ए डी के तहत चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पाटनरोधी जांच आरंभ की थी। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना सं. 14/19/2008 - डी जी ए डी के तहत प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए गए थे और राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 जून, 2009 की अधिसूचना सं. 65/2009 - सीमा

3866 GI/2015 (1)

शुल्क के तहत अस्थायी पाटनरोधी शुल्क लगाए गए थे। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. 14/19/2008 - डी जी ए डी के तहत अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए गए थे, जिनमें चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पर निश्चात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम में की गई सिफारिशों के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना सं. 50/2010 - सीमा शुल्क के तहत चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए गए थे।

- 3. यतः , माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण (सी ई एस टी ए टी) के दिनांक 11 अगस्त, 2011 के आदेश सं. ए डी/31-51/2011 ए डी के तहत जारी आदेशों के अनुसरण में दिनांक 23 जनवरी, 2012 को निर्णयोपरांत सुनवाई की गई थी और इच्छुक पक्षकारों के अनुरोध की जांच करने के बाद प्राधिकारी ने केंद्र सरकार द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर दिनांक 10 अप्रैल, 2012 के आदेश सं. 14/19/2008 डी जी ए डी के तहत इस संबंध में जारी अधिसूचना की तारीख से संबद्ध वस्तुओं के सभी निर्यातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की पूर्व सिफारिश की पृष्टि की थी।
- 4. यत:, मैसर्स भारत फोर्ज लि., जो संबद्ध वस्तुओं का घरेलू निर्यातक है, ने अधिनियम और नियमों के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत प्रमाणित याचिका दाखिल की है , जिसमें चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने का आरोप लगाया गया था और चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों के जारी रहने अथवा उनमें वृद्धि करने के लिए एक निर्णायक समीक्षा जांच आरंभ करने का अन्रोध किया था।
- 5. घरेलू उद्योग की ओर से पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार दाखिल पुख्ता याचिका के आधार पर प्राधिकारी ने दिनांक 13 जून, 2014 की अधिसूचना सं. 15/11/2014 डी जी ए डी के तहत यह जांचने के लिए कि क्या इस शुल्क के समाप्त होने से घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, यह निर्णायक समीक्षा जांच आरंभ की है।
- 6. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की वैधता अविध को केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2014 की अधिसूचना सं. 30/2014-सीमा शुल्क (ए डी डी) के तहत दिनांक 14 जून, 2015 तक बढ़ा दिया गया था।
- 7. वर्तमान समीक्षा के कार्य क्षेत्र में संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पूर्व जांच के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने उक्त जांच को पूरा करने की समय सीमा को पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 के अनुसार 3 महीने अर्थात 12 सितंबर, 2015 तक बढ़ा दिया था।

ख. प्रक्रिया

- संबद्ध जांच के संबंध में नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है :
 - क) नियम 5 के उप नियम 5 के तहत प्राधिकारी ने पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा आरंभ करने के लिए याचिका प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।

- ख) संबद्ध देश के नई दिल्ली स्थित दूतावास को नियम 6 (2) के अनुसार जांच आरंभ करने के बारे में सूचित भी कर दिया गया था।
- ग) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग को अपने पास उपलब्ध सूचना के अनुसार जांच आरंभ करने के संबंध में दिनांक 13.6.2014 की अधिसूचना की प्रतियां भेजी। इस जांच के पक्षकारों से प्रश्नावली के उत्तर दाखिल करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचार प्रकट करने का अनुरोध किया गया था । निर्यातकों को भेजे गए प्रेषण पत्र, याचिका तथा प्रश्नावली की प्रतियां भी ज्ञात निर्यातकों/ उत्पादकों की एक सूची के साथ संबद्ध देश के दूतावास को भेजी गई थी, जिसमें संबद्ध देश से निर्यातकों/ उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर भेजने की सलाह देने का अनुरोध किया गया था।
- घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका के अगोपनीय अंश की प्रतियां उक्त नियमावली के नियम 6
 (3) के अनुसार संबद्ध देश के द्तावास और ज्ञात निर्यातकों को उपलब्ध कराई गई थी।
- ङ) संगत सूचना प्रकट करने के लिए नियम 6 (4) के अनुसार संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावलियां भेजी गई थीं :-
 - (i) मैसर्स ह्बेई ट्राई रिंग फोर्जिंग कं. लि.
 - (ii) मैसर्स ह्बेई ट्राई रिंग ऑटो एक्सल कं. लि.
 - (iii) मैसर्स ह्बेई ट्राई रिंग मोटर स्टीयरिंग कं. लि.
- च) चीन जन. गण. एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश होने के कारण, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के ज्ञात निर्यातकों को नियमावली के अनुबंध- । के पैरा 8 के उप- पैरा (3) में यथाउल्लिखित आवश्यक सूचना/ दस्तावेज प्रस्तुत करने के बारे में सूचित किया तािक प्राधिकारी इस पर विचार कर सके कि क्या ऐसे सहयोगी निर्यातक/ उत्पादक को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किया जाना चािहए जिससे वे यह प्रदर्शित कर सकेंगे कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की शर्तों के तहत संचािलत होते हैं।
- छ) संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने वाले निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने प्रश्नावली के उत्तर दाखिल किए हैं :-
 - (i) मैसर्स हुबेई ट्राई रिंग फोर्जिंग कं. लि.
 - (ii) मैसर्स ह्बेई ट्राई रिंग ऑटो एक्सल कं. लि.
- ज) नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना भेजने के लिए भारत में संबद्घ वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और उपभोक्तओं को प्रश्नाविलयां भेजी गई थीं :-
 - (i) अशोक लीलेंड लि.
 - (ii) महेन्द्रा ट्रक्स एंड बसेस लि.
 - (iii) वी ई कॉमर्शियल व्हीकल्स लि.
 - (iv) टाटा मोटर लि.
 - (v) ए एम डब्ल्यू मोटर्स लि.
- झ) केवल मैसर्स अशोक लीलेंड लि. ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर तथा कुछ विधिक याचिकाएं दाखिल की हैं।

- ज) वाणिन्यिक आसूचना और सांख्यकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) को जांच अविध सिंहत क्षिति अविधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के लेन देन - वार ब्यौरे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में डी जी सी आई एंड एस स्रोत द्वारा सूचित लेन देन - वार आयात के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- ट) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा एक सार्वजनिक फाइल के रूप में प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया, जो हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए खुले तौर पर उपलब्ध थी । सेनडिस्क मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसरण में और माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उक्त फैसले के खिलाफ प्राधिकारी द्वारा दाखिल अपील पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त लेन देन वार आंकड़े आयातकों के विवरणों को हटाने के बाद सार्वजनिक फाइलों में रखे गए हैं।
- ठ) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और सामान्यतः सहमत लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की अधिकतम लागत और खरीदने व बेचने की लागत निकाली गई थी तािक यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यून पाटनरोधी श्ल्क घरेलू उद्योग की क्षति को हटाने के लिए पर्याप्त होगा।
- ड) विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में उनके दावों के संबंध में गोपनीयता के दावों की जांच की गई । जो सूचना गोपनीय प्रकृति की है अथवा जो हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई है और साथ में उसका अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराया गया है, उसे गोपनीय माना गया है।
- ढ) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई करने के लिए दिनांक 5 मार्च, 2015 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की थी, जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधि और अन्य इच्छुक पक्षकार उपस्थित हुए थे। इच्छुक पक्षकारों से लिखित में अपना अनुरोध दाखिल करने और उस पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने को कहा गया था । इच्छुक पक्षकारों से प्राप्त हुए लिखित अनुरोध और उनके प्रत्युत्तरों पर उनकी संगतता के अनुसार और साक्ष्य के आधार पर जांच परिणामों में विचार किया गया है।
- ण) निर्दिष्ट प्राधिकारी के परिवर्तित हो जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 11 अगस्त, 2015 को एक अन्य जन सुनवाई आयोजित की गई जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को नए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया गया था और जन सुनवाई के परिणामस्वरूप पक्षकारों द्वारा जांच के लिए अपने लिखित अनुरोध देकर व्यक्त किए गए विचारों और उनके प्रत्युत्तरों को रिकार्ड में शामिल किया गया है और उनकी संगतता के अनुसार और साक्ष्य के आधार पर उन पर विचार किया गया है।
- त) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और संबद्ध देश में प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की आवश्यकता के अनुसार और उनकी व्यावहारिकता के आधार पर स्थल पर ही पुष्टि करके उनका सत्यापन किया।
- थ) उपरोक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार जांच परिणामों के लिए आवश्यक तथ्यों/ आधारों के बारे में ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक **28**.09.2015 को बता दिया गया था और उन पर प्राप्त हुई टिप्पणियों पर अंतिम जांच परिणामों में विचार गया है।

- द) दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की अविध (जांच की अविधि) के लिए जांच की गई थी। तथापि, क्षिति की जांच में 2010-11, 2012-13 और जांच की अविधि के दौरान की अविधि शामिल है।
- ध) *** इस प्रकटन में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना शामिल है और उन पर प्राधिकारी दवारा नियमों के तहत विचार किया गया है।
- न) प्राधिकारी ने जांच की अविध के लिए (अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 तक) औसत विनिमय दर 60.85 रुपए = 1 अमरीकी डॉलर माना है।

ग. विचाराधीन उत्पादों और समान वस्त्ओं का कार्य क्षेत्र

- 9. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद और इस समीक्षा जांच में जांच आरंभ करने संबंधी अधिसूचना में यथानिर्दिष्ट उत्पाद हैं, " मीडियम और हैवी कॉमर्शियल वाहनों में प्रयुक्त फ्रंट एक्सल बीम (एफ ए बी) और स्टीयरिंग नॅकॅल (एस के), चाहे फोर्ज हों या मशीनीकृत हों "।
- 10. फ्रंट एक्सल बीम एक सुरक्षा से जुड़ी नाजुक वस्तु होती है क्योंकि यह वाहन के भार को वहन करती है और साथ ही स्टीयरिंग को भी यथा स्थान रखती है। फ्रंट एक्सल बीम का कार्य वाहन के आगे के भार को वहन करना, उबड़ खाबड़ सड़कों पर समस्तर और शीर्ष स्तर के भार को संभालना तथा आरामदायक यात्रा के लिए स्प्रिंग के ज़िरए एक गद्दे की तरह काम करना होता है। स्टीयरिंग नॅकॅल एक बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है और वाहन के स्टीयरिंग को नियंत्रित करने के लिए बाजु के माध्यम से एक्सल बीम पर ठीक से लगा होता है।
- 11. "फ्रंट एक्सल बीम " और "स्टीयरिंग नॅकॅल " वाहनों के पुर्जों अथवा सहायक पुर्जों की श्रेणी में आते हैं और उप शीर्ष 8708.10.90 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 87 के तहत आते हैं। इन उत्पादों को कई अन्य सीमा शुल्क वर्गीकरणों के तहत भी आयात किया जा सकता है। अतः यहां दिया गया सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल दर्शाने के लिए है और यह जांच के कार्य क्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकर नहीं है।
- 12. "फ्रंट एक्सल बीम" (एफ ए बी) और "स्टीयरिंग नॅकॅल" (एस के) उत्पादों को पहले स्टील की बिलेट/ छड़ों से तैयार किया जाता है और उसके बाद उत्पादों को मशीन से इस तरह से तैयार किया जाता है तािक वे वाहनों में फिट हो सकें। तथािप, उत्पादों को फोर्ज और मशीनीकृत, दोनों रूपों में वाहन निर्माताओं को बेचा जाता है। यद्यपि मशीनीकृत उत्पादों को सीधे वाहनों में लगाने के लिए भेजा जाता है, जबिक यदि उत्पाद फोर्ज अवस्था में आपूर्ति किया जाता है तो उपभोक्ता/ वाहन निर्माताओं को फोर्ज उत्पाद को वाहन में लगाने से पूर्व मशीन से तैयार करना पड़ता है। फोर्ज और मशीनी प्रकार के उत्पाद के बीच केवल अतिरिक्त रूप से मशीनीकृत किए जाने का अंतर होता है जो फोर्ज उत्पाद के मामले में किया जाता है।
- 13. प्रतिवादी निर्यातक ने यह अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का चयन इस ढंग से किया जाए कि उनकी व्यावहारिक रूप से तुलना संभव हो। यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग के आंकड़ों के अनुसार फोर्ज किए गए एफ ए बी और फोर्ज किए गए स्टीयरिंग नॅकॅल का कोई आयात नहीं हुआ, इसलिए यह समझ से परे है कि किस आधार पर इसे विचाराधीन उत्पाद में शामिल किया गया और घरेलू उद्योग फोर्ज उत्पादों के आयातों के अभाव में किसी क्षति का सामना कैसे कर रहे हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि यदि घरेलू उद्योग वास्तव में मशीनीकृत फंट एक्सल बीम (एफ ए बी) और मशीनीकृत स्टीयरिंग नॅकॅल का उत्पादन कर रहा है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी को इसकी जांच करनी चाहिए। यदि घरेलू उद्योग मशीनीकृत संबद्ध उत्पाद का उत्पादन नहीं कर रहा है तो मशीनीकृत संबद्ध उत्पाद के आयातों के कारण क्षति होने का पूरे का पूरा दावा ही गलत हो जाता है और उसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए।

निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त तर्कों के आलोक में उत्पाद के सही होने की संभावना के संबंध में निर्णय कर सकता है ।

- 14. निर्यातकों और आयातकों ने प्रकटीकरण के उपरांत के अपने अनुरोधों में अपनी बात पुनः दोहराई है कि फोर्ज और मशीनीकृत उत्पादों को तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरेके विकल्प के तौर पर नहीं माना जा सकता और इसीलिए वे समान उत्पाद नहीं हैं । इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया है कि उत्पादों को उपयोक्ताओं की जरुरतों के अनुसार तैयार किया जाता है और घरेलू उद्योग तथा आयातों से अलग अलग ग्राहकों की पूर्ति होती है ।
- 15. याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि उपभोक्ताओं/ ऑटोमोबाइल निर्माताओं द्वारा दिए गए विनिर्देशनों के आधार पर प्रत्येक उत्पादक द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पादों और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई खास फर्क नहीं होता। अतः घरेलू उद्योग का यह दावा है कि विचाराधीन आयातित उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएं नियमानुसार अर्थ के अनुसार "समान वस्तु" हैं। यह दावा किया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम में वही निष्कर्ष निकाला है और वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के कारण विचाराधीन उत्पादों का क्षेत्र वही होना चाहिए जो मूल जांच में है।
- प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि यद्यपि जांच की अवधि के दौरान केवल मशीनीकृत उत्पादों का ही **16**. आयात किया गया है लेकिन घरेलू उद्योग, फोर्ज और मशीनीकृत दोनों प्रकार के 'फ्रंट एक्सल बीम' और स्टीयरिंग नॅकॅल का उत्पादन और आपूर्ति करता है। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि संबद्ध वस्त्एं पहले फोर्ज की जाती हैं और उसके बाद मीडियम और हैवी कॉमर्शियल वाहनों में प्रयोग में लाए जाने से पूर्व उन्हें मशीन में तैयार किया जाता है । कुछ उपभोक्ता/ ओ ई एम फोर्ज वस्त्ओं की खरीद करते हैं और उनको स्वयं मशीन द्वारा परिष्कृत करते हैं अथवा मशीनीकृत उत्पाद की खरीद करते हैं और सीधे ही ऑटोमोबाइल में लगा देते हैं। अतः फोर्ज उत्पाद म्ख्यतः परिष्कृत मशीनी उत्पादों से तत्काल पूर्व की अवस्था होती है और फोर्ज तथा मशीनीकृत , दोनों वस्तुओं को तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से परस्पर बदला जा सकता है । यह सच्चाई है कि उत्पादों को ऐसे वाहनों के मॉडल के अनुसार निर्मित किया जाता है जिनमें इन्हें लगाया जाना हो । उपयोगकर्ता उदयोग तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से विचार करते हुए फोर्ज अथवा मशीनीकृत उत्पादों को घरेलू उत्पादकों से खरीदते हैं या उनका आयात करते हैं । अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वस्तुएं चाहे फोर्ज रुप में हैं या मशीनीकृत रुप में , वे घरेलू तौर पर उत्पादित वस्तुओं का बाजार में स्थान लेगी । पूर्व जांचों में घरेलू रुप से तैयार और आयातित वस्तुओं को परस्पर समान वस्तुएं माना गया था । अतः प्राधिकारी का यह मानना है कि घरेलू उदयोग दवारा निर्मित किए गए और आपूर्ति किए गए तथा संबद्ध देश से आयात किए गए फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयरिंग नॅकॅल इस निर्णायक समीक्षा जांच के प्रयोजन से समान वस्तुएं हैं ।
- 17. उत्पादकों द्वारा फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयरिंग नॅकॅल की आपूर्ति की जाती है और ऑटोमोबाइलों में उनकी खपत संख्या में होती है। तथापि, विभिन्न प्रकार के फ्रंट एक्सल बीम तथा स्टीयरिंग नॅकॅल का भार ऑटोमोबाइलों के प्रकार और डिजाइन के विनिर्देशनों के आधार पर अलग अलग होता है और इसीलिए प्रति नग/ इकाई उनकी लागत काफी हद तक अलग अलग होती है, यद्यपि भार के अनुसार प्रति इकाई लागत अधिक हो सकती है या कम हो सकती है । अतः प्राधिकारी ने पूर्व जांच में भार को विभिन्न निर्धारणों और उचित तुलना के प्रयोजन से मापन की उपयुक्त सामान्य इकाई माना है। इस जांच में भी वही तरीका अपनाया गया है।

घ. घरेलू उदयोग और उसका आधार

- 18. यह याचिका भारत फोर्ज लि., पुणे द्वारा दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता भारत में संबद्घ वस्तुओं का एक प्रमुख निर्माता है और अनेक देशों को वस्तुओं की आपूर्ति करता है। याचिकाकर्ता के अलावा, टाटा मोटर्स और एमटेक इंडिया भी फ्रंट एक्सल बीम का उत्पादन करते हैं। स्टीयरिंग नॅकॅल के मामले में अन्य भारतीय उत्पादकों में महेन्द्रा सी आई ई ऑटोमोटिव लि., एमटेक इंडिया तथा हेपी फोर्जिंग शामिल हैं।
- 19. प्रतिवादी निर्यातकों और आयातकों ने अपने अनुरोध में यह तर्क दिया है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 के साथ पठित नियम 23 (3) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी को 'घरेलू उद्योग' की क्षिति का निर्धारण करना होता है। इस निर्धारण के लिए पूर्व अपेक्षा यह है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत यथानिर्धारित घरेलू उद्योग मौजूद होना चाहिए। किसी भी निर्णायक समीक्षा में इस पूर्व अपेक्षा की पूर्ति आवश्यक है। अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग के आधार की जांच कर सकता है।
- 20. इसके अलावा, प्रतिवादी निर्यातक ने यह तर्क दिया है कि कैप्टिव उत्पादों के उत्पादन को कुल भारतीय उत्पादन से अलग नहीं माना जा सकता । कैप्टिव उत्पादक पाटनपरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के प्रयोजन से घरेलू उत्पादक भी है और इसमें महत्वपूर्ण बात संबंधित उत्पाद का उत्पादन है न कि यह बात कि एक उत्पादक अपने उत्पादन का क्या करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उत्पादक अपने उत्पादन का उपयोग अपने लिए करता है या नहीं। इस संबंध में निर्यातकों ने विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय का ध्यान संयुक्त राज्य कॉटन यार्न मामले में दी गई व्यवस्था की ओर आकर्षित किया है जिसमें कि यह पाया गया है कि उत्पादकों को घरेलू उपयोग की परिभाषा से बाहर केवल इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वे अपने उत्पादन को घरेलू बाजार के लिए ही बेचना नहीं चाहते बल्कि उसका उपयोग अपनी आंतरिक खपत के लिए भी करते हैं।
- 21. इसके अलावा, निर्यातकों द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन संबद्घ उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन का बड़ा हिस्सा नहीं होता और इसीलिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के प्रयोजन से कुल भारतीय उत्पादन में बड़ा हिस्सा नहीं माना जा सकता । प्रतिवादी निर्यातकों ने प्रकटीकरण के उपरांत के अपने अन्रोधों में अपनी स्थिति को प्नः दोहराया है ।
- 22. प्राधिकारी ने यह उल्लेख किया है कि यह एक निर्णायक समीक्षा है और नियमों के अनुसार 'घरेलू उद्योग' के संबंध में क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का निर्धारण करने की जरुरत है। इसलिए उपर्युक्त तर्कों के आलोक में प्राधिकारी के समक्ष घरेलू उत्पादक के हिस्से की जांच की गई है।
- 23. याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादक भारत में संबद्घ वस्तुओं का एक प्रमुख उत्पादक है। टाटा मोटर्स भी संबद्घ वस्तुओं का एक प्रमुख उत्पादक है लेकिन समग्र उत्पादन की केवल अपने ऑटोमोबाइल के लिए ही खपत करता है। टाटा मोटर्स द्वारा तैयार संबद्घ वस्तुएं देश के वाणिज्य में शामिल नहीं होती और इसीलिए किथत पाटित आयातों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । अतः इस उत्पादक के संबंध में क्षिति का निर्धारण करने का कोई अर्थ नहीं निकलता । तथापि, इस पर विचार किए बिना चाहे टाटा मोटर्स की अपनी खपत को भी शामिल करे तो याचिकाकर्ता कंपनी के उत्पादन का कुल घरेलू उत्पादन में हिस्सा 'फंट एक्सल बीम' के लिए 75 प्रतिशत से अधिक और स्टीयिरेंग नॅकॅल के लिए 40 प्रतिशत से अधिक है। भारत में संबद्घ वस्तुओं का अन्य कोई घरेलू उत्पादक कैप्टिव या किसी अन्य प्रकार का उत्पादक नहीं है । अतः याचिकाकर्ता स्पष्ट तौर पर समीक्षा याचिका के लिए किसी अन्य विरोधी घरेलू उत्पादक की मौजूदगी के बिना घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा रखता है। तदनुसार, क्षिति की जांच के प्रयोजन से और क्षित के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के प्रयोजन से याचिकाकर्ता, अर्थात मैसर्स भारत फोर्ज लि. को नियम 2 (ख) के प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग पाया गया है।

ङ. जांच के लिए इच्छ्क पक्षकार

- 24. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर और बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार की प्रश्नावली का उत्तर चीन से निम्नलिखित दो उत्पादकों दवारा प्रस्तुत किया गया है :-
 - (i) मैसर्स ह्बेई ट्राई रिंग फोर्जिंग कं. लि.
 - (ii) मैसर्स ह्बेई ट्राई रिंग ऑटो एक्सल कं. लि.
- 25. अशोक लीलेंड ने आयातक की प्रश्नावली और कुछेक विधिक अनुरोध दाखिल किए हैं। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता, दो चीन के उत्पादकों व निर्यातकों और अशोक लीलेंड पर वर्तमान जांच में भाग लेने के लिए इच्छुक पक्षकार के रूप में विचार किया है।

च. इच्छ्क पक्षकारों द्वारा उठाये गए विविध मामले

26. इस जांच के इच्छुक पक्षकारों ने इस जांच के लिए प्रक्रिया और वास्तविक निर्धारण के संबंध में कई सामान्य प्रश्न उठाए हैं। संक्षेप में सामान्य मामलों का नीचे सारांश दिया गया है और उनकी संगतता के अनुसार जांच की गई है।

च. 1 निर्यातकों और आयातकों (अन्य इच्छ्क पक्षकारों) के विचार

- 27. निर्यातकों और आयातकों (अन्य इच्छुक पक्षकारों) तथा घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच, पाटन निर्धारण की कार्यप्रणाली तथा घरेलू उद्योग के क्षिति दावों के संबंध में कई मामले उठाए हैं। यद्यपि पाटन और क्षिति के निर्धारण से संबंधित मामले इस प्रकटीकरण में उपयुक्त स्थानों पर निपटाए गए हैं लेकिन जांच के लिए पक्षकारों द्वारा उठाए गए सामान्य मामलों की यहां जांच की गई है। संक्षेप में पक्षकारों के अनुरोध और उनमें उठाए गए मामलों का सारांश नीचे दिया गया है।
- 28. इस मामले में प्रतिवादी निर्यातक और आयातक के प्रतिनिधि, मैसर्स लक्ष्मीकुमारन एवं श्रीधरन ने *अन्य* बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विधिक और अन्य मामले उठाए हैं :
 - क) वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क को , जिसकी अविध 14.06.2014 को समाप्त हुई थी, पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के 40 दिनों के बाद दिनांक 23 जुलाई, 2014 की अधिसूचना सं. 30/2014 सीमा शुल्क (ए डी डी) द्वारा पुन: शुरू नहीं किया जा सका। यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान अधिसूचना में कोई बचाव की क्लाज नहीं है। अधिसूचना में किसी प्रावधान के कारण स्वत: ही शुल्क की अविध नहीं बढ़ी। यह भी तर्क दिया गया है कि कुम्हो पैट्रो कैमिकल्स कं. लि. बनाम भारत संघ, 2014 (306) ई एल टी 3 (दिल्ली) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट तौर पर, किसी निर्णायक समीक्षा के लंबित रहते पाटनरोधी शुल्क को विस्तार प्रदान करने के संबंध में उक्त कानूनी सिद्धांत की पुष्टि करता है। अत: अधिसूचना समय समाप्त होने पर समाप्त हो गई। यह जांच केवल तभी संभव है जब कोई पाटनरोधी शुल्क लागू हो, जिसके समाप्त होने से इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना हो। तथापि, जहां कोई पाटनरोधी शुल्क मौजूद नहीं है, वहां पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना की कोई जांच नहीं हो सकती।
 - ख) इच्छुक पक्षकारों ने प्रकटीकरण के उपरांत के अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि यद्यपि माननीय दिल्ली उच्चच न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था पर रोक लगाई गई है लेकिन बाबू वर्गिस एवं अन्य बनाम बार काउंसिल ऑफ केरल एवं अन्य मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था से उत्पन्न कानून का सिद्धांत अभी भी लागू है । इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर यह व्यवस्था दी थी कि यदि कोई विनिर्दिष्ट समय अविध

का विस्तार किया जाना हो तो मूल समय अविध के समाप्त होने से पूर्व समय विस्तार के लिए आदेश पारित किया जाना चाहिए ताकि निरंतरता बनी रहे । यह तर्क दिया गया है कि इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी थी कि विनिर्दिष्ट समय अविध के समाप्त हो जाने के बाद कोई भी ऐसा न्यायाधिकार , जो पहले निहित था, वह समाप्त हो जाएगा और इसीलिए यह विस्तार नियम के विरुद्ध है। यह विधिक सिद्धांत वर्तमान मामले समान रुप से लागू है क्योंकि वित्त मंत्रालय ने दिनांक 14 जून, 2014 को मूल अिधसूचना समाप्त हो जाने के बाद पाटन रोधी शुल्क में विस्तार करने की अपनी शक्तियां खो दी थी ।

- ग) याचिका के साथ प्रमाण नहीं है क्योंकि याचिका के सामान्य मूल्यों और निर्यात कीमतों के संबंध में कोई साक्ष्य शामिल नहीं है। कानून की अपेक्षा के लिए याचिकाकर्ता ने केवल यह कहा है कि उसे एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमतों अथवा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमतों अथवा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कोई कीमत संबंधी ब्यौरा नहीं मिल सका। किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित सामान्य कीमत बताए बिना याचिका बिलकुल अधूरी है।
- घ) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने याचिका के साथ प्रस्तुत साक्ष्य की पर्याप्तता की जांच न करके और सामान्य कीमत तैयार करने के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे को स्वीकार करके विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) ए डी ए के अन्च्छेद 5.3 का उल्लंघन करने का कार्य किया है।
- इ) प्रतिभागी निर्यातकों के खपत संबंधी मानदंडों पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए वर्तमान जांच में विचार किया जाए।
- च) याचिकाकर्ता ने पाटन और क्षिति की पुनरावृत्ति होने की संभावना के दावे के लिए पाटन अथवा उसे होने वाली क्षिति के जारी रहने का उल्लेख करने के लिए जांच की अविध के बाद के कोई भी आंकड़े उपलबध नहीं कराए हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच की अविध के बाद की सूचना दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं को निर्देश दे सकता है और निर्दिष्ट प्राधिकारी क्षिति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में विश्लेषण करते समय उसकी जांच करे।
- छ) याचिकाकर्ता द्वारा निर्यात कीमतों के अनुमान के लिए विभिन्न कटौतियों/ समायोजनों के संबंध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
- ज) याचिकाकर्ता ने याचिका में यह कहा है कि संबद्ध उत्पादों का आयात संख्याओं में होता है लेकिन उन्हें भार में परिवर्तित किया गया है। तथापि, याचिकाकर्ता द्वारा आयात के आंकड़ों की छंटनी करने और संबद्ध उत्पादों को संख्या से भार में परिवर्तित करने के लिए अपनाई गई पद्धित के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
- झ) यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस जांच में आयात संबंधी आंकड़ों के अन्य स्रोतों पर भरोसा करता है तो ऐसे स्रोतों से अध्रे और तैयार आयात आंकड़े भी सार्वजनिक फाइल में रखे जाने चाहिए और उन्हें समुचित जांच और टिप्पणियों के लिए एम एस एक्सल फार्मेट में इच्छुक पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इस संबंध में इन पक्षकारों ने स्केनिडिस्क इंटरनेशनल लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्यों के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के हाल ही के फैसले की ओर प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित किया है।
- ज) याचिकाकर्ता ने उसके द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की सूचना का कोई सार्थक सारांश उपलब्ध नहीं कराया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराने में भी

असफल रहा कि गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना का सारांश क्यों नहीं दिया जा सकता। इससे प्रतिवादी क्षति संबंधी पहल्ओं पर सार्थक टिप्पणियां प्रदान नहीं कर पाया।

- ट) फार्मेट- क और फार्मेट- ग1 में सूचना आसानी से सूचीबद्ध रूप में उपलब्ध कराई जा सकती है तािक जांच की अविध और पिछले वर्षों की प्रवृत्ति का उल्लेख हो सके। प्रोफार्मा IV क में कुछेक मानदंड यथा निवेश, निवल मूल्य तथा विस्तार के लिए पूंजी निवेश, बिक्री मूल्य तथा निर्यातों के लिए बिक्रियों की लागत को गोपनीय रखा गया है और ऐसे मानदंडों के लिए कोई भी सूचीबद्ध आंकड़े प्रदान नहीं किए गए हैं।
- ठ) याचिका में गैर- क्षति कीमत अथवा कीमत कम करने के विश्लेषण के संबंध में कोई भी सूचना प्रदान नहीं की गई है। यह बिलकुल संभव है कि याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के तहत प्रदत्त सिद्धांतों के आधार पर गैर क्षति मूल्य निर्धारित नहीं किया है।

च. 2 घरेलू उद्योग के विचार

- 29. घरेलू उद्योग ने अपने विभिन्न अनुरोधों में इच्छुक पक्षकारों के तर्कों का खंडन किया है। घरेलू उद्योग के अनुरोधों का सारांश इस प्रकार से है :-
 - क) इच्छुक पक्षकारों का यह कहना है कि याचिका में अपर्याप्त प्रकटीकरण अथवा प्रतिनिधि देश के रूप में विचार करना अथवा याचिका में अपर्याप्त साक्ष्य/ सूचना होना आदि प्राथमिक मामले हैं और जांच आंरभ करने की अधिसूचना का उत्तर देते समय इन्हें उठाया जाना चाहिए। इन मामलों को पहली बार उठाने के लिए सुनवाई के बाद लिखित अनुरोध के अवसर का उपयोग नहीं किया जाए । इन मामलों को मौखिक सुनवाई के दौरान नहीं उठाया गया था। यह प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई लिखित अनुरोध की छूट का स्पष्ट दुरुपयोग है। अतः प्राधिकारी को इन सभी अनुरोधों को अस्वीकार करना चाहिए। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी का ध्यान यू एस होट रोल्ड स्टील मामले में डब्ल्यू टी ओ पैनल के निर्णय की ओर आकर्षित किया है जिसमें पैनल ने यह पाया था कि अनुच्छेद 6.1 और 6.2 द्वारा प्रदत्त क्रमशः 'विस्तृत' और 'पूर्ण' अवसरों को अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता और एक समय इनकी मौजूदगी समाप्त हो जानी चाहिए। इस बात का निर्धारण जांच प्राधिकारियों के द्वारा उनकी जांच और समीक्षा करने के लिए भरोसा करने के अधिकार का उल्लेख करके किया जाए।
 - ख) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले के दिए गए इस निर्णय को, कि वर्तमान शुल्क की समाप्ति के बाद शुल्कों को बढ़ाया नहीं जा सकता, माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और उस पर रोक लगाई गई है।
 - ग) निर्णायक समीक्षा करने के लिए साक्ष्य पर आधारित अनुरोध के आधार पर जांच की गई थी। कानून में निश्चय ही घरेलू उद्योग को इतनी विस्तृत सूचना देने की जरूरत नहीं है, जो आवेदन की अवस्था में या आंरभ में अंतिम निर्धारण के लिए अपेक्षित होती है। पाटन, क्षित और अस्थायी संबंध होने के केवल प्रथम दृष्टया साक्ष्य के लिए जांच अथवा समीक्षा की जरूरत होती है। निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास आरंभन अवस्था में निर्धारण के लिए यथा अपेक्षित समस्त सूचना का रिकार्ड रखने की जरूरत नहीं। यह भी तर्क दिया गया है कि कुछेक क्षेत्राधिकारों में प्राधिकारी स्वयं जांच आरंभ करते हैं। ऐसे मामलों में तर्कों का कोई आधार नहीं होता।
 - घ) निर्यातक और आयातक, दोनों ने ही प्राधिकारी को उत्तर भेजा है। निर्यातक अथवा आयातक का यह तर्क नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा सूचित आयातों की मात्रा और मूल्य को बढ़ा - चढ़ाकर बताया गया है। वास्तव में तथ्यात्मक स्थिति शायद यह होगी कि इनमें कटौती की जाए क्योंकि

सामान्य तौर पर यह पाया गया है कि भारतीय आंकड़ों में सूचित आयातों से संबंधित मात्रा में कभी- कभी क्छ आयातों के लेन देन शामिल नहीं होते।

- ड) जहां तक इस दलील का संबंध है कि याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता द्वारा अपनाए गए भार को विनिर्दिष्ट नहीं किया है, याचिका के साथ संलग्न आयात संबंधी आंकड़ों में संख्या और भार, दोनों के संबंध में स्पष्ट सूचना निहित है।
- च) याचिकाकर्ता ने केवल उसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है, जिसकी गोपनीयता कानून के अनुसार संरक्षित की गई है।
- छ) निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी इच्छुक पक्षकारों को आयात की तारीख, आयात के विवरण, आयात की मात्रा, आयात के मूल्य तथा पोर्ट के संबंध में वास्तविक आधार पर आयात संबंधी सूचना प्रकट करने के लिए निर्यातक और आयातक को निर्देश देना चाहिए। इसके अलावा, कोई भी पक्षकार सूचना का अधिकार के तहत डी जी सी आई एंड एस से सूचना की मांग कर सकता है। घरेलू उद्योग भी निर्दिष्ट प्राधिकारी की सहमति प्राप्त करके डी जी सी आई एंड एस से उपरोक्त सूचना की मांग कर सकता है। ऐसे मामलों में इस सूचना का गोपनीय सूचना के रूप में दावा करने का कोई आधार नहीं है।
- ज) इस दलील के संबंध में कि खंड VI में लागत संबंधी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है, याचिकाकर्ता का यह कहना है कि निर्यातक ने भी इन सभी सूचनाओं के गोपनीय होने का दावा किया है।
- झ) जहां तक निवेश और निवल मूल्य का संबंध है, याचिकाकर्ता ने उसमें लगी पूंजी और उस पूंजी पर प्रतिफल के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है। कानून के तहत विनिर्दिष्ट मानदंड पूंजी पर प्रतिफल के संबंध में है और वह सूचना याचिकाकर्ता के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जहां तक बिक्री मूल्य का संबंध है, प्राधिकारी द्वारा इन्हें क्षिति मानदंडों की तरह नहीं माना गया है। जहां तक निर्यातों के लिए बिक्री की लागत का संबंध है यह क्षिति आकलन के लिए पूर्णतया असंगत है। जहां तक विस्तार के लिए लगी पूंजी का संबंध है, याचिकाकर्ता ने इस संबंध में बताया है।
- आवेदन फार्म में याचिकाकर्ता को गैर- क्षित मूल्य और कटौती किए गए मूल्य के संबंध में सूचना उपलब्ध करानी होती है। आवेदन फार्म में याचिकाकर्ता को केवल लागत संबंधी सूचना उपलब्ध करानी होती है। वास्तव में प्राधिकारी द्वारा गैर क्षित मूल्य का निर्धारण उसी तरह से करना होता है न कि घरेलू उद्योग द्वारा क्योंकि निर्यातक प्रश्नावली में निर्यातकों को पाटन मार्जिन का निर्धारण करने की जरूरत नहीं होती। यहां तक कि यदि याचिकाकर्ता ने चाहे याचिका में क्षित मार्जिन का निर्धारण किया हो तो भी घरेलू उद्योग पर यह दायित्व नहीं पड़ता कि वह कार्यवाही की हर अवस्था में उसका निर्धारण करे।
- ट) जहां तक शुरुआत में साक्ष्य के स्तर का संबंध है, कई क्षेत्राधिकारों में निर्णायक समीक्षा संबंधित प्राधिकारी द्वारा बिना किसी उचित याचिका के स्वतः आरंभ कर दी जाती है और ऐसी जांच आरंभ करने के लिए व्यापक प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता। अतः इच्छुक पक्षकारों के तर्क व्यर्थ और बिना आधारहीन के होते हैं।

च. 3 प्राधिकारी के विचार

30. इच्छुक पक्षकारों द्वारा उठाये गए विभिन्न विविध मामलों की जांच की गई और इस प्रकार से उनका समाधान किया गया :

- क) इच्छुक पक्षकारों की यह दलील है कि पाटनरोधी शुल्क वित्त मंत्रालय द्वारा मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के बाद जारी नहीं रखा जा सकता। प्राधिकारी ने इस संबंध में यह नोट किया है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और माननीय न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के प्रचालन पर आंतरिक रोक लगा दी थी। वर्तमान मामले में शुल्क समाप्त होने से पूर्व जांच शुरू की गई थी। ऐसी ही स्थिति में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने जांच शुरू करने और निर्णायक समीक्षा जांच जारी रखने पर रोक लगाई है। जहां तक बाबू वर्गिस मामले में निर्णय के अनुपात का संबंध है, जैसा कि इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण के उपरांत के अपने विवरणों में उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है और इस मामले को इच्छुक पक्षकारों द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उठाना चाहिए।
- ख) इस दलील के संबंध में कि याचिका की विधिवत पुष्टि नहीं हुई थी और उसमें बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में सामान्य मूल्य के साक्ष्य शामिल नहीं किए गए थे, प्राधिकारी ने नोट किया है कि याचिका में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य था, जिसमें विचाराधीन उत्पाद के निरंतर पाटन होने और निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ करने को न्यायोचित ठहराने के लिए पाटन और क्षित के जारी रहने की संभावना दर्शाई गई हो।
- ग) आयात संबंधी आंकड़ों और आयात के आंकड़ों की छटनी के लिए प्रयुक्त कार्य प्रणाली के संबंध में प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि चीन से उत्पादक/ निर्यातक और भारत में आयातक वर्तमान जांच में भाग ले रहे हैं। अधिकांश आयात का लेन देन चीन के उत्पादक/ निर्यातक तथा भारतीय आयातक द्वारा किए गए निर्यातों से संबंधित है। याचिका में संलग्न आयात संबंधी आंकड़ों में उल्लिखित विवरण से इन पक्षकारों को आयातों की मात्रा और कीमत के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने में सहायता मिलनी चाहिए थी। तथापि, प्राधिकारी ने संबद्ध देश में प्रतिवादी उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा सूचित आयातों की वास्तविक मात्रा और कीमत की जांच के लिए उल्लेख किया है। प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील लंबित रहने के बावजूद प्रयुक्त लेन देन वार आयात संबंधी आंकड़ों को सार्वजनिक फोल्डर में भी रखा गया है, जिससे प्राधिकारी को आयातों की मात्रा और कीमत पर टिप्पणी करने का पर्याप्त अवसर मिला है।
- घ) जहां तक इस दलील का संबंध है कि याचिका में भार के आधार पर आयातों को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त परिवर्तन फैक्टर नहीं दिया गया है, यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आयात के आंकड़ों में संख्याएं और भार, दोनों को दर्शाया गया है और इसीलिए इच्छुक पक्षकारों के लिए याचिकाकर्ता द्वारा अपनाए गए परिवर्तन फैक्टर को जानना और उस पर टिप्पणी करना संभव था। जो भी हो, सहयोगी निर्यातकों द्वारा यथा सूचित उत्पादों के यूनिट भार को ऐसे परिवर्तन के लिए उपयोग में लाया गया है।
- इ) सूचना की गोपनीयता के संबंध में दोनों प्रतिवादी पक्षकारों के अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के दावों को इस संबंध में कानूनी प्रावधानों पर विचार करके और गोपनीयता का दावा करने वाले पक्षकारों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण तथा इस संबंध में प्राधिकारी की पूर्व कार्रवाइयों को ध्यान में रखकर स्वीकार किया गया है। जो सूचना गोपनीय प्रकृति की हैं अथवा जिनके प्रकटीकरण से सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों के हितों पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ता है, उसे गोपनीय माना गया है।

- च) जहां तक याचिका में एन आई पी आंकड़ों के न होने का संबंध है, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा एन आई पी का दावा घरेलू उद्योग की गोपनीय कारोबारी सूचना है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा प्रकट नहीं किया जाना चाहिए था। अंतिम एन आई पी का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा नियमावली में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किया गया है, यद्यपि घरेलू उद्योग को इस संबंध में दावा करने की छूट है।
- छ) जहां तक शामिल पूंजी पर ऐतिहासिक प्रतिफल का संबंध है, प्राधिकारी ने यह उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा पूंजी पर अर्जित ऐतिहासिक प्रतिफल जांच की अविध में घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित वास्तविक प्रतिफल और प्राधिकारी द्वारा अनुमत पूंजी पर तर्कसंगत प्रतिफल से वास्तव में काफी अधिक है। घरेलू उद्योग और प्रतिवादी पक्षकारों, दोनों ने ही शामिल पूंजी पर विगत प्रतिफल को अपनाने का दावा किया है। तथापि, प्राधिकारी ने अपनी संगत प्रक्रिया के अनुसार, लगाई गई पूंजी पर 22 प्रतिशत प्रतिफल अपनाया है।
- ज) इस दलील के संबंध में कि याचिका में सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के लिए व्यर्थ के आधार दिए गए है, प्राधिकारी ने यह उल्लेख किया है कि चूंकि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है, पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। याचिका में निर्णायक समीक्षा आरंभ किए जाने को न्यायोचित ठहराने के लिए पाटन और क्षति के जारी रहने के संबंध में पर्याप्त सूचना उपलब्ध है। आंकड़ों की गुणवता और निर्धारण के स्तर में जांच की प्रगति के साथ सुधार आया है।
- झ) याचिका में दावा किए गए विभिन्न मूल्य संबंधी समायोजनों के संबंध में, प्राधिकारी ने उल्लेख किया है कि यहां तक कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई प्रारंभिक सूचना में अनुमानित मूल्य शामिल थे लेकिन अब इन व्ययों पर चीन के उत्पादक/ निर्यातक द्वारा दाखिल किए गए प्रश्नावली उत्तर के आधार पर विचार किया गया है। इस संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि याचिका में प्राधिकारी को यह निर्धारित करने के लिए केवल प्रथम दृष्ट्या सूचना और साक्ष्य निहित है कि क्या जांच प्रारंभ करने के लिए कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण है। जांच के दौरान इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई तथ्यात्मक सूचना के आधार पर अंतिम निर्धारण किया गया है।
- 31. जांच के लिए पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य सभी मुद्दों को उनकी संगतता के अनुसार इस जांच परिणाम में संबंधित खंडों में शामिल किया गया है।

छ. वर्तमान पाटन के निर्धारण की प्रणाली

छ.1 कानूनी स्थिति

32. सीमा श्ल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (5) में निम्नलिखित प्रावधान है कि :

"इस धारा के अंतर्गत लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जब तक उसे पहले ही समाप्त न किया जाए, इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा ;

बशर्ते यदि किसी समीक्षा में केंद्र सरकार का यह मत हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षिति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह इस प्रकार से लगाए गए शुल्क की अवधि को समय समय पर आगे और 5 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और आगे की ऐसी अवधि इस प्रकार के समय विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी। बशर्ते यह भी कि पांच वर्षों की पूर्ववर्ती अवधि की समाप्ति से पूर्व शुरू की गई किसी समीक्षा का निष्कर्ष ऐसी समाप्ति से पूर्व नहीं निकलता है तो ऐसी समीक्षा का परिणाम लंबित रहने तक पाटनरोधी शुल्क एक वर्ष से अनिधिक अवधि के लिए लागू रहेगा ।"

- 33. तदन्सार, एक निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी को यह जांच करनी होती है कि:
 - क्या पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद पाटन जारी रहा है और यदि हां तो क्या इसके जारी रहने की संभावना है ;
 - ऐसे मामलों में, जहां पाटन जारी नहीं रहा, तो क्या पाटन रोधी शुल्कों का निरसन होने की स्थिति में इसके प्न: होने की संभावना है ;
 - क्या घरेलू उद्योग निरंतर भारी क्षिति का सामना करता रहा और यिद हां तो क्या यिद शुल्कों को हटा दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षिति जारी रहने की संभावना है;
 - ऐसे मामलों में, जहां घरेलू उद्योग को निरंतर क्षिति का सामना नहीं करना पड़ा, तो पाटनरोधी श्ल्कों के निरसन की स्थिति में क्या घरेलू उद्योग को प्नः क्षिति होने की संभावना है।
- 34. अतः प्राधिकारी ने पहले यह जांचने की कार्यवाही आरंभ की है कि क्या संबद्ध वस्तुओं का पाटन संबद्ध देशों से जारी रहा है और क्या घरेलू उद्योग को यह जांचने से पूर्व ऐसे पाटित आयातों के कारण महत्वपूर्ण क्षति जारी रही कि क्या शुल्कों का निरसन किए जाने पर पाटन के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है और ऐसी स्थिति में क्षति के जारी रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

छ. 2 पाटन के जारी रहने की जांच : सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण

35. प्राधिकारी ने यह उल्लेख किया है कि चीन से दो उत्पादक निर्यातकों ने अपने प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत किए हैं और बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा किया है। पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में निर्यातकों के विचार नीचे सारांश में दिए गए हैं :-

छ. 2.1 निर्यातकों और आयातकों/ अन्य इच्छुक पक्षकारों के विचार

- 36. प्रतिवादी निर्यातकों और आयातकों ने प्रकटीकरण के उपरांत के अनुरोधों सिहत अपने अनुरोधों में पाटन के दावों और चीन में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित और प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रणाली का उल्लेख किया है और उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिए हैं :-
 - (क) कि यद्यपि निर्यातकों ने मूल जांच में उनके बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जें का उल्लेख किया है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि प्रतिवादी निर्यातकों को दो आधारों पर प्रतिवादी निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया जाए, अर्थात हुबेई ग्रुप में महत्वपूर्ण राज्य अंशधारिता है और इसीलिए सरकार के हस्तक्षेप को नकारा नहीं जा सकता ; और चीन जन. गण. में स्टील की कीमतें बाजार की कीमतों को नहीं दर्शाती। यह तर्क दिया गया है कि मात्र सरकार की अंशधारिता होने से स्वयं ही यह अर्थ नहीं निकलता कि सरकार कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। विश्व व्यापार संगठन अपीलीय निकाय ने यूनाइटेड स्टेट- डेफिनिटिव एंटी डंपिंग एंड काउंटरवेलिंग इयूटीज ऑन सर्टेन होट रोल्ड प्रॉडक्ट्स फ्राम चाइना, डी एस 379/एबी/आर दिनांक 11.03.2011 के मामले में यह पाया है कि चीन सरकार की किसी उद्यम में मात्र अंशधारिता होने से स्वयं यह सिद्ध नहीं होता कि उद्योग में सरकार का नियंत्रण मौजूद है।

- (ख) कानून में 'राज्य का हस्तक्षेप' वाक्यांश की व्याख्या विनियामक के रूप में सरकार के हस्तक्षेप से होनी चाहिए। चीन सरकार निर्यातक कंपनियों में शेयर होल्डिंग में एक निवेशक के रूप में काम करती है न कि विनियामक के रूप में। यह तथ्य कि चीन सरकार ने निदेशकों को निवेश के रूप में नियुक्त किया है न कि विनियामक के रूप में, जो यह दर्शाता है कि निवेशकों की नियुक्ति में कोई कानूनी हस्तक्षेप नहीं हुआ।
- (ग) चीन जन. गण. में स्टील की कीमत बाजार मूल्य को दर्शाती है। वास्तव में, पूर्व जांचों में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन. गण. में स्टील की कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के समान माना है और चीन के ऐसे उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान किया है, जो स्टील को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं।
- (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने शेनयांग मत्सुशिता एस. बैटरी कं. लि. बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लि. एवं अन्य (2005) मामले में यह पुष्टि की थी कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-। के पैरा-7 में दिए गए अंतिम विकल्प का उस समय सहारा ले सकता है जब पहले दो तरीके समाप्त हो चुके हों। अतः विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए इस मामले में गैर बाजार अर्थव्यवथा वाले देशों जैसे चीन से निर्यातों के मामलों में सामान्य मूल्य का आकलन करना अनिवार्य है। जिसके लिए पहले एक बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश कीमत अथवा निर्मित कीमत अथवा भारत सहित अन्य देशों को ऐसे किसी देश से कीमत का मुख्य विकल्प खत्म करना होगा। केवल पहले दो विकल्पों को खत्म करने पर ही विनिर्दिष्ट प्राधिकारी पर्याप्त मायोजनों पर समुचित ध्यान देकर भारत में भुगतान की गई या भुगतान की जाने वाली कीमतों का आकलन करने के लिए किसी अन्य तर्कसंगत आधार का प्रयोग कर सकता है।

छ. 2.2 घरेलू उद्योग के विचार

- 37. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि चीन चूंकि एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था है, इसलिए उस देश में संबद्ध वस्तुओं की सामान्य कीमत उस देश में प्रचलित कीमत के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती और इसीलिए निर्मित की जानी आवश्यक है। चीन में एक सामान्य कीमत का निर्धारण करने के संबंध में घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिए हैं कि :-
 - (क) चीन एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था है और उसे विगत तीन वर्षों में इस प्राधिकारी द्वारा और यूरोपीय संघ एवं संयुक्त राज्य द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था मान लिया गया है। यहां तक कि चीन संधि में इस बात पर सहमत हो गया कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य 11 दिसंबर, 2016 तक एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में मान सकते हैं।
 - (ख) पाटनरोधी नियमों में कुछेक शर्ते विनिर्दिष्ट की गई हैं जिन्हें बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा स्थापित करने के लिए पूरा करना जरूरी है। यह उल्लेखनीय है कि बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के दावे के लिए एक प्रतिवादी निर्यातक द्वारा प्रत्येक शर्त को पूरा किया जाना चाहिए। केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जहां पर कि प्रतिवादी चीन के निर्यातक प्रत्येक मानक की पुष्टि करता है, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-। के पैरा-7 के अनुसार सामान्य कीमत निर्धारित करनी है।
 - (ग) भारत और अन्य जांच प्राधिकारियों द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था दर्जों की जांच करने के संबंध में विभिन्न घोषणाओं के आधार पर कुछेक न्यायशास्त्रों का स्पष्ट तौर पर उदय हुआ है और जब तक प्रतिवादी निर्यातक कुछ शर्तों को पूरा/ संतुष्ट नहीं करता तब तक बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता। ये शर्तें इस प्रकार हैं :-

- i. कोई भी बड़ा राज्य स्वामित्वनामा/ नियंत्रण न हो ;
- ii. प्रमुख निविष्टियों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित बाजार कीमतों को पूरा तरह से दर्शाती हों ;
- iii. उनकी बहियों की अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अन्सार लेखा परीक्षा की गई हो ।
- (घ) चीन में एक प्रतिवादी निर्यातक को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि चीन में निर्यातक नियमों के तहत विनिर्दिष्ट प्रत्येक मानदंड के संबंध में जांच में सफल नहीं हो पाते। प्रतिवादी चीन के निर्यातकों को यह प्रमाणित करना होगा कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में संचालित हो रहे हैं। बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिवादी कंपनी और इसके समूह मिलकर दावा न करेंगे। यदि समूह की एक या अधिक कंपनी ने उत्तर दाखिल नहीं किया तो बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- (ङ) मूल जांचों में वो निर्यातक, हुबेई ट्राई रिंग ऑटो एक्सल कं. लि. ('फंट एक्सल बीम' की विनिर्माता और निर्यातक कं.) और हुबेई ट्राई रिंग फोर्जिंग कं. लि. ('स्टील नॅकॅल- की विनिर्माता और निर्यातक कं.) ने उत्तर दिया था कि बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा किया था। तथापि, प्राधिकारी ने इन निर्यातकों को महत्वपूर्ण राज्य शेयरधारिता, चीन की कंपनियों की यह प्रमाणित करने में अयोग्यता को देखते हुए कि इनपुट कीमत काफी हद तक बाजार की कीमतों को दर्शाती है और साथ ही यह देखते हुए कि चीन में स्टील की कीमतें बाजार की कीमतों को नहीं दर्शाती, उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया गया था। वास्तविकता वही रही जो मूल जांचों में थी। अत: चीन की कंपनियों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए योग्य नहीं माना जाना चाहिए;
- (च) मूल जांचों में प्राधिकारी ने चीन के इन निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान नहीं किया था और चीन में सामान्य मूल्य का निधारण यथा संशोधित उक्त नियम के अनुबंध-। के पैरा- 7 और 8 के अनुसार उचित लाभ के साथ चीन में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की अनुमानित लागत के आधार पर आकलित सामान्य मूल्य के आधार पर किया। प्राधिकारी को वर्तमान जांच में चीन जन. गण. के लिए सामान्य कीमत की गणना करने के लिए वही प्रणाली अपनानी चाहिए।
- (छ) प्राधिकारी ने पूर्व जांच में यह भी नोट किया कि चीन के उत्पादकों को गैर बाजार अर्थव्यवस्था मानने के लिए घरेलू उद्योग के इस दावे पर विचार करते समय चीन के उत्पादकों या आयातकों या किसी अन्य इच्छुक पक्षकार ने एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित कीमत के संबंध में न तो कोई दावा किया और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया।
- (ज) भारत में भुगतान की गई वास्तविक कीमत पर इस कारण से विचार नहीं किया जा सका कि वह उत्पादन की लागत से कम थी। इस प्रकार प्राधिकारी के पास केवल एक उपाय उपलब्ध था कि भारत में उत्पादन की लागत पर विधिवत समायोजन के उपरांत विचार किया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय कच्ची सामग्री की कीमतें और इष्टतम परिवर्तन लागत, बिक्री, सामान्य व प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ दर्शाया जा सके। इस दृष्टिकोण पर अपील अभिकरणों और न्यायालयों ने रोक लगाई है। अत: इच्छुक पक्षकारों के तर्कों में कोई दम नहीं है।

- (झ) याचिकाकर्ता ने यह नहीं कहा है कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देशों में लागतों या कीमतों को अपनाना नहीं चाहिए। वस्तुत: याचिकाकर्ता ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का प्रस्ताव किया है।
- (ञ) प्राधिकारी ने मूल जांच में यह नोट किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत के लिए कीमतें इस कारण से भी अपनाई नहीं जा सकी कि (क) विचाराधीन उत्पाद में अनेक प्रकार की किस्में हैं जिनकी संबद्ध लागतों और कीमतों में भिन्नता है (ख) फैक्ट्री-बाहय कीमतों के निर्धारण के लिए कीमत समायोजन उपलब्ध नहीं थे (ग) इन कीमतों पर विचार नहीं किया जा सका कि तीसरे देशों से भारत के लिए कीमतें चीन से पाटन के कारण अन्पय्क्त थी।
- (ट) प्राधिकारी ने नियमों में वैकल्पिक तरीके से सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए सूचना प्रदान करने हेतु इच्छुक पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया था। किसी भी इच्छुक पक्षकार ने इस संबंध में कोई सकारात्मक सूचना प्रदान नहीं की है। अतः इच्छुक पक्षकारों का आचरण स्पष्ट तौर पर इस संबंध में प्राधिकारी को सहयोग करने की बजाय जांच की प्रक्रिया में बाधा डालना था।
- (ठ) इस प्रकार चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण (क) भारत में कीमत तथा (ख) भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा लाभ सिहत विधिवत समायोजन करने पर किया जा सकता है। चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण विधिवत समायोजन के बाद उत्पादन की लागत के आधार पर किया जाना चाहिए।
- (ड) चीन में सामान्य मूल्य का निर्माण कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार करके, और घरेलू उद्योग सहित बेहतर उपलब्ध सूचना के अनुसार खपत मानकों और परिवर्तन लागत को अपनाकर किया जाना चाहिए।
- (ढ) घरेलू उद्योग ने सशक्त तौर पर यह दलील दी है कि निर्यातकों के खपत मानकों को स्वीकार किया जाना चाहिए। यह अनुरोध किया है कि जब तक कि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर न पहुंचे कि निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए योग्य है तब तक यह तर्क बिलकुल भी उचित नहीं होगा।
- (ण) विभिन्न समायोजनों के संबंध में घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि याचिकाकर्ता ने अनुमानों के आधार पर सूचना उपलब्ध कराई है क्योंकि संगत सूचना निर्यातक या आयातक के पास है और इसीलिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। घरेलू उद्योग से ऐसे साक्ष्य की अपेक्षा करना अनुचित है जबकि संगत सूचना निर्यातक या आयातक के कब्जे में है।
- (त) याचिकाकर्ता ने फोर्ज और मशीनीकृत उत्पादों के लिए दोनों के बीच महत्वपूर्ण लागत व कीमत संबंधी अंतर को देखते हुए पृथक पाटन मार्जिन का अनुमान लगाया है। तथापि, दोनों ही उत्पाद वर्तमान क्षति अविध में केवल मशीनी रूप में आयातित किए गए हैं और पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तरों से अधिक और महत्वपूर्ण है।

ज. मामलों की जांच और सामान्य मूल्य का निर्धारण

38. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि विश्लेषण किए गए आयात आंकड़ों के अनुसार चीन ने जांच की अविधि के दौरान भारत को केवल 279 मीट्रिक टन फ्रंट एक्सलबीम (मशीनीकृत) और 181 मीट्रिक टन स्टीयिरंग नॅकॅल (मशीनीकृत) का निर्यात किया है। मैसर्स हुबेई ट्राई - रिंग फोर्जिंग कं. लि. (एच टी आर एफ) ने स्टीयिरंग नॅकॅल के निर्यातक के रूप में प्रश्नावली उत्तर दाखिल किए जबिक मैसर्स ट्राई - रिंग ऑटो एक्सल कं. लि. (एच टी आर ए) ने फ्रंट एक्सल बीम के निर्यातक के रूप में प्रश्नावली उत्तर दाखिल

किए। दोनों ही उत्पादकों में परस्पर संबंध हैं और बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने और घरेलू बाजार में बिक्री के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार की प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है। जांच की अविध के दौरान एल टी आर एफ ने **** मीट्रिक टन स्टीयिरेंग नॅकॅल का भारत को निर्यात किया है और एच टी आर ने भारत को **** मीट्रिक टन फ्रंट एक्सल बीम का निर्यात किया है। प्रतिवादी उत्पादक निर्यातकों ने अपने अनुरोध में अन्य बातों के साथ - साथ यह दावा किया है कि :

- क. वे चीन में फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयरिंग नॅकॅल के संबंध में सबसे बड़े उत्पादक हैं। यद्यपि भारत में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण निर्यात कम हुआ है। भारतीय ग्राहकों ने बेहतर उत्पाद गुणवत्ता और मांग की पूर्ति के लिए भारतीय उत्पादकों की अक्षमता के कारण निर्यातक से विचाराधीन उत्पाद का आयात जारी रखा।
- ख. उनकी निर्माण प्रक्रिया याचिकाकर्ता की निर्माण प्रक्रिया से भिन्न है।
- ग. एच टी आर ए ने यह दावा किया है कि बड़े पैमाने पर फ्रंट एक्सल बीम के निर्माण के लिए 'होट प्रैस' के साथ 'रोल फॉर्मिंग' करते हैं। भारत के लिए निर्यात किए गए उत्पाद और एच टी आर एफ द्वारा घरेलू बाजार में बेचे गए उत्पाद या किसी अन्य देशों को बेचे गए उत्पाद के बीच अंतर सामग्री, भारत अथवा प्रक्रिया की कठिनाइयों के संबंध में है।
- घ. एच टी आर एफ ने यह दावा किया है कि स्टीयरिंग नॅकॅल के निर्माण के लिए उनके द्वारा प्रयोग की गई प्रक्रिया के लिए अपेक्षित निवेश कम है और लागत भी कम है। एच टी आर एफ ने यह भी दावा किया है कि वे विभिन्न वेल्डिंग सामग्रियों का उपयोग करके डाई रिपेयर के उन्नत तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिससे डाई की उम्र बढ़ती है और परिणामस्वरूप तैयार उत्पाद की प्रति यूनिट रनिंग लागत कम होती है। इसके अलावा, भारतीय निर्माता द्वारा प्रयुक्त स्टील विनिर्देशन महंगा है।
- 39. दोनों ही उत्पादक निर्यातकों के बाजार अर्थव्यवस्था के दावों और उनके द्वारा प्रस्तुत अन्य आंकड़ों की पृष्टि स्थल पर ही जांच करके की गई।

ज. 1 प्रतिवादी निर्यातकों के बाजार अर्थव्यवस्था के दावों की जांच

- 40. यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध । के पैरा 8 के अनुसार गैर- बाजार अर्थव्यवस्था की संकल्पना को केवल तभी नकारा जा सकता है यदि चीन के निर्यातक पैरा 8 के उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर और इसे प्रतिकूल सिद्ध करके पर्याप्त साक्ष्य और सूचना उपलब्ध कराए। चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के सहयोगी निर्यातकों/ उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3) में उल्लिखित आवश्यक सूचना पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है तािक निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सके कि क्या :-
 - (क) चीन जन. गण. में संबंधित फर्मों का मूल्यों, लागतोंअऔर निविष्टियों जैसे कच्ची सामग्री, प्रौद्योगिकी एवं श्रम की लागत, आउटपुट, बिक्री तथा निवेश के संबंध में निर्णय आपूर्ति और मांग को दर्शाने वाले बाजार के संकेतों को देखकर और इस संबंध में राज्य के पर्याप्त हस्तक्षेप के बिना किए गए हैं और क्या प्रमुख विनिष्टियों की लागत पर्याप्त रूप से बाजार की कीमतों को दर्शाती है;
 - (ख) उत्पादन लागत और ऐसी फर्मों की वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपित्तयों के मूल्य हास, अन्य बहे खाते की राशियों, विनिमेय व्यापार और ऋण क्षितिपूर्ति के द्वारा भुगतान के संबंध में पूर्व गैर बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से हटकर विपरीत परिवर्तन करने के अध्यधीन हैं;

- (ग) ऐसी फर्में दिवालिएपन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं, जो फर्म के प्रचालन के लिए कानूनी निश्चिंतता और स्थायित्वता की गारंटी है; और
- (घ) विनिमेय दर परिवर्तन बाजार की दर पर किए गए हैं।
- 41. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इन दोनों उत्पादक निर्यातकों में परस्पर संबंध है और साझा स्वामित्व में प्रचलित होते हैं। इन कंपनियों ने मूल जांच में भी बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा किया था। तथापि, इस जांच में प्रतिवादी निर्यातकों के बाजार अर्थव्यवस्था दावों की उक्त नियमों के अनुसार पुन: जांच की गई है।

(i) मैसर्स ह्बेई ट्राई - रिंग ऑटो एक्सल कं., लिमि., चीन जन. गण. (एच टी आर ए)

एच टी आर ए के बाजार अर्थव्यवस्था के दावों की जांच की गई है और यह नोट किया गया है कि जांच 42. की अविध के दौरान दो प्रमुख शेयरधारक अर्थात मैसर्स ह्बेई ट्राई - रिंग हैवी इंडस्ट्रीज लि. और मैसर्स हबेई ट्राई - रिंग ग्र्प कं. लि. का एच टी आर ए का क्रमश: *** प्रतिशत अंश और *** प्रतिशत अंश है। यह भी उल्लेख किया गया है कि ट्राई-रिंग ग्र्प कं. लि. का ह्बई ट्राई-रिंग हैवी इंडस्ट्रीज कं. लि. का पूर्ण स्वामित्व है। व्यक्तियों का स्वामित्व टी आर ए के शेष *** प्रतिशत शेयर का है तथापि, जांच की अवधि के उपरांत यह स्थिति बदल गई है क्योंकि ह्बेई ट्राई-रिंग हैवी इंडस्ट्रीज कं. लि. और ट्राई- रिंग ग्र्प कं. लि. का अब टी आर ए *** प्रतिशत हिस्सा है। जांच की अवधि के दौरान ह्बेई ट्राई- रिंग हैवी इंडस्ट्रीज कं. लि. के पास अब टी आर का *** प्रतिशत हिस्सा है, क्योंकि इसने *** प्रतिशत शेयर खरीदें हैं जो पहले व्यक्तियों के पास थे। लेकिन ट्राई- रिंग ग्रुप कं. लि. के पास अभी भी टी आर ए में *** प्रतिशत हिस्सा बरकरार है। अत: कंपनी अब पूर्ण रूप से राज्य के स्वामित्व का उपक्रम है। यह भी नोट किया गया है कि टी आर ए के बोर्ड में 7 निदेशकों में से 6 की नियुक्ति ट्राई-रिंग ग्रुप कं. लि. द्वारा की जाती है, जो एक राज्य के स्वामित्व वाला उपक्रम है। अत: यह कंपनी पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनी है। यह भी नोट किया गया है कि एच टी आर ए दवारा दो परस्पर संबद्ध राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं और अन्य प्राइवेट संस्थाओं से प्रमुख कच्ची सामग्रियों अर्थात स्टील की खरीद की जाती है।

(ii) मैसर्स ह्बेई ट्राई - रिंग फोर्जिंग कं., लिमि., चीन जन. गण. (एच टी आर एफ)

- 43. प्राधिकारी ने यह उल्लेख किया है जांच की अविध के दौरान मैसर्स हुबेई ट्राई-रिंग हैवी इंडस्ट्रीज का एच टी आर एफ में *** प्रतिशत हिस्सा है और एच टी आर एफ की लेबर यूनियन का एच टी आर में *** प्रतिशत हिस्सा है। यह भी नोट किया गया है कि मैसर्स ट्राई- रिंग ग्रुप कंपनी लि. का हुबेई ट्राई-रिंग हैवी इंडस्ट्रीज कं. लि. में पूर्ण स्वामित्व है। जबिक ट्राई रिंग ग्रुप कं. लि. एक राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी है। अलग व्यक्तियों का टी आर एफ में शेष *** प्रतिशत हिस्सा है। जांच की अविध के बाद यह स्थिति नहीं बदली। यह भी नोट किया गया है कि एच टी आर एफ बोर्ड में 7 निदेशकों में से 6 की नियुक्ति ट्राई रिंग ग्रुप कं. लि. द्वारा की जाती थी। 7 निदेशकों, एक प्राइवेट व्यक्ति के पास कुछ शेयर होते हैं और उनका बोर्ड में अध्यक्ष भी है। अतः प्राधिकारी ने यह नोट किया कि कंपनी ने एक राज्य के नियंत्रण और प्रबंधन वाली कंपनी के रूप में कार्य जारी रखा, हालांकि रिकार्ड के अनुसार, एक निजी व्यक्ति के पस कुछ शेयर थे।
- 44. स्टीयरिंग नॅकॅल के उत्पादन के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री अलॉय स्टील बार है और इसका एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता मैसर्स *** कं. लि. है जो मैसर्स *** कं. का ही एजेंट है और यह ट्राई-रिंग ग्रुप कं. लि. की एक सहायक कंपनी है। इस कंपनी की जिम्मेदारी ग्रुप की सहायक कंपनियों के लिए कच्चा माल खरीदने के लिए एक अन्य संबद्ध कंपनी मैसर्स *** कं. लि. के साथ सहयोग करने की है। दो अन्य निजी

कंपनियां भी टी आर एफ को स्टील बार की आपूर्ति करती हैं। तथापि, कच्ची सामग्री की खरीद राज्य के स्वामित्व से संबंधित कंपनियों से की जाती है।

- 45. उपरोक्त जांच से पता चलता है कि दोनों ही प्रतिवादी निर्यातक राज्य के स्वामित्व और नियंत्रण वाली हैं। प्राधिकारी इच्छुक पक्षकारों के तर्कों को नोट करता है कि मात्र राज्य की धारिता होने से कंपनी के कार्यों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं माना जाता। यह तर्क दिया गया है कि पहले प्राधिकारी ने चीन में कुछ स्टील उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किया था। अत: यह नहीं माना जा सकता कि चीन में प्रमुख कच्चा माल बाजार की सही स्थिति नहीं दर्शाता।
- 46. इस संबंध में प्राधिकारी ने यह नोट किया कि बाजार अर्थटयवस्था की स्थिति की जांच एक समग्र आकलन है, जिसमें कंपनी के स्वामित्व, निर्णय लेने की प्रक्रिया और कच्चे माल की कीमतों आदि जैसे कई अन्य मामलों सिहत अनेक कारकों को ध्यान में रखा जाता है। यद्यिप स्वामित्व होना निर्धारण का कारण नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसकी वाणिज्यिक क्रियाकलापों में निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ जांच की जाती है। इस मौजूदा मामले में बोर्ड बिना किसी स्वतंत्र सदस्य के सरकारी नामित व्यक्तियों से भरा हुआ है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि हॉट रोल्ड स्टील के उत्पादों में हाल ही की जांच में चीन में उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया गया है, जिससे स्पष्ट तौर पर यह साबित होता है कि चीन में कच्चे माल की कीमतें बाजार की सही स्थिति नहीं दर्शाती। विनिमय दर और ब्याज दर की सरकार दवारा व्यापक प्रबंधन किया जाता है और यह बाजार की सही स्थिति नहीं दर्शाती।
- 47. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि प्रतिवादी उत्पादक निर्यातकों पर राज्य का पर्याप्त नियंत्रण है और उक्त कंपनियों द्वारा संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख कच्चे माल की कीमतें परस्पर संबंधों के आधार पर खरीद करने और देश में सामान्य गैर बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति मौजूद होने के कारण बाजार की सही स्थिति सामने नहीं आती। अत: प्राधिकारी का यह मानना है कि घरेलू बाजार में कंपनी की लागत और कीमतें बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति नहीं दर्शाती और उसे चीन में संबद्ध वस्तुओं की सामान्य कीमतों के निर्धारण के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। उपर्युक्त के आलोक में निर्यातक द्वारा प्रकटीकरण के उपरांत के अपने अनुरोधों में दोहराए गए इन तर्का को मान्य नहीं समझा गया।

ज. 2 सामान्य मूल्यों का निर्धारण

- 48. चूंकि प्राधिकारी ने यह पाया है कि घरेलू बाजार में प्रतिवादी निर्यातक की लागत और मूल्य बाजार की सही स्थिति नहीं दर्शाते इसलिए प्राधिकारी ने चीन में सामान्य मूल्यों के निर्धारण के लिए नियमों में अन्य वैकल्पिक प्रावधानों की ओर रुख किया।
- 49. पाटनरोधी नियमावली के अन्बंध-। के पैरा -7 में उपबंध हैं कि :

"गैर -बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सिहत अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान

दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।"

- 50. इस संबंध में प्राधिकारी ने यह नोट किया है इच्छुक पक्षकारों के ये तर्क कि प्राधिकारी को तीसरे विकल्प का उपयोग करने से पूर्व पहले पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-। के पैरा- 7 में प्रथम और द्वितीय विकल्प की जांच करनी चाहिए। इस संबंध में प्राधिकारी ने यह नोट किया कि किसी भी इच्छुक पक्षकार ने एक उपयुक्त तीसरे देश का उस देश में लागत और कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए अथवा उस देश से भारत सहित अन्य देशों को उक्त पैरा-7 में दिए गए पहले दो विकल्पों के अनुसार चीन में सामान्य मूल्य के रूप में एक प्रतिनिधि के रूप में चयन करने के लिए कोई भी सार्थक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि जांच की अवधि के दौरान किसी अन्य देश से संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं हुआ। अतः किसी भी अन्य देश से कीमतों को उक्त प्रावधान के आधार पर चीन में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता।
- 51. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमों में उल्लिखित तीसरे विकल्प के तहत चीन में सामान्य मूल के निर्धारण के लिए प्रस्ताव किया है। प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि निर्यातक के उपभोक्ता मानदंडों को तब तक उत्पादन की लागत और सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए माना नहीं जा सकता जब तक कि निर्यातक को पूर्ण बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान न कर दिया जाए। इस संबंध में प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि खपत की गई प्रौद्योगिकी और हासिल की गई क्षमता का एक कारक है और उसमें ऐसे वाणिज्यिक पहलुओं का कोई संबंध नहीं है, जो गैर बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति से प्रभावित होते हैं। अत: यह प्रतिवादी निर्यातक के खपत मानदंडों का समुचित दस्तावेजीकरण करके निर्यातक के अभिलेखों से सत्यापन किया जाए तो अन्य स्रोतों से अन्य कारकों को स्वीकार करके लागतों का निर्माण करते समय इसे नरजअंदाज नहीं किया जा सकता।
- 52. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि प्रतिवादी निर्यातक ने घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई उत्पादन प्रक्रिया की तुलना में उनके द्वारा प्रयुक्त उत्पादन प्रक्रिया में कुछ अंतर होने का दावा किया है। एच टी आर ए उत्पादन प्रक्रिया में प्री-रॉलिंग करता है जो हॉट राउंड बार को एक एक्सल बीम में प्रारंभिक आकार में बदल देता है। उसके बाद दबाव की अवस्था में केवल 2500 मी. टन दबाव ही किया जाता है ताकि हॉट बार को अंतिम आकार दिया जा सके। यह दावा किया गया है कि इस रोल फोर्जिंग की प्रक्रिया से दबाव की अवस्था के दौरान एक भारी दबाव का प्रयोग करने की जरूरत काफी कम हो जाती है और साथ ही ट्रिमिंग के रूप में कम स्क्रेप होने के कारण सामग्री की खपत भी कम होती है। एच टी आर एफ की संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन प्रक्रिया में 250 के जी प्रोग्राम कंट्रोल हाइड्रोलिक हैमर का प्रयोग शामिल है। टी आर एफ ने यह दावा किया है कि फोर्जिंग के लिए हाइड्रोलिक हैमर का प्रयोग करने के तीन फायदे हैं: (i) हैमर फोर्जिंग में स्टीयरिंग नॅकॅल की एक व्यापक उत्पाद रेंज तैयार की जा सकती है; (ii) इसमें कम ऊर्जा का उपयोग होता है; और (iii) इस प्रक्रिया के लिए अपेक्षित निवेश परंपरागत प्रैस फोर्जिंग प्रक्रिया की तुलना में कम होता है।
- 53. जहां तक निर्माण प्रक्रिया में अंतर से संबंधित निर्यातक की दलील का संबंध है, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि यद्यपि प्रतिवादी निर्यातक द्वारा प्रयुक्त उत्पादन प्रक्रिया में उपरोक्तानुसार कुछ अंतर है, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि क्या यह वास्तव में उत्पादन की यूनिट लागत में भी बचत करता है। तथापि, इसके खपत संबंधी मानदंडों में यथा सत्यापित और दर्शाए गए अनुसार कम नुकसान होने के संबंध में बचत को सामान्य मूल्यों के निर्धारण के लिए शामिल किया गया है। उतना ही उत्पादन प्रक्रिया में अंतर पर भी विचार किया गया है। तथापि, सही त्लना के लिए प्रति कि.ग्रा. के अनुसार सामान्य मूल्य

किया गया है और घरेलू उद्योग तथा निर्यातक के इनपुट/ आउटपुट अनुपात/ खपत मानकों में कोई अधिक अंतर नहीं है।

- 54. निर्यातक ने प्रकटीकरण के उपरांत के अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि सामान्य मूल्य तैयार करने के लिए प्रतिवादी निर्यातकों के खपत संबंधी मानकों और कच्ची सामग्री के मूल्यों पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग भी चीन में उसी आपूर्तिकर्ता से कच्चे माल की खरीद करता है । यह भी तर्क दिया गया है कि सामान्य मूल्य तैयार करने के लिए ब्याज लागतों और पैकेजिंग लागतों को अलग रखा जाना चाहिए । इस संबंध में प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि प्राधिकारी की संगत प्रथा के अनुसार सामान्य मूल्य तैयार किए गए हैं । जहां तक कच्ची सामग्री का संबंध है यदि घरेलू उद्योग चीन में उसी आपूर्तिकर्ता से उसी मूल्य पर वस्तुओं की खरीद करता है तो निर्यातकों की कच्ची सामग्री की कीमतों पर, तैयार किए गए सामान्य मूल्य में उसी हिसाब से कब्जा किया गया है ।
- 55. तदनुसार, जांच की अविध के दौरान आयातित फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयिरंग नॅकॅल के उत्पाद कि किस्मों का सामान्य मूल्य मशीनीकृत स्थिति में आयातित फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयिरंग नॅकॅल के लिए जांच अविध के दौरान हासिल प्रतिवादी निर्यातकों और घरेलू उद्योग के सर्वाधिक सक्षम मानकों के खपत मानकों पर विधिवत विचार करने के बाद निर्धारित किया गया है। जहां कहीं, जांच की अविध के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कोई मॉडल विशेष तैयार नहीं किया वहां निर्यातक के खपत संबंधी मानकों को अपनाया गया है। संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयुक्त प्रमुख कच्चे माल के रूप में कार्बन स्टील/ विशिष्ट श्रेणी का अलॉय स्टील है, जिसके लिए विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय कीमतें उपलब्ध नहीं थीं। अतः घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री खरीदने की कीमतें अपनाई गई हैं उपयोग की लागत पर घरेलू उद्योग के बेहतर खपत मानकों के अनुसार विचार किया गया है। लागत के अन्य सभी घटक घरेलू उद्योग के इष्टतम उत्पादन पर आधारित हैं। निर्मित लागत के 5 प्रतिशत का सामान्य लाभ प्रदान किया गया है जो प्राधिकारी के सतत प्रयोग के तहत निर्मित सामान्य मूल्य के लिए किया गया है।
- 56. विचाराधीन अविध के दौरान चीन से निर्यातकों ने केवल दो प्रकार के फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयिरंग नॅकॅल अर्थात एफ ए 90 और एफ ए 99 का ही मशीनीकृत रूप से निर्यात किया गया था। चूंकि जांच की अविध के दौरान केवल मशीनीकृत उत्पादों का ही निर्यात किया गया है, इसलिए मशीनीकृत रूप में इन दो प्रकार के फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयिरंग नॅकॅल के लिए सामान्य मूल्य निर्यात उत्पादों के समान तुलना करने के लिए निर्धारिण किया गया है। निर्मित सामान्य मूल्यों का आकलन इस प्रकार किया गया है:

सीएनवी यूएसडी/ कि. ग्रा.	एस के	एस के	एफएबी	एफएबी
	मशीनीकृत	मशीनीकृत	मशीनीकृत	मशीनीकृत
	एफए 90	एफए 99	एफए 90	एफए 99
	अमरीकी	अमरीकी	अमरीकी	अमरीकी
	डॉलर/ किग्रा.	डॉलर/ किग्रा.	डॉलर/ किग्रा.	डॉलर/ किग्रा.
अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार कच्ची सामग्री की	***	***	***	***
लागत				
उपयोग की लागत	***	***	***	***
ब्याज सहित एसजीए (स्क्रैप मूल्य का निवल	***	***	***	***
ऋण)				
बनाने व बेचने की लागत	***	***	***	***
लाभ	***	***	***	***
निर्मित सामान्य मूल्य (अमरीकी डॉलर/ किग्रा.)	***	***	***	***

ज. ३ निर्यात मूल्य

मैसर्स ह्बेई ट्राई - रिंग ऑटो एक्सल कं., लिमि., चीन जन. गण. (एच टी आर ए) का निर्यात मूल्य

57. जांच की अविधि के दौरान एच टी आर ए ने भारत में केवल एक ग्राहक अर्थात अशोक लीलेंड लि. को सीधे केवल मशीनीकृत फ्रंट एक्सल बीम का निर्यात किया गया था और भारत को 3915 फ्रंट एक्सल बीम, जिनका भारत 331.21 मीट्रिक टन था, का निर्यात किया था। दो विभिन्न प्रकार के फ्रंट एक्सल बीम इस अविधि के दौरान भारत को निर्यात किए गए जो एफए 90 और एफए 99/ एफ वी डी पी है। लेनदेन सी एन एफ के रूप में था। ऑन स्पॉट जांच के दौरान पूर्व कार्यों के अनुसार अपेक्षित लेन देन व समायोजनों का सत्यापन किया गया। यह उल्लेख किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के निर्यात पर वेट की वापसी की दर 17 प्रतिशत है। अतः वेट के लिए कोई समायोजन अपेक्षित नहीं है। तदनुसार फ्रंट एक्सल बीम के लिए नेट एक्स वर्क्स निर्यात कीमत इस प्रकार निर्धारित की गई है:

उत्पाद	कि. ग्रा.	कि. ग्रा. नेट	देश के अंदर	पोर्ट और	गैर वापसी	समुद्री	बैंक	ऋण लागत	नेट	नेट
कोड	नेट भार	भार में	यातायात	अन्य	योग्य वुडन	भाड़े का	प्रभारों	का योग	वसूली	ईपी
	में मात्रा	मात्रा का	का योग	निर्यात	पैकिंग की	योग	का योग	(यूएसडी)	(यूएसडी)	यूएसडी/
	का योग	योग	(यूएसडी)	संबंधी व्यय	लागत का	(यूएसडी)	(यूएसडी)			किग्रा.
		(यूएसडी)		का योग	योग					
				(यूएसडी)	(यूएसडी)					
एफए 90	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
एफवीडीपी/	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
एफए99										
सकल योग	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

58. निर्यातक ने प्रकटीकरण के उपरांत की अपनी टिप्पणियों में यह कहा है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह फ्रंट एक्सल बीम के लिए कारखाना -बाइय निर्यात मूल्य के निर्धारण में अंतर्देशीय यातायात, समुद्री मालभाड़ा और बैंक प्रभारों को अपनाए , जैसा कि सहयोगी निर्यातक द्वारा सूचित किया गया है । इस संबंध में प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि प्रत्यक्ष बिक्री व्यय , जैसा कि निर्यातक द्वारा सूचित और किया गया है और पुष्टि की गई है , को प्रश्नावली के उत्तर में यथा सूचित दैनिक विनिमय दर को अपनाकर यू एस डॉलर में परिवर्तित किया गया है और इसे निर्यात मूल्यों के निर्धारण के लिए उचित तरीके से अपनाया गया है ।

मैसर्स हुबेई ट्राई-रिंग फोर्जिंग कं., लिमि., चीन जन. गण. (एच टी आर एफ) का निर्यात मूल्य

59. जांच की अविधि के दौरान टी आर एफ भारत में केवल एक ग्राहक, अर्थात मैसर्स अशोक लीलेंड लि. के केवल मशीनीकृत स्टीयिरिंग नॅकॅल का निर्यात किया था। जांच की अविधि के दौरान *** मीट्रिक टन भार के *** नग स्टीयिरिंग नॅकॅल का निर्यात किया गया था। इस अविधि के दौरान भारत को दो प्रकार के नॅकॅल अर्थात एफए 90 और एफए 99 का निर्यात किया गया था। लेन देन सी एन एफ के रूप में था। ऑन स्पोट जांच के दौरान पूर्व कार्यों के लिए अपेक्षित लेन देन और समायोजनों का सत्यापन किया गया था। यह उल्लेख किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं के निर्यात पर वेट की वापसी दर 17 प्रतिशत है। अतः वेट के लिए किसी समायोजन की जरूरत नहीं है। तदनुसार स्टीयिरिंग नॅकॅल के लिए नेट एक्स- वर्क्स निर्यात कीमत इस प्रकार है:

लेबल	उत्प	इ नेट	देश में	पैकिंग	पोर्ट और	समुद्री	बैंक	क्रेडिट	नेट	नेट ईपी
	के	इनवॉयस	यातायात	कम का	अन्य	भाड़े का	प्रभारों	लागत	निर्यात	(यूएसडी/कि.
	भारत	कायोग	का योग	जोड़	निर्यात	योग	का योग	का योग	मूल्य	ग्रा.
	का	(यूएसडी)	(यूएसडी)	(यूएसडी)	संबंधी	(यूएसडी)	(यूएसडी)	(यूएसडी)	(यूएसडी)	
	योग	·			व्यय					

	कि.ग्रा.				(यूएसडी)					
एफए 90 स्टीयरिंग नॅकॅल	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
एफए 99 स्टीयरिंग नॅकॅल	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
सकल योग	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

ज. 4 पाटन मार्जिन

60. चीन से प्रतिवादी निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए पूर्व कार्यों से निर्मित सामान्य मूल्य और इस प्रकार से निर्धारित निबल पूर्व कार्यों के निर्यात मूल्यों की तुलना की गई है, जो इस प्रकार है:

पाटन मार्जिन टी आर ए

						1	
उत्पाद का प्रकार	मात्रा	एन वी	ई पी अमरीकी	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन	पाटन मार्जिन
	किग्रा. में	अमरीकी	डॉलर/ मी. टन	अमरीकी डॉलर/	कीमत	मार्जिन%	की रेंज
		डॉलर/ मी.		मी. टन			
		टन					
एफए 90	***	***	***	***	***	***%	
एफए 99	***	***	***	***	***	***%	
कुल	***	***	***	***	***	***%	10-20%
पाटन मार्जिन टी आर एफ							
उत्पाद का प्रकार	मात्रा	एन वी	ई पी अमरीकी	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन	पाटन मार्जिन
	किग्रा. में	अमरीकी	डॉलर/ मी. टन	अमरीकी डॉलर/	कीमत	मार्जिन%	की रेंज
		डॉलर/ मी.		मी. टन			
		टन					
एफए 90 स्टीयरिंग नॅकॅल	***	***	***	***	***	***%	
एफए 99 स्टीयरिंग नॅकॅल	***	***	***	***	***	***%	
सकल योग	***	***	***	***	***	***%	0-10%

ज. 5 चीन से अन्य निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन

61. चीन जन. गण. से अन्य निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण तथ्यों के आधार पर किया गया है, जो इस प्रकार है :

	एन वी अमरीकी डॉलर/	ई पी अमरीकी	पाटन मार्जिन अमरीकी डॉलर/	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन की
	मी. टन	डॉलर/ मी. टन	मी. टन		रेंज
एफ ए बी	***	***	***	***%	40-50%
एस के	***	***	***	***%	5-15%

62. दोनों उत्पादों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन डी - मिनिमाइज से अधिक और महतवपूर्ण है।

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध की प्रणाली और निर्धारण

63. जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, निर्णायक समीक्षा जांच में, क्षिति जांच के संबंध में प्राधिकारी को यह जांच करनी होती है :

- क्या घरेलू उद्योग को निरंतर क्षिति का सामना करना पड़ा और यदि हां तो घरेलू उद्योग को क्षिति के जारी रहने की संभावना है।
- यदि घरेलू उद्योग के निरंतर क्षिति का सामना नहीं करना पड़ा, तो क्या घरेलू उद्योग को,
 पाटनरोधी श्ल्कों के निरसन की अवस्था में प्नः क्षिति होने की संभावना है।
- 64. घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद का निरंतर पाटन होता रहा, यद्यपि पाटित आयातों की मात्रा में, वर्तमान पाटनरोधी शुल्कों के परिणामस्वरूप गिरावट आई है और यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क का निरसन किया गया तो पाटन में तेजी आने की संभावना है।
- 65. अतः प्राधिकारी ने संबद्ध देश से शुल्कों के निरसन की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षिति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की जांच आरंभ करने से पूर्व यह जांच की कि क्या घरेलू को संबद्ध देश से पाटित आयातों के संबंध में निरंतर भारी क्षिति का सामना करना पड़ा। घरेलू उद्योग को भारी क्षिति होने की जांच पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-।। और पाटनरोधी करार के खंड 3 के अनुसार है।
- 67. प्राधिकारी ने यह नोट किया कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखने के लिए आवेदन मैसर्स भारत फोर्ज लि. द्वारा दाखिल किया गया है, जो भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन का बड़ा हिस्सा कवर करता है। नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार याचिकाकर्ता को इस जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है। अतः इस निर्धारण के प्रयोजन से नियम 2(ख) के अनुसार, घरेलू उद्योग, याचिकाकर्ता की लागत और क्षति संबंधी सूचना की जांच की गई है।

झ. 1. घरेलू उदयोग के क्षिति दावों के संबंध में प्रतिवादी निर्यातकों और आयातकों के विचार

- 68. प्रतिवादी निर्यातकों और आयातकों ने अपने विभिन्न अनुरोधों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित तर्क दिए हैं :
 - यह कि एक निर्णायक समीक्षा में पूरी जांच इस तथ्य पर केंद्रित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क के निरसन से घरेलू उद्योग को पाटन अथवा क्षति की पुनरावृत्ति होगी। अत: यह पाटन और क्षति वर्तमान स्तर की नहीं है, जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन पाटन और क्षति की संभावना है, जो एक निर्णायक समीक्षा जांच में अधिक आवश्यक है। इस प्रकार एक जांच प्राधिकारी को भावी घटनाओं का एक विश्लेषण करना होता है ताकि पाटन अथवा क्षति की संभावना का निर्धारण हो सके। तथापि, वर्तमान जांच में याचिकाकर्ता ने जांच की अवधि के बाद के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं जिससे कि यह उल्लेख किया जा सके कि क्षति और पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना के दावे के लिए, इससे हो रही क्षति अथवा पाटन जारी रहा।

- याचिकाकर्ता, यदि पाटनरोधी शुल्कों को निरस्त कर दिया जाता है तो भविष्य में पाटन या क्षिति की पुनरावृत्ति की संभावना प्रमाणित करने में असफल रहा।
- विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-।।। के तहत उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर गैर-क्षिति कीमतों का निर्धारण करे। विनिर्दिष्ट प्राधिकारी गैर-क्षिति मूल्य तय करते समय पिछले तीन वर्षों और जांच की अविध के दौरान उत्तम क्षमता के उपयोग पर विचार करे। इसके अलावा, घरेलू उद्योग के लिए यह बिलकुल ही अनुचित होगा कि आवश्यकता से अधिक प्रतिफल दर का दावा करे और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे लाभ की अनुमित दे। घरेलू के केवल ऐतिहासिक प्रतिफल दर आर ओ सी ई के निर्धारण के लिए विचार किया जाए, जिसे गैर-क्षिति मूल्यों की गणना करने में अपनाया जाए। केवल वही ऋण जो उससे संबंधित है अथवा संबद्ध उत्पाद के लिए विभाजित किए गए हैं, गैर क्षिति कीमतों का निर्धारण करते समय शामिल किए जाएं।
- फंट एक्सल बीम और स्टीयिरंग नॅकॅल के संबंध में अयात संबंधी आंकड़े बिलकुल स्पष्ट हैं कि संबद्ध उत्पाद का आयात तेजी से गिर रहा है और इस प्रवृत्ति में बदलाव होने का कोई संकेत नहीं है। फंट एक्सल बीम के आयातों में जांच की अविध में मात्र 3.12 प्रतिशत की घरेलू बिक्री और केवल 1.48 प्रतिशत की कुल मांग शामिल है। इसी प्रकार स्टीयिरंग नॅकॅल के आयातों में जांच की अविध में कुल भारतीय मांग का केवल 1.98 प्रतिशत ही शामिल है। यह समझ से परे है कि इतने कम आयातों से कैसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।
- याचिका से आंकड़े स्पष्ट तौर पर यह बताते हैं कि आयातों की कीमतें फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयरिंग नॅकॅल, दोनों के लिए बढ़ रही हैं। तथापि, यही आश्चर्य की बात है कि घरेलू उद्योग कम मात्रा और अधिक कीमत के आयातों के बावजूद कीमत वृद्धि करने में असमर्थ रहा है। यह समझ से परे है कि अत्यधिक कम मात्रा में संबद्ध उत्पाद घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर सकता है।
- आयातों की कम मात्रा और घरेलू उद्योग की कीमतों में कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। प्रतिवादियों ने यह अनुरोध किया है कि केवल कुछेक दु:खद कारकों के कारण, घरेलू उद्योग को क्षिति का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यह क्षिति संबद्ध उत्पादों के आयातों के कारण नहीं हो सकती। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने पहले ही यह स्वीकार कर लिया है कि यह मंदी के कारण का जिससे संबद्ध उत्पादों की मांग में कमी आई। अत: मंदी के कारण क्षिति संबद्ध उत्पाद के आयातों के कारण नहीं हो सकती।
- याचिकाकर्ता का लाभ/हानि, नकद लाभ और पी बी आई टी में गिरावट आ रही है जबिक क्षिति अविध के दौरान संबद्ध उत्पादों के आयातों में पर्याप्त गिरावट आई है। उपर्युक्त के आलोक में संबद्ध जांच में कारणात्मक संबंध प्रमाणित नहीं हो पाया है। इसके अलावा, अन्य घरेलू उत्पादकों ने घरेलू बाजार में पर्याप्त हिस्सा लिया है, जिससे याचिकाकर्ता के बाजार अंश में पर्याप्त कमी आई है।
- याचिकाकर्ता निर्यात बाजारों पर केंद्रित रहा जबिक उसे भारत में अपनी बाजार में उपस्थिति को बढ़ाने के लिए कदम उठाना चाहिए था। याचिकाकर्ता यह तर्क नहीं दे सकता िक वह निर्यात बाजार में अपनी वस्तु सूची का निपटान कर रहा है क्योंकि याचिकाकर्ता के पास संबद्ध उत्पाद की कोई वस्तु सूची नहीं है, क्योंकि संबद्ध उत्पाद को आदेश पर बनाया जाता है।

- निर्दिष्ट प्राधिकारी पर खंड 11.3 के तहत अपेक्षित विश्लेषण के स्तर को पूरा करने के संबंध में कार्रवाई करने का काफी भार है। खंड 11.3 के तहत विश्लेषण करते समय जांच की अविध के बाद के आंकड़ों पर विचार किया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि वर्तमान मामले में इस अपेक्षा की पूर्ति की जाए क्योंकि किसी भी क्षिति के होने को साबित नहीं किया जा सका और निर्दिष्ट प्राधिकारी शुल्क में किसी वृद्धि को न्यायोचित ठहराने के लिए उचित कार्रवाई करे। वर्तमान मामले में बुनियादी जरूरत को पूरा किया बिना की गई कोई समीक्षा निर्णायक समीक्षकों से संबंधित सभी विनियमों और कान्नों का उल्लंघन होगा।
- याचिकाकर्ता कुछेकअन्य अतिरिक्त कारकों को दर्शाने में असफल रहा जिससे क्षिति हो सकती
 थी और इसीलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी उन कारकों की जांच करे जैसे मंदी के कारण उत्पाद
 और बिक्री में गिरावट; और विनिमय दर पर विचार।
- पर्याप्त संरक्षण के बावजूद घरेलू उद्योग भ्रमवश बिना सहायक आंकड़ों के वर्तमान मामले में पाटन और क्षिति की पुनरावृत्ति अथवा उसके जारी रहने की संभावना का दावा कर रहा है। घरेलू उद्योग को किसी अनुचित संरक्षण की जरूरत नहीं और इसीलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी वर्तमान समीक्षा को समाप्त करे।
- क्षिति, यिद कोई है तो वह भारतीय बाजार में परस्पर स्पर्द्धा के कारण है या घरेलू उद्योग के स्वाभाविक कारणों की वजह से है। अन्य भारतीय उत्पादक क्षित अविध के दौरान धीरे-धीरे अपनी बिक्री को बनाए रखने में समर्थ हैं और वास्तव में उन्होंने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर कब्जा किया।
- घरेलू उद्योग की गिरती बिक्री का अन्य कारण ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी का होना है।
 मशीनीकृत संबद्ध उत्पाद की बिक्री में गिरावट का कारण मशीनीकृत संबद्ध उत्पाद के लिए कम मांग का होना है।
- फोर्ज संबद्ध उत्पाद के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षिति का दावा निराधार है ओर
 उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि फोर्ज संबद्ध उत्पादका कोई आयात नहीं है।
- प्रचित विनिमय दर जांच की अविध से अधिक है। भारत में वर्तमान आयात जांच की अविध के दौरान के आयातों से काफी अधिक है यह महत्वपूर्ण है कि प्रचित्त विनिमय दर कीमत में कटौती और कीमत में गिरावट की वास्तविक तस्वीर पेश करती है।

झ. 2. घरेलू उदयोग के विचार

- 69. घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि:
 - पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा रहा है और कीमत वृद्धि को रोक रहा है, जो पाटन के अभाव में होती।
 - घरेलू उद्योग का निष्पादन उत्पादन, घरेलू बिक्री, लाभ, निवेश पर प्रतिफल, नकद प्रवाह इत्यादि के संदर्भ में कम ह्आ है।
 - घरेलू उद्योग का निष्पादन कम होता रहा। पाटन के प्रभाव से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी के कारण गिरावट आई है, जिससे घरेलू उद्योग को पहले ही क्षिति हो चुकी है।
 - चीन में उत्पादकों/ निर्यातकों के पास अत्यधिक उत्पादन क्षमताएं हैं। वर्तमान शुल्क की समाप्ति
 के मामले में चीन से पटन में निश्चय ही वृद्धि हुई है और अंतत: इसके कारण घरेलू उद्योग की
 मात्रा और कीमत संबंधी क्षति में तेजी आई ।

- पूर्व जांचों में निर्धारित और वर्तमान जांच में अनुमानित पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण हैं और स्पष्ट तौर पर पाटन शुल्क समाप्त होने पर पाटन और उसके परिणामस्वरुप होने वाली क्षिति की संभावना को दर्शाते हैं ।
- शुल्क समाप्त होने के मामले में निर्यातक भारतीय बाजार में उनकी आउटपुट को आगे उपयोग में लाएंगे क्योंकि उनके पास पहले से ही अत्यधिक क्षमता मौजूद है और वास्तव में वे संबद्ध वस्तुओं को काफी कम कीमतों पर तीसरे देशों को बेच रहे हैं।
- बिना पाटनरोधी शुल्क के कीमत कटौती काफी महत्वपूर्ण है । घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच कीमत में काफी अंतर होने से ग्राहकों को एक बार फिर से बड़े पैमाने पर चीन से होने वाले आयात पर निर्भर होना पड़ेगा । भारत में भारी मांग और चीन के उत्पादकों की अप्रयुक्त क्षमताओं को देखते हुए चीन के उत्पादक भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर शीघ्र ही बड़े पैमाने पर आपूर्ति करने को तैयार हो जाएंगे ।
- पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को क्षिति जारी रहने और क्षिति में तेजी आने की संभावना है। यह देखते हुए कि कीमत कटौती सकारात्मक है, घरेलू उद्योग शुल्क समाप्त होने की स्थिति में कीमतों में कटौती करने अथवा खुली मात्रा में बिक्री करने को बाध्य होगा। यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कम करता है तो इससे लाभ, शामिल पूंजी के प्रतिफल, और नकदी के प्रवाह में कमी के रुप में तीव्र कीमत संबंधी क्षिति होगी। यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कम नहीं करता है तो इससे बिक्रियों की मात्रा में कमी आएगी और परिणामस्वरुप ऊपादन और क्षमता उपयोग पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ेगा।
- भारत और विश्व में विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में गिरावट आई है क्योंकि ऑटोमोबाइल उद्योग में काफी मंदी रही है । तो ऐसी परिस्थितियों में क्या वर्तमान शुल्क को समाप्त कर दिया जाए , यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग में क्षति में तेजी आएगी ।
- यहां तक यदि घरेलू उद्योग किसी अन्य स्रोत से या किसी अन्य कारणों से क्षिति का सामना कर रहा है तो प्राधिकारी को यह जांच करनी होगी कि क्या पाटन रोधी शुल्क के समाप्त होने की अवस्था में घरेलू उद्योग को क्षिति जारी रहेगी । इस प्रकार क्षिति जारी रहने के संबंध में कानूनी अपेक्षा यह है कि क्षिति को जारी रहने दिया जाए जिसका घरेलू उद्योग पहले से ही सामना कर रहा है ।
- आयातक ने परस्पर विरोधी और भ्रामक निवेदन किया है । जबिक अशोक लीलेंड अपनी ओर से किए गए विधिक अनुरोध में " बेहतर कीमतों " के लिए कह रहा है, जिसमें यह आश्चर्य व्यक्त किया गया है कि याचिकाकर्ता अपनी कीमतों में वृद्धि क्यों नहीं कर पा रहा है ।
- आयाता की मात्रा और घरेलू उद्योग की कीमतों के बीच सीधा संबंध है । चूंकि घरेलू उद्योग ने कम कीमत प्रस्तुत की है , इसलिए आयात की मात्रा में भी कमी आई है ।
- यह तथ्य कि याचिकाकर्ता के पास काफी निर्यात है , इसका यह अर्थ नहीं है कि याचिकाकर्ता पाटन कानूनों के तहत संरक्षण के लिए पात्र नहीं है । वास्तव में निर्दिष्ट प्राधिकारी को पहले यह पता चला कि ई ओ यू और एस ई जैड इकाइयां कानून के तहत संरक्षण के लिए पात्र हैं ।
- कृपया निर्दिष्ट प्राधिकारी (क) निर्यातक की क्षमता , (ख) उनकी घरेलू खपत , और (ग) वर्तमान निर्यात पर विचार करें । मात्र इससे ही पाटन रोधी शुल्क के निरसन की अवस्था में क्षिति की काफी संभावना स्पष्ट तौर पर प्रमाणित होगी ।

- नियमों में कोई ऐसी अतिरिक्त शर्त नहीं है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह निर्धारित करना पड़े कि क्या घरेलू उद्योग को मूल जांच में अस्थायी शुल्क लगाए जाने से पर्याप्त संरक्षण मिला हुआ है। घरेलू उद्योग ने अनुचित पाटन से संरक्षण की मांग की है । यह निर्यातक पर निर्भर करता है कि वह यह स्पष्ट करे कि उन्होंने पाटन का सहारा नहीं लिया है । यदि वह कीमत जिस पर वस्तुओं का भारत में निर्यात किया गया है , वह सामान्य मूल्य से कम है तो यह माना जाना चाहिए कि निर्यातक अनुचित पाटन प्रक्रिया का सहारा ले रहा है ।
- इस दलील के संबंध में कि विनिमय दर में जांच की अविध से उतार चढ़ाव आया है , यह कहना है कि पाटन से होने वाली क्षिति का निर्धारण जांच की अविध के लिए किया गया है और इसीलिए मात्र जांच की अविध में प्रचलित सूचना ही संगत है ।
- निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उसमें शामिल पूंजी पर 22 % प्रतिफल पर विचार करने की प्रथा आरंभ की है । यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी पूर्व प्रतिफल के आधार पर प्रतिफल को अपनाना चाहता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया गैर - क्षिति कीमत के निर्धारण के प्रयोजन से पूर्व में प्राप्त सर्वोत्तम आर ओ सी ई को अपना सकता है ।
- नियमों में क्षमता के उपयोग की सूचना देने का प्रावधान केवल ऐसी अवस्था में लागू है, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को उत्पादन की क्षमताओं का अनुचित उपयोग किए जाने के कारण क्षति का सामना करना पड़ा है। वर्तमान मामले में उत्पादन क्षमताओं का अनुचित उपयोग नहीं हुआ है।
- निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की ब्याज लागत, सावधि ऋणों, नकद ऋण सीमा, अल्पावधिक ऋणों, जमा राशियों और अन्य उधारयों की औचित्यता की जांच करे और सीमा शुल्क को शामिल करने के बाद कीमत कटौती और क्षति मार्जिन का निर्धारण करे।
- पाटनरोधी शुल्क को आगे पांच वर्ष की अविध के लिए बढ़ाने की जरूरत है और संशोधित पाटन और क्षिति मार्जिन को ध्यान में रखकर इस उपाय को निर्धारित मात्रा पर रखने की जरूरत है।

झ. 3. उठाए गए माले की जांच

- 70. प्राधिकारी अन्य इच्छुक पक्षकारों के तर्कों और क्षिति और कारणात्मक संबंध के दावों और इच्छुक पक्षकारों द्वारा उठाए गए मामलों पर घरेलू उद्योग के तर्कों के संबंध में उसमें उठाए गए विभिन्न मामलों को नोट करताहै। सभी मामलों को उनकी संगतता के अनुसार यहां और जांच परिणामों में उनके संगत स्थानों पर शामिल किया गया है:
 - क. जहां तक इस दलील का संबंध है कि जांच की अविध का डाटा विश्लेषण कानून के तहत एक अनिवार्य अपेक्षा नहीं है। क्षिति जांच अविध और जांच की अविध में विवरण पाटनरोधी जांच से संबंधित है। तथापि, जांच की अविध के बाद की सूचना संगत है और ऐसी स्थिति की है जहां जांच की अविध के लिए सूचना में कोई पाटन और कोई क्षिति साबित नहीं होती और किसी पाटन और क्षिति की कोई संभावना नहीं है जिससे कि इन विवरणों को ध्यान में रखकर संभावित पिरहश्य का आमकन हो सके। ऐसी स्थिति में जहां जांच की अविध के लिए सूचना यह निर्धारण करने के लिए पर्यात है कि पाटन और क्षिति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, जांच कीक अविध के उपरांत के लिए सूचना संगत नहीं है और इसीलिए उसकी अनिवार्य रूप से जांच करने की जरूरत नहीं। तथापि, प्राधिकारी ने जांच की अविध के बाद की सूचना की संगतता और आवश्यकता के अनुसार जांच की है।

- ख. जहां तक इस दलील की संबंध है कि वर्तमान आयातों की मात्रा कम है और पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि निर्णायक समीक्षा की अवस्था में कानूनी अपेक्षा पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की है। यदि वर्तमान में आयात की मात्रा कम है तो भी यह पाटनरोधी शुल्क के निरसन के मामले में पाटन और क्षति की संभावना न होने पर लागू नहीं होता।
- ग. जहां तक इस दलील का संबंध है कि घरेलू उद्योग को क्षिति घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर स्पर्धा के कारण है, तो प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इच्छुक पक्षकारों द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में यह नोट किया गया है कि अशोक लीलेंड उत्पादों का प्रमुख ग्राहक है और इसीलिए प्राधिकारी की यह प्रमाणित करने में सहायता करने की स्थिति में था कि कारणात्मक संबंध के अभाव में परस्पर स्पर्धा मौजूद है। तथापि, अशोक लीलेंड ने ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।
- घ. जहां तक अन्य घरेलू उत्पादकों के बाजार अंश में वृद्धि का संबंध है। प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि गिरती मांगों के परिदृश्य में बाजार अंश में परिवर्तन, परस्पर स्पर्धा के संबंध में स्पष्ट स्थिति प्रदान नहीं करते। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है कि उसे भारत में चीन के आयातों के कारण ही क्षति का सामना करना पड़ा है। वर्तमान जांच सभी अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देकर पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करने के लिए है।
- ड. जहां तक इच्छुक पक्षकारों द्वारा कारणात्मक संबंध न होने के दावे का संबंध है, प्राधिकारी ने यह नोट किया कि वर्तमान अविध में कारणात्मक संबंध न होना केवल ऐसी स्थिति में संगत है जहां प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षित देश में वर्तमान पाटित आयातों के कारण है। आगे के खंडों में जांच परिणाम से यह स्थापित होगा कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की अवस्था में घरेलू उद्योग को क्षिति की संभावना पर यह जांच केंद्रित है। अतः वर्तमान जांच में यह संभव है कि पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने पर घरेलू उद्योग की स्थिति में और भी गिरावट की संभावना है तदनुसार प्राधिकारी ने यह जांच की कि क्या पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त होने से घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट और पाटन के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने को बल मिलेगा।
- च. जहां तक इस दलील का संबंध है कि याचिकाकर्ता का प्रमुख ध्यान निर्यातों पर है, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता का काफी निर्यात है लेकिन याचिकाकर्ता ने घरेलू बाजार में भी अग्रणी स्थित बनकर रखी है। यह प्रमाणित नहीं हो पाया कि घरेलू उद्योग उत्पाद की आपूर्ति नहीं कर पाया। इसके अलावा, डाटा यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को समग्र क्षमता उपयोग में काफी गिरावट आई है, यद्यपि इसने अपने निर्यात निष्पादन को बनाए रखा है। जिसमें यह दर्शाया गया है घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में अपने निर्यातों से समझौता किए बिना अपनी पर्याप्त बिक्रियां कर सकता था।
- छ. जहां तक इच्छुक पक्षकारों की इस दलील का संबंध है कि वर्तमान विनिमय दर को सभी गणनाओं में उपयोग में लाया जाए, प्राधिकारी ने यह नोट किया कि जांच की अविध की औसत विनिमय दर उस अविध के दौरान लागत और कीमतों की एक उचित तुलना के लिए क्षिति जांच में विभिन्न मूल्यों के अंतरण के लिए की जाती है। लागत और कीमतों के परिवर्तन के लिए वर्तमान विनिमय दर को अपनाने से इस तुलना के लिए इन आंकड़ों में तोड़ मरोड़ होगा और इसीलिए उपयुक्त नहीं है।

71. इच्छुक पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य सभी मामले इस प्रकटीकरण में संगत खंडों में शामिल कर लिए गए हैं ।

झ. 4. घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पक्षकारों की प्रकटीकरण के उपरांत टिप्पणियां

- 72. निर्यातकों/आयातकों और अन्य इच्छुक पक्षकारों ने अपनी प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों में यह भी कहा है कि :
 - सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (5) के अनुसार उचित विधिक स्थिति यह है कि पाटन रोधी शुल्क को निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में केवल तभी जारी रखा जाए जब (क) पाटन और क्षिति जारी हो, अथवा (ख) यदि पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है तो पाटन और क्षिति की पुनरावृति होने की संभावना है । पाटनरोधी शुल्क को वर्तमान मामले में केवल तभी जारी रखा जा सकता है जब उपरोक्त विधिक मानक को पूरा कर लिया गया हो ।
 - विभिन्न उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा है जो अशोक लीलेंड द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट है। यह तर्क दिया गया है कि भारत में अन्य उत्पादक वास्तव में बहुत ही कम कीमतों पर संबद्ध उत्पाद प्रदान कर रहे हैं और अशोक लीलेंड ने वास्तव में घरेलू उद्योग के अलावा भारतीय उत्पादकों से काफी मात्रा में और याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादक द्वारा पेश की गई कीमतों से काफी कम कीमतों पर खरीद की गई है। अत: अन्य भारतीय उत्पादक आयात की बजाय घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी कटौती कर रहे हैं और इसीलिए घरेलू उद्योग को क्षिति होने का कारण आपस में काफी प्रतिस्पर्धा का होना है न कि संबद्ध उत्पाद का आयात होना है। अन्य भारतीय उत्पादकों ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर काफी हद तक कब्जा कर लिया है।
 - घरेलू उद्योग की बिक्री में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी के कारण गिरावट होने और आपस में काफी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, जैसा कि घरेलू उद्योग ने स्वीकार भी किया है और प्राधिकारी द्वारा उचित पाया है, यह कहना सही नहीं होगा कि घरेलू उद्योग को क्षिति का कारण आयात का होना है जबिक जांच की अविध के दौरान मामूली आयात (केवल 2 प्रतिशत की मांग में) हुआ है । घरेलू उद्योग ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि क्षिति के कारण के लिए अन्य कारक उत्तदायी हैं । घरेलू उद्योग को क्षिति होने के लिए आयात को जिम्मेदार ठहराने से घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार या बदलाव नहीं आएगा ।
 - यह निर्विवाद तथ्य है कि फ्रंट एक्सल बीम के लिए घरेलू उद्योग का हिस्सा घटा है क्योंकि भारतीय उत्पादक इस बाजार पर तेजी से कब्जा कर रहे हैं । इसके अलावा, यह भी निर्विवाद तथ्य है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी और अन्य भारतीय उत्पादकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद स्टीयरिंग नॅकॅल के लिए घरेलू उद्योग के बाजारी हिस्से में सुधार आया है । ये पहलु यह दर्शाने के लिए संगत हैं कि घरेलू उद्योग फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयरिंग नॅकॅल, दोनों के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है न कि संबद्ध वस्तु के आयात का सामना कर रहा है , जो वास्तव में जांच की अवधि के दौरान भारतीय मांग का मात्र 2 % रहा है । वास्तव में यदि आयातों का बाजार में हिस्सा गिरती मांग की स्थिति में गिरता तो पाटन रोधी शुल्क जारी रहने के लिए इसे मान लिया जाता । तथापि जब मांग गिरने की स्थिति में आयात का बाजार में हिस्सा कम हो रहा है तो यह दर्शाता है कि आयात भारतीय बाजार में उनके लिए स्थान नहीं बना पा रहा और भारतीय उत्पादकों का सामना करने में सक्षम नहीं है । अतः बाजार में हिस्सा एक महत्वपूर्ण मानदंड होता है जिसे क्षति विश्लेषण करते समय नजर अंदाज नहीं किया जा सकता ।

- कीमतों में कटौती और कम बिक्री विश्लेषण के प्रयोजन से निर्दिष्ट प्राधिकारी को सहयोगी निर्यातकों अथवा अशोक लीलेंड द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर लदान कीमत अपनानी चाहिए न कि डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के आधार पर ।
- यह तर्क कि घरेलू उद्योग कथित पाटित आयातों के कारण से अपनी कीमतों को बढ़ाने में समर्थ नहीं है,
 केवल तभी मान्य होगा यदि घरेलू उद्योग और संबद्ध देश से निर्यातक एक ही क्रेता से खरीद कर रहे हों।
 इस मामले में संबद्ध देश से सहयोगी निर्यातक भारत मे केवल एक ही क्रेता, अशोक लीलेंड को आपूर्ति कर रहे हैं।
- कीमतों में मंदी/ कीमत गिरने के लिए केवल एक ही कारण है और वह है घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा का होना और इसे क्षति का विश्लेषण करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए । यह भी तर्क दिया गया है कि आयात की मात्रा इतनी कम है कि इसके कारण कीमत में मंदी अथवा गिरावट नहीं हो सकती ।
- घरेलू उद्योग के कई क्षिति मानदंड यह दर्शाते हैं कि इसमें सुधार हुआ है और घरेलू उद्योग को, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी और परस्पर कड़ी स्पर्धा होने के कारण मांग में गिरावट आने के बावजूद लाभ हुआ है । इसके अलावा इसमें लगी पूंजी पर घरेलू उद्योग को प्रतिलाभ भी क्षिति विश्लेषण अविध के दौरान अच्दा रहा है । घरेलू उद्योग 2011-12 तक अत्यधिक लाभ अर्जित कर रहा था और उसके बाद की अविध में इसके लाभ में धीरे धीरे गिरावट आने लगी । इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि घरेलू उद्योग स्वयं ही मुनाफे में इस कमी से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी के कारण मांग में गिरावट के लिए जिम्मेदार है । परस्पर प्रतिस्पर्धा भी 2011-12 के बाद मुनाफे में कमी होने का कारण है । अतः 2011-12 के साथ जांच की अविध के लिए मुनाफे की त्लना करना असंगत होगा ।
- यदि पाटन रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग को कोई क्षिति अथवा पाटन की पुनरावृति होने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती । इस संबंघ में जांच की अविध के दौरान स्टीयिरंग नॅकॅल का आयात वास्तव में घरेलू उद्योग की गैर क्षिति कीमतों से अधिक कीमतों पर हुआ है । अतः यह कहना उचित नहीं है कि संबद्ध उत्पाद भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहा है जबिक वास्तविकता बिल्कुल विपरीत है ।
- इच्छुक पक्षकारों द्वारा किए गए जांच की अविध के उपरांत के विश्लेषण के अनुसार घरेलू उद्योग के
 मुनाफे में जांच की अविधि के उपरांत काफी सुधार आया है; सभी आर्थिक मानदंडों पर इसके निष्पादन
 में भी सुधार आया है। घरेलू उद्योग का कम मांग के कारण क्षति होने का दावा भी समाप्त हो गया है
 क्योंकि संबद्ध उत्पाद के लिए मांग में, जांच की अविधि के उपरांत मीडियम और हैवी वाणिज्यिक वाहनों
 की बेहतर मांग होने के कारण काफी वृद्धि हुई है।
- आयातो से घरेलू उद्योग को कोई क्षिति नहीं हुई और इस बात की प्रबल संभावना है कि आयात पाटित कीमत पर न हों और यदि पाटन रोधी शुल्क समाप्त कर दिए जाए तो उनके कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षिति न हो ।
- प्राधिकारी ने स्टीयरिंग नॅकॅल और इसकी कीमतों के लिए आयातों की मात्रा का आकलन करने में चूक की है । प्रतिवादियों के विश्लेषण के अनुसार स्टीयरिंग नॅकॅल की आयात मात्रा जांच की अविध के उपरांत कम है जबिक स्टीयरिंग नॅकॅल के आयात का लदान मूल्य निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किए गए विश्लेषण की तुलना में काफी अधिक है । इसे देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुराध है कि वह संबद्ध उत्पाद के आयातों की मात्रा और कीमत के लिए जांच की अविध के बाद के आंकड़ों की प्न: जांच करें ।

- याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए विवरण से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता भारत और भारत से बाहर मीडियम और हैवी कॉमर्शियल वाहनों की मांग में बढौत्तरी को दिखा रहा है । याचिकाकर्ता के वित्तीय निष्पादन में भी काफी स्धर आया है ।
- वर्तमान निर्णायक समीक्षा को समाप्त किया जाए क्योंकि कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षिति नहीं हुई है और यदि पाटनरोधी शुल्क को हटा लिया जाता है तो पाटन और क्षिति न तो जारी रहेगी और न ही इसकी कोई संभावना नहीं है ।
- उपरोक्त को ध्यान में दिए बिना यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी वर्तमान मामले में पाटन रोधी शुल्क के जारी रखने का निर्णय लेते हैं तो प्राधिकारी इस निर्णायक समीक्षा में परिकलित कम पाटन मार्जिन अथवा क्षिति मार्जिन के आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाएं न कि मूल जांच के समय परिकलित दर पर ।
- 73. घरेलू उद्योग ने प्रकटीकरण के उपरांत की अपनी टिप्पणियों में अन्य के साथ-साथ यह कहा है :
- क्) मूल जांच में यह दर्शाया गया है कि चीन के आयात का बाजार में हिस्सा फ्रंट एक्सल बीम के मामले में 2006-07 में 0 % से बढ़कर जांच की अविध के दौरान 23.78 % और जांच की अविध के उपरांत 61.80 % हो गया है । इसी प्रकार स्टीयिरंग नॅकॅल का बाजार में हिस्सा जांच की अविध और जांच के उपरांत की अविध में क्रमश: 2006-07 में 0 % से बढ़कर 17.47% और 19.98 % हो गया । घरेलू उद्योग ने बहुत ही तीव्र गित से उसी अनुपात में अपना बाजार का हिस्सा खो दिया और घरेलू उद्योग के मुनाफे में जांच अविध के दौरान तीव्र गिरावट आई । वर्तमान मामले में काफी कीमत कटौती हुई है जबिक उत्पादों की मांग में वर्तमान क्षति अविध के दौरान गिरावट आई है । अत: पाटन रोधी शुल्कों को यदि हटा लिया जाता है तो घरेलू उद्योग को काफी प्रतिकूल मात्रा और कीमत संबंधी प्रभावों का सामना करना पड़ेगा ।
 - यद्यपि उत्पादों का उत्पादन और बिक्री संख्याओं में होती है लेकिन विभिन्न प्रकार के विचाराधीन उत्पादों के लिए प्राधिकारी ने मूल जांचों के समय यह विचार किया कि विभिन्न प्रकार के विचाराधीन उत्पादों को औसत भार के आधार पर व्यक्त करना उचित होगा । यद्यपि यह उचित होगा और वास्तव में विभिन्न प्रकार के उत्पादों को भार के आधार पर व्यक्त करना आवश्यक/अनिवार्य होगा और भारत के आधार पर कीमत का विश्लेषण करना अब बिल्कुल ही भ्रामक होगा । अत: अब पाटन मार्जिन और क्षित मार्जिन का निर्धारण तुलना से पूर्व आंकडों को संख्या में परिवर्तित करने के बाद किया जाएगा। यह इस कारण से है कि इस जांच में चीन के उत्पादकों ने दो प्रकार के स्टीयरिंग नॅक्ल और दो प्रकार के फ्रंट एक्सल बीम बेचे हैं । यद्यपि याचिकाकर्ता ने दोनों प्रकार के फ्रंट एक्सल बीम बेचे हैं लेकिन याचिकाकर्ता ने एफ ए 99 प्रकार स्टीयरिंग नॅकल फोर्ज रूप में अथवा मशीनीकृत रूप में आपूर्ति नहीं की है । इसके अलावा एफ ए 99 नकल का कच्ची सामग्री और तैयार सामग्रीका भार काफी अलग है । यहां तक कि कच्ची सामग्री की खपत में नॅक्ल के प्रकार के आधार पर काफी भिन्नता है ।
 - चूंकि उत्पादन प्रक्रिया में कोई अक्षमता नहीं है, इसलिए एनआईपी का निर्धारण उत्पादन की वास्तविक लागत को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ऊपरी लागतों के प्रभाव को वर्तमान जांच की अविध में उत्पादन को कम करने के लिए समायोजित किया जाए ।
 - वास्तिविक प्रकटीकरण के अभाव में प्राधिकारी ने इसमें लगी पूंजी का निर्धारण कैसे कर लिया और याचिकाकर्ता
 एन आई पी के निर्धारण के लिए पूंजी के संबंध में शामिल किए गए आंकडों की उपयुक्तता पर टिप्पणी देने
 की स्थिति में नहीं है । तथापि, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्राधिकारी ने एन आई पी के निर्धारण के लिए बहुत
 ही कम स्तर पर म्नाफे को स्वीकार किया है ।
 - प्राधिकारी ने एस जी ए व्यय में काफी कटौती की है और ऐसी राशि स्वीकार की है जो याचिकाकर्ता द्वारा यथास्चित एस जी ए की राशि से काफी कम है ।

- यह स्पष्ट है कि प्राधिकारी ने कुछ ऐसे व्यय निकाल दिए हैं जो प्रकटीकरण विवरण में प्रकट नहीं किए गए हैं। अब निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास एन आई पी के निर्धारण के लिए विशेष नियम है। यह काफी अनुचित होगा कि नियमों से हटकर कार्य किया जाए और कुछ व्ययों को निकाल दिया जाए जिनके निकालने के लिए नियमों में विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। चीन जन गण. से आयात पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी पाटित मूल्यों पर होता रहा है। आयातों की मात्रा में काफी हद तक गिरावट आई है जो शुल्क लगाए जाने के कारण है। कम मात्रा में आयात होने का स्पष्ट प्रमाण यह है कि वर्तमान आयात की मात्रा और मूल्य पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की अवस्था में संभव नहीं है और चीन के उत्पादकों द्वारा पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की अवस्था में संभव नहीं है और चीन के उत्पादकों द्वारा पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की अवस्था में संभव नहीं है और चीन के उत्पादकों द्वारा पाटनरोधी शुल्क हटाए
- इस तरह की मांग में गिरावट की स्थिति में और क्षिति की जांच अविध के दौरान आयात में गिरावट के कारण अधिक आयात मूल्य अथवा कम बाजार अंश पाटनरोधी शुल्क को हटाने की अवस्था में घरेलू उद्योग की स्थिति के लिए पर्याप्त और उपयुक्त सूचक नहीं है।
- यद्यपि पाटित आयातों के लदान मूल्य में क्षिति अविध के दौरान वृद्धि हुई है लेकिन समग्र क्षिति जांच अविध के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से काफी कम रही है ।
- जांच की अविध के दौरान घरेलू उद्योग का निष्पादन मात्रा और मूल्य संबंधी मानकों, दोनों के संदर्भ में प्रितकूल रहा है । अतः घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच पर्याप्त रूप से मूल्य संबंधी अंतर को देखते हुए पाटनरोधी शुल्क को हटाने से घरेलू उद्योग को क्षिति में तेजी आएगी । ऐसा कोई कारण नहीं है कि अशोक लीलेंड जैसे बड़े ग्राहक ने घरेलू उद्योग को इतनी अधिक कीमत और इतनी मात्रा में आपूर्ति के आदेश कैसे दिए जबिक वे उत्पाद को काफी कम कीमतों पर प्राप्त कर सकते थे ।
- संबद्ध देश से आयातों की मात्रा में पाटनरोधी शुलक के कारण काफी कमी आई है । इतनी कम मात्रा से शुल्कों
 हटाए जाने की अवस्था में पाटन मार्जिन अथवा क्षिति मार्जिन को दर्शाया नहीं जा सकेगा । ऐसे मार्जिन के
 आधार पर पाटनरोधी शुल्क से पाटन में कमी और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षिति से निपटा नहीं जा
 सकेगा।
- निर्णायक समीक्षा का उद्देश्य पाटनरोधी शुल्क को हटाने की अवस्था में प्रकट होने वाली स्थिति पर विचार करना है और इसीलिए वर्तमान कीमतें ऐसी स्थिति को नहीं दर्शाती । यहां तक कि चीन के निर्यातक और भारतीय आयातक/उपभोक्ता ने जांच की समूची अविध के दौरान यह दलील दी है कि वर्तमान जांच की अविध के दौरान आयातों की मात्रा नगण्य रही है ।पाटनरोधी शुल्क की मात्रा नगण्य मात्रा के आधार पर नहीं हो सकती।
- मूल जांच में निर्धारित मार्जिन के आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाना अधिक उपयुक्त होगा और इससे पाटन की समस्या से निपटा जा सकेगा ।
- निर्यातकों और उत्पादकों को कम पाटनरोधी शुल्क का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे पाटन में तेजी आएगी ।
- यह निर्धारण करने के लिए नियमों में प्रावधान है कि क्या पाटनरोधी शुलकों को आगे बढ़ाना चाहिए । यह इस निर्णय पर निर्भर करता है कि शुलकों को आगे बढ़ाया जाए अथवा नहीं । यद्यपि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्कों की मात्रा में संशोधन करने के लिए इस अवसर का भी उपयोग किया है लेकिन ऐसा अवसर उस समय उपलब्ध नहीं होता जब मामले का आधार पाटन और क्षित की संभावना हो । वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क का विस्तार संभावना पर आधारित है और इसीलिए आयातों की मात्रा और मूल्य पाटनरोधी शुलक की मात्रा के संबंध में निर्णय लेने के लिए कोई मापदंड नहीं होना चाहिए ।

- कनाडा, यूएस और यूरोप जैसे तीनों देशों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार यह निर्णय लिया जाना है
 कि क्या पाटनरोधी शुल्कों को बढ़ाया जाए अथवा नहीं। ये देश पाटनरोधी शुल्कों की मात्रा को परिवर्तित नहीं
 करते । यद्यिप, जांच की अविधि में काफी आयात होते हैं और पाटन मार्जिन और क्षिति मार्जिन वर्तमान
 पाटनरोधी शुलकों से काफी कम होते हैं ।
- पूर्व के उदाहरण भी उपलब्ध हैं जहां पर कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उतनी ही मात्रा में शुल्क बढ़ाया है जितनी कि उनकी मूल जांचों में सिफारिश की गई है जबिक समीक्षा मामलों में पाटन मार्जिन मूल जांचों में निर्धारित किए गए मार्जिन से कम रहा है । अत: शुल्क की मात्रा उतनी ही रहनी चाहिए जितनी कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में सिफारिश की गई है ।
- श्ल्क को यू एस डॉलर/िकग्रा. में व्यक्त िकया जाना जारी रखा जाए ।
- 74. पक्षकारों की प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों में उठाए गए मामले अंतिम जांच में संबंधित खंडों में शामिल कर लिए गए हैं और इसीलिए अब इनका पुन: उल्लेख करने की जरूरत नहीं है ।

ञ. वर्तमान क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

- 75. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में पारित आयातों की मात्रा और मूल्यों पर पारित आयातों के प्रभाव; (ख) ऐसी वस्तुओं के घरेलु उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव, दोनों की एक उद्देश्यपरक जांच का प्रावधान है। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह जांच करनी अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में सापेक्ष रूप में या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के मूल्य संबंधी प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह जांच करनी है कि क्या भारत में समान उत्पाद के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों से भारी कीमत कटौती हुई है अथवा ऐसे आयातों के प्रभाव से भारी मात्रा में कीमतें प्रभावित हुई है अथवा कीमत में वृद्धि होने से रुकावट हुई है, जो अन्यथा भारी मात्रा में होती।
- 76. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए सभी संबद्ध आर्थिक कारक और संकेतक जिनका उद्योग की स्थिति के संबंध है, इनमें बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार अंश, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, वस्तु सूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी या निवेश में वृद्धि की क्षमता में वास्तविक और संभावित गिरावट शामिल है, पर नियमावली के

अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है। उपरोक्तानुसार घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक मानकों की निम्नलिखित अनुसार जांच की गई है :

ञ. 1. पाटित आयातों की मात्रा संबंधी प्रभाव

(क) आयात मात्रा एवं मार्किट शेयर

- 77. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना है कि क्या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में पाटित आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रदत्त
 - लेन- देन वार आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देश और अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा की जांच की है।
- 78. प्राधिकारी ने यह नोट किया कि डी जी सी आई एंड एस संबद्ध वस्तुओं के आयातों की सूचना संख्या में देता है। चीन के सहयोगी निर्यातक द्वारा दाखिल प्रश्नावली उत्तर के अनुसार केवल मशीनीकृत उत्पाद ही इस अविध के दौरान भारत को निर्यात किए गए हैं। अत: आयात भार को मशीनीकृत उत्पादों की इकाई

भार को ध्यान में रखकर परिवर्तित किया गया है जैसा कि निर्यातकों ने सूचित किया है। तदनुसार, संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा इस प्रकार है :

आयातों की मात्रा	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पी ओ आई
फ्रंट एक्सल बीम					
संबद्घ देश-चीन	मी. टन	2,143	2,143	1,417	279
अन्य देश	मी. टन	-	-	-	-
कुल आयात	मी. टन	2,143	2,143	1,417	279
स्टीयरिंग नॅकॅल	मी. टन				
संबद्ध देश- चीन	मी. टन	669	1,089	790	181
अन्य देश	मी. टन	-	-	-	-
कुल आयात	मी. टन	669	1,089	790	181

79. डी जी सी आई एंड एस आयात डाटा की जब सहयोगी निर्यातकों के निर्यात डाटा से तुलना की गई तो वह संबद्ध देश से निर्यात और भारत में आयात के बीच समय के अंतर के कारण कुछ मात्राओं में अंतर दर्शाता है। अतः डी जी सी आई एंड एस डाटा को इस जांच में स्वीकार किया गया है। डाटा में यह उल्लेख है कि संबद्ध वस्तुएं केवल चीन से आयात की जा रही हैं और शुल्क लगाने के बाद जांच अविध के दौरान पाटनरोधी के बाद आयात में काफी गिरावट हुई है।

(ख) मांग/ स्पष्ट खपत का मूल्यांकन

80. भारत में उत्पाद की स्पष्ट खपत या मांग का आकलन भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के आधार पर किया गया है। उत्पादकों की अपनी अनुमानित खपत पर भी विचार किया गया है। तदन्सार, घरेलू बाजार में संबद्ध वस्त्ओं की अन्मानित मांग इस प्रकार है :

उत्पाद - फ्रंट एक्सल बीम	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पी ओ आई
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	20,191	19,175	11,531	9,233
संबद्घ देश - चीन	मी. टन	2,143	2,143	1,417	279
अन्य भारतीय उत्पादों की बिक्री	मी. टन	3,338	3,020	3,704	2,780
मांग/ खपत, कैप्टिव को शामिल करके	मी. टन	25,672	24,338	16,652	12,292
कैप्टिव की मांग खपत निकालकर	मी. टन	100	95	65	48
कैप्टिव की अनुमानित खपत	मी. टन	5,901	6,065	4,809	6,199
मांग/ खपत, कैप्टिव को शामिल करके	मी. टन	31,573	30,403	21,461	18,491
	प्रवृति	100	118	84	72
उत्पाद - स्टीयरिंग नॅकॅल	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	718	1,048	1,285	1,250
संबद्घ देश - चीन	मी. टन	669	1,089	790	181
अन्य उत्पादों की बिक्री	मी. टन	5,904	5,873	4,257	3,333
मांग/ खपत, कैप्टिव को शामिल करके	मी. टन	7,291	8,010	6,331	4,764
कैप्टिव की मांग खपत निकालकर	मी. टन	100	110	87	65
कैप्टिव की अनुमानित खपत	मी. टन	5,764	6,634	4,461	3,902
मांग/ खपत, कैप्टिव को शामिल करके	मी. टन	13,055	14,644	10,792	8,666
	प्रवृति	100	112	83	66

81. उपरोक्त आंकडों से यह पता चलता है कि क्षिति अविध के दौरान दोनों उत्पादों की मांग में उल्लेखनीय गिरावट आई है। याचिकादाता ने यह बताया है कि मांग में यह गिरावट भारत में ऑटोमोबाईल उद्योग की खपत पेटर्न में गिरावट आने के कारण आई है। याचिकादाता ने आगे यह भी बताया है कि सामान्य बृहत-आर्थिक कारकों और ऑटोमोबाईल उद्योग में विशेष मंदी आने के कारण विश्व भर में भारी और मध्यम किस्म के वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई है जिसके फलस्वरूप विचाराधीन उत्पादों की मांग में गिरवाट आई है। इन परिस्थितियों में यदि मौजूदा शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है, तो उससे घरेलू उद्योग को अत्यधिक क्षिति होगी। इस संबंध में विगत 4 वर्षों में वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन और बिक्री के आंकडे नीचे दिए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
स्थानीय बिक्री	संख्या	323,059	348,701	268,689	200,627
निर्यात बिक्री	संख्या	28,349	27,917	19,524	28,813
कुल बिक्री	संख्या	351,408	376,618	288,213	229,440
उत्पाद न	संख्या	345,818	383,277	280,677	221,626

स्रोत : एसआईएम (सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव मेन्युफेक्चरर्स)

82. उपरोक्त आंकडों से यह पता चलता है कि भारत में वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन और बिक्री में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इसलिए संबंधित माल की मांग में गिरावट आने से ऑटोमोबाईल्स की प्रमुख उपयोगी मदों की मांग में भी गिरावट आई है। प्रतिवादी निर्यातकों का यह तर्क है कि यदि घरेलू उद्योग को ऐसी कोई क्षति हुई है, तो उसका कारण इस अवधि के दौरान ऑटोमोबाईल उद्योग में मांग की ऐसी गिरावट होना और मंदी आना है और उसका कारण चीन से आयात होना नहीं है जो कि अपेक्षाकृत बहुत कम है। प्राधिकारी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि ऑटो-उद्योग की मांग में कमी आना एक विश्वव्यापी घटना है और यदि घरेलू उत्पादकों को कुछ क्षति हुई है तो उसका कारण मांग की स्थिति है। लेकिन विश्व की मांग में गिरावट आने को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देश से पाटित आयात और बढने वाले संभावित आयात से पडने वाले प्रभाव को दूर किए जाने की आवश्यकता है और मांग में गिरावट आने के लिए पाटित आयात को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए।

(ग) मांग में बाजार का हिस्सा

83. घरेलू बिक्री और बाजार के हिस्से पर पाटित आयात के प्रभावों की जांच की गई है, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है :

फ्रंट एक्सिल बीम	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि		
मांग में बाजार का हिस्सा - केप्टिव मांग को छोड कर							
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	79%	79%	69%	75%		
संबद्घ देश - चीन	%	8%	9%	9%	2%		
अन्य उत्पादक	%	13%	12%	22%	23%		
मांग में बाजार का हिस्सा - केप्टिव मांग सहित							
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	64%	63%	54%	50%		

संबद्घ देश - चीन	%	7%	7%	7%	2%			
अन्य उत्पादक	%	29%	30%	40%	49%			
स्टीयरिंग नुक्कल्स	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि			
मांग में बाजार का हिस्सा - केप्टिव मांग को	छोड कर							
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	10%	13%	20%	26%			
संबद्घ देश - चीन	%	9%	14%	12%	4%			
अन्य उत्पादक	%	81%	73%	67%	70%			
मांग में बाजार का हिस्सा - केप्टिव मांग सी	मांग में बाजार का हिस्सा - केप्टिव मांग सहित							
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	6%	7%	12%	14%			
संबद्घ देश - चीन	%	5%	7%	7%	2%			
अन्य उत्पादक	%	89%	85%	81%	83%			

84. यह नोट किया गया है कि क्षिति अविध के दौरान संबंधित माल की मांग में गिरावट आई है। जहां तक एफएबी का संबंध है, याचिकादाता के बाजार के हिस्से और आयात में गिरावट आई है, जबिक अन्य उत्पादकों के हिस्से में वृद्धि हुई है, हालांकि अन्य उत्पादकों की कुल बिक्री में गिरावट आई है। लेकिन स्टीयिरंग नुक्कल्स के मामले में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में जांच अविध की तुलना में आधार वर्ष में वृद्धि हुई है, जब कि अन्य के हिस्सों में गिरावट आई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मांग में गिरावट आने की ऐसी विशेष स्थिति में तथा क्षिति की जांच करने की अविध के दौरान हुए छुटपुट आयात को ध्यान में रखते हुए बाजार के हिस्से को, उद्योग की स्थिति का एक उपयुक्त सूचक नहीं माना जा सकता है।

85. इच्छुक पक्षकारों ने प्रकटीकरण के उपरांत के अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि घरेलू बाजार में आपस में व्यापक प्रतिस्पर्धा है और अन्य घरेलू उत्पादक वस्तुओं की बिक्री प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर कर रही है जिससे याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग के बाजार के अंश पर कब्जा हुआ है। तथापि, यह तर्क उपरोक्त आंकड़ों से प्रकट नहीं हुआ है। फंट एक्सल बीम के मामले में अन्य उत्पादकों के बाजार अंश में कैप्टिव खपत पर विचार किए बिना वृद्धि की गई है लेकिन यह वृद्धि चीन से हुए आयातों की लागत के कारण है। याचिकाकर्ता का घरेलू बाजार में वाणिज्यिक बिक्रियों का 75 प्रतिशत हिस्सा है। स्टीयरिंग नॅकॅल के मामले में अन्य उत्पादकों ने बाजार अंश में काफी नुकसान उठाया है और याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग ने वास्तव में अपने हिस्से में वृद्धि की है। अतः इच्छुक पक्षकारों के ये तर्क कि अन्य उत्पादकों के साथ परस्पर प्रतिस्पर्धा और मूल्य में कटौती क्षति, यदि काई हो, का मुख्य कारण है, यह स्वीकार्य नहीं है। 86. इच्छुक पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिए गए हैं कि यदि आयातों के बाजार अंश में मांग में गिरावट की स्थिति में वृद्धि हो रही है तो पाटनरोधी शुल्क को जारी रखा जाए। तथापि, जब आयातों का बाजार अंश गिरती मांग की स्थिति में कम हो रहा हो तो यह दर्शाता है कि आयात भारतीय बाजार में उनके लिए कोई स्थान नहीं बना पा रहा है और भारतीय उत्पादकों से निपटने में सक्षम नहीं है। अतः बाजार अंश एक महत्वपूर्ण मापदंड है जिसे क्षति विश्लेषण में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयातों की मात्रा और पाटित आयातों के बाजार अंश में गिरावट यह दर्शाती है कि लगाया गया पाटनरोधी शुल्क पाटित आयातों के प्रभावों की जांच करने में प्रभावी रहा है और यदि शुल्कों को हटा दिया जाता है तो इससे घरेलू उद्योग पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ सकता है।

ट 2. घरेलू उद्योग पर पाटित आयात के कीमत संबंधी प्रभाव

87. कीमतों पर पाटित आयातों के पड़ने वाले प्रभाव के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस तथ्य पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या भारत में इस प्रकार के उत्पादों की कीमतों की तुलना में पाटित आयात से कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है अथवा क्या ऐसे आयातों का अन्यथा प्रभाव पड़ा है, जिससे कीमतों में काफी कमी आई है या कीमतों में भारी वृद्धि नहीं हो पाई है, जबिक यदि ऐसा आयात नहीं होता तो उससे कीमतों में काफी वृद्धि हो सकती थी। इसलिए हालांकि आयात की मात्रा बहुत कम है, लेकिन फिर भी पाटित आयातों से कीमत के कम होने और बिक्री नहीं होने, दोनों प्रकार के प्रभावों की जांच की गई है।

88. घरेलू उद्योग ने प्रकटीकरण के उपरांत के अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि कीमत संबंधी सभी तुलना खंडों में की जाए । इसका कारण यह है कि वस्तुएं खंडों में बेची जाती हैं और भार के संदर्भ में औसत तुलना के कारण इसके परिणामों में परिवर्तन आ रहा है क्योंकि घरेलू उद्योग ने इस प्रकार के उत्पादों का उत्पादन और बिक्री नहीं की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पूर्व जांच और वर्तमान जांच में पाटन और क्षति का विश्लेषण घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार भार के संदर्भ में किया गया था । अतः तुलना का आधार जांच की इस अवस्था में केवल इस आधार पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता कि इसे विभिन्न कारकों के कारण कुछेक प्रकार के उत्पादों के संबंध में परिणामों में परिवर्तन हो रहा है ।

89. निर्यातकों ने प्रकटीकरण के उपरांत के अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि प्राधिकारी को कीमत विश्लेषण के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार लदान मूल्य की बजाए प्रतिवादी निर्यातकों के लदान मूल्य को अपनाना चाहिए। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कीमत के प्रभाव का विश्लेषण आयातक देश के बाजार में पाटित आयातों की मात्रा और मूल्य के आधार पर किया जाता है न कि जांच की अविध के दौरान निर्यातक देश से होने वाले पाटित निर्यातों के आधार पर । अत: यह विश्लेषण करना अनिवार्य है कि इस जांच अविध के दौरान आयातों की कुल मात्रा और मूल्यों का विश्लेषण किया जाए । तद्नुसार इस विश्लेषण के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों को अपनाया गया है ।

(क) कीमत में कटौती

90. पाटित आयातों से कीमत में कटौती होने के प्रभाव की जांच करने के प्रयोजन से दोनों उत्पादों के लिए घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली की तुलना डीजीसीआईएंडएस के आंकडों के अनुसार समदृशी उत्पादों के आयात के पहुंच मूल्यों के साथ की गई है। घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दी जा रही छूट, डिसकाउंट्स और कमीशन और उसके द्वारा अदा किए जा रहे उत्पाद शुल्क को छोड दिया गया है। चीन से केवल यंत्रित उत्पादों का आयात किया गया है। इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित और बेचे गए यंत्रित उत्पादों की बिक्री कीमत को ही कीमत कम होने के लिए ध्यान में रखा गया है। संबद्ध देश से पाटित आयातों से कीमत के कम होने के प्रभावों की जांच की गई है, जो कि निम्नान्सार है:

फ्रंट एक्सिल बीम - यंत्रित	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
एडीडी के बिना पहंच कीमत	रुपए/किलोग्राम	94.80	106.36	116.01	118.44
डीआई की निबल बिक्री	रुपए/किलोग्राम	¥**	***	***	***
एडीडी के बिना कीमत में कमी होना	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
कीमत में कमी होना	सीमा/रैंज	25-35%	15-25%	10-20%	10-20%
एडीडी सहित पहुंच कीमत	रुपए/किलोग्राम	110.96	123.21	135.14	139.74
कीमत में कमी होना	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	(***)
एडीडी सहित पहुंच कीमत	सीमा/रेंज	15-25%	5-15%	0-10%	(0-10)%

स्टीयरिंग नुक्लस - यंत्रित

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
एडीडी के बिना पहुंच कीमत	रुपए/किलोग्राम	140.29	148.24	163.66	185.79
डीआई की निबल बिक्री	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
एडीडी के बिना कीमत में कमी होना	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
कीमत में कमी होना	सीमा/रैंज	20-30%	10-20%	10-20%	5-15%
एडीडी सहित पहुंच कीमत	रुपए/किलोग्राम	169.84	179.05	198.64	224.73
एडीडी के बिना पहुंच कीमत	रुपए/किलोग्राम	***	(***)	(***)	(***)
कीमत में कमी होना	सीमा/रेंज	5-10%	(0-10)%	(0-10)%	(5-15)%

91. उपरोक्त आंकडों से यह पता चलता है कि हालांकि क्षति की जांच अविध के दौरान पाटित आयातों की पहुंच कीमतों में वृद्धि हुई है, फिर भी क्षति की समस्त जांच अविध के दौरान इनकी कीमतें, घरेलू उद्योग की कीमतों से काफी नीचे रही हैं। समग्र कीमत और प्रतिशत दोनों ही रूप में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है। शुल्क दत्त पहुंच मूल्यों में कीमत में कटौती नकारात्मक रही है। इससे यह पता चलता है कि जबकि पाटन-रोधी शुल्क अदा करने वाले आयातों पर कीमत कटौती का प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन शुल्क अदा किए बिना किए गए आयात, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों से निरंतर काफी कम रहे हैं। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह जांच करना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या ऐसे आयात की कीमतों से घरेलू कीमतें पहले से ही मंद है जिसके फलस्वरूप शुल्क दत्त आयातों की कीमतों पर नकारात्मक कम प्रभाव पड़ा है।

92. इच्छुक पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि यद्पि फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयरिंग नॅकॅल,दोनों के लिए आयातों की कीमतों में वृद्धि हो रही है, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि घरेलू उद्योग कम मात्रा और अधिक आयात मूल्य के बावजूद इसकी कीमतों में वृद्धि नहीं कर पाया । घरेलू उद्योग की यह दलील है कि यद्यपि क्रेता, अशोक लीलेंड बेहतर कीमतों के लिए कह रहा है लेकिन उस निर्यातक की ओर से यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपनी कीमतों में वृद्धि क्यों हुई थी । इच्छुक पक्षकारों ने प्रकटीकरण के उपरांत के अपने अनुरोधों में यह तर्क भी दिए हैं कि अन्य घरेलू उत्पादक कम कीमतें प्रस्तुत कर रहे हैं और इससे घरेलू उद्योग की कीमतें वास्तव में प्रभावित हो रही हैं । इच्छुक पक्षकारों के ये तर्क एक-दूसरे के विरोधी हैं । प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जब तक पाटित आयातों से घरेलू कीमतों में पर्याप्त कटौती होती रहेगी तब तक याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग सिहत घरेलू उत्पादकों के लिए कीमतों में वृद्धि करना कठिन होगा। वास्तव में कम मात्रा में आयातों का कारण घरेलू उद्योग द्वारा अपना बाजार अंश बरकरार रखने के लिए अपनाई गई कठोर मूल्य नीति को अपनाना है ।

(ख) पटित आयातों के कम कीमत पर बेचे जाने के प्रभाव

93. कम कीमत पर बेचे जाने का निर्धारण करने के प्रयोजन से डीजीसीआईएंडएस के आंकडों के अनुसार संबद्ध देश से दोनों उत्पादों के आयात की पहुंच कीमतों की समदर्शी उत्पादों के लिए घरेलू उद्योग की गैर-क्षिति बिक्री कीमत से तुलना की गई है ताकि नियमों के अनुबंध-2 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार उनकी कीमतों का निर्धारण किया जा सके। पटित आयातों के कम कीमत पर बेचे जाने के प्रभाव निम्नान्सार हैं:

विवरण	यूओएम	एफएबी	एसके
एनआईपी भारित औसत	रुपए/किलोग्राम	***	***
एडीडी रहित भारित औसत कीमत पहुंच कीमत	रुपए/किलोग्राम	118.44	185.95
कम कीमत पर बेचना	रुपए/किलोग्राम	***	(***)
कम कीमत पर बेचना	%	0-10%	(0-10)%
एडीडी सहित भारित औसत कीमत पहुंच कीमत	रुपए/किलोग्राम	139.74	223.90
कम कीमत पर बेचना	रुपए/किलोग्राम	(***)	(***)
कम कीमत पर बेचना	%	(5-15)%	(25-30)%

94. यह देखा गया है कि संबद्घ देश से भारतीय बाजारों में प्रवेश करने वाले आयात, घरेलू उद्योग की गैर-क्षिति कीमत से काफी कम हैं जिससे यह पता चलता है कि कम कीमत पर बेचने का घरेलू कीमतों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है । तथापि, जैसा कि पहले नोट किया गया है, इसकी जांच, कीमत ह्रास/न्यूनीकरण के विश्लेषण के साथ किए जाने की आवश्यकता है ।

(ग) कीमत हास/न्यूनीकरण

95 . घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों से पड़ने वाले कीमत हास अथवा न्यूनीकरण के प्रभावों की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग की निबल बिक्री वसूली की प्रवृति की घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के साथ तुलना की गई है और पाटित आयातों की पहुंच कीमतें निम्नानुसार हैं :

उत्पाद - फ्रंट एक्सिल बीम - यंत्रित

विवरण	यूओएम	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
बिक्री की लागत	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
	प्रवृति	100	85	88	88
बेचने की कीमत	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
	प्रवृति	100	99	103	102
पहुंच कीमत	रुपए/किलोग्राम	95	106	116	118
	प्रवृति	100	112	122	125
एडीडी अभिदत्त पहुंच कीमत	रुपए/किलोग्राम	111	123	135	140
_	प्रवृति	100	111	122	126

उत्पाद - स्टीयरिंग न्क्कल्स - यंत्रित

विवरण	यूओएम	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
बिक्री की लागत	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
	प्रवृति	100	90	92	105
बेचने की कीमत	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
	प्रवृति	100	97	105	111
पहुंच कीमत	रुपए/किलोग्राम	140	148	164	186
	प्रवृति	100	106	117	132
एडीडी अभिदत्त पहुंच कीमत	रुपए/किलोग्राम	170	179	199	225
	प्रवृति	100	105	117	132

- 96. उपरोक्त आंकडों से यह पता चलता है कि एफएबी के मामले में आधार वर्ष की तुलना में क्षिति की जांच करने की अविध के दौरान उत्पादन की लागत में लगभग 12% की उल्लेखनीय गिरावट आई है । आयात की पहुंच कीमतों में जो कि आधार वर्ष में अत्यिधक कम थीं, आधार वर्ष की तुलना में लगभग 25% की वृद्धि हुई है, लेकिन वे फिर भी घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत के साथ-साथ बिक्री की कीमत से काफी नीचे बनी हुई थीं। बिक्री कीमत में मामूली वृद्धि हुई है।
- 97. जहां तक स्टीयरिंग नुक्कल्स का संबंध है, घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत में आधार वर्ष की तुलना में लगभग 5% तक की मामूली वृद्धि हुई है। आयात का पहुंच मूल्य जो कि आधार वर्ष के दौरान बहुत कम था, आधार वर्ष की तुलना में लगभग 32% बढा है लेकिन यह अभी भी घरेलू उत्पाद के उत्पादन की लागत की तुलना में मामूली नीचे बना हुआ है।
- 98. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि आयात की ऐसी छोटी मात्रा घरेलू उद्योग की कीमतों में हास अथवा न्यूनीकरण नहीं ला सकती हैं और कीमतों में हास और न्यूनीकरण के लिए केवल एक कारण घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा का होना है। तथापि, आंकडों से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग प्रत्यक्षत: कीमत दिशा पर बना हुआ है क्योंकि आयात की कीमतें, उसकी लागतों और कीमतों से अभी काफी नीचे हैं। चूंकि घरेलू उद्योग प्रत्यक्षत: कीमत दिशा पर बना हुआ है और पहुंच मूल्य में वृद्धि होने के फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि नहीं कर रहा है, इसलिए कीमत में कटौती तथा कम कीमत पर बेचने का मार्जिन नकारात्मक है। आयात की मात्रा नहीं बढ़ने का यही कारण हो सकता है। घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि यदि शुल्कों को रद्द कर दिया जाता है तो आयात की पहुंच कीमत, घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री की कीमत से निरंतर काफी कम बनी रहेगी और इसलिए इसके फलस्वरूप कीमत का हास होगा और वित्तीय घाटें होंगे।

ट. 3 घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक प्राचलों की जांच

(क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री पर पडने वाले वास्तविक और संभावित प्रभाव

99. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा संबंधी सूचना नीचे तालिका में दी गई है :

विवरण	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	पीओआई
क्षमता	एमटी	240,000	240,000	240,000	240,000
कुल उत्पादन- संयंत्र	एमटी	162,930	189,036	144,987	145,333
संयंत्र की क्षमता का उपयोग	%	68%	79%	60%	61%
एफएबी					
उत्पादन	एमटी	34,522	44,885	30,859	32,566
घरेलू बिक्री	एमटी	20,191	19,175	11,531	9,233
केप्टिव को छोड कर मांग	एमटी	25,672	24,338	16,652	12,292
एसके					
उत्पादन	एमटी	5,459	6,360	5,303	5,282
घरेलू बिक्री	एमटी	718	1,048	1,285	1,250
केप्टिव को छोड कर मांग	एमटी	7,291	8,010	6,331	4,764

100. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए किटबद्ध क्षमताएं नहीं हैं। ऐसी क्षमताएं अनेक ढलाई और यंत्रित उत्पादों के लिए सामान्य होती हैं। इसलिए प्राधिकारी ने सामान्य उत्पादन क्षमताओं से निर्मित किए जाने वाले सभी उत्पादों को शामिल करने के बाद ही क्षमता और क्षमता उपयोग पर विचार किया है। उपरोक्त आंकडे यह निर्दिष्ट करते हैं कि ढलाई और मशीन से निर्मित किए जाने वाले उत्पादों का उत्पादन करने के लिए संयंत्र की क्षमता समान बनी हुई है, इनके उत्पादन में, वर्ष 2011-12 में उल्लेखनीय वृद्धि होने के बाद आधार वर्ष के उत्पादन की तुलना में लगभग सभी 10% की गिरावट आई है। वर्ष 2011-12 में संयंत्र की क्षमता के उपयोग में वृद्धि हुई थी और उसके बाद उसमें गिरावट आई है। तथापि, उपर्युक्त दर्शाए गए संयंत्र की क्षमता और उत्पादन, उक्त संयंत्र में विनिर्मित समस्त उत्पादों के लिए है और इसलिए ये विचाराधीन उत्पाद के बारे में सही छावि प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।

- 101. जहां तक उत्पादन का संबंध है, इन आंकडों से यह पता चलता है कि वर्ष 2011-12 में एफएबी और एसके दोनों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने के बाद उसमें आधार वर्ष के स्तर से मामूली गिरावट आई है । तथापि, घरेलू बाजार में एफएबी के बिक्री से यह पता चलता है कि इस अविध के दौरान इसमें काफी गिरावट आई है जबिक नुक्कल्स की बिक्री में वर्ष 2011-12 में कुछ सुधार होने के बाद यह अभी सामान्य बनी हुई है । प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस अविध के दौरान दोनों उत्पादों की मांग में गिरावट आई है ।
- 102. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति की जांच अविध के दौरान संबद्ध माल के आयात की मात्रा कम है, इसलिए उपरोक्त मानदंडों के आधार पर आयात का वास्तविक प्रभाव अधिक नहीं होगा । लेकिन ये आंकडे यह भी निर्दिष्ट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां मांग में काफी गिरावट होती है, यदि आयात की मात्रा बढती है तो इससे उत्पादन और क्षमता उपयोग के साथ-साथ घरेलू उद्योग की बिक्री पर गंभीर प्रभाव पडेगा।

(ख) लाभप्रदता, लाभप, निवेश पर आय और नकद प्रवाह पर पडने वाले वास्तविक और संभावित प्रभाव

103. प्राधिकारी द्वारा उत्पादन की लागत और अन्य संबद्घ लागत के साथ-साथ बिक्री की कीमतों की विस्तृत जांच करने के आधार पर घरेलू बाजार में संबद्घ माल की बिक्री से घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ का आक्कलन कर लिया गया है जो कि निम्नान्सार है :

फ्रंट एक्सिल बीम	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
लाभ/हानि	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
प्रवृति		100	112	89	68
नकद लाभ	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
प्रवृति		100	109	95	86
ब्याज पूर्व लाभ	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
प्रवृति		100	112	99	79
नियोजित पूंजी पर आय	%	20-30%	25-35%	15-25%	15-25%
प्रवृति		100	125	96	95
स्टीयरिंग नुक्कल्स	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
लाभ/हानि	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
प्रवृति		100	476	457	96
नकद लाभ	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
प्रवृति		100	180	175	77
ब्याज पूर्व लाभ	रुपए/किलोग्राम	***	***	***	***
प्रवृति		100	245	245	89
नियोजित पूंजी पर आय	%	5-15%	25-35%	25-35%	5-15%
प्रवृति		100	348	320	127

104. इच्छुक पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि इसमें लगाई गई पूंजी पर घरेलू उद्योग का लाभ समग्र क्षिति विश्लेषण अविध के दौरान अच्छा रहा है और घरेलू उद्योग आटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी के कारण मांग में गिरावट आने के लिए लाभ में गिरावट के लिए भी जिम्मेदार है । वर्ष 2011-12 के बाद मुनाफे में गिरावट के कारणों में परस्पर प्रतिस्पर्धा का होना भी है। उपरोक्त आंकर्ड यह निर्दिष्ट करते हैं कि एफएबी के मामले में वर्ष 2011-12 तक लाभ, नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ और लगाई गई पूंजी पर आाय में वृद्धि हुई है और उसके बाद क्षिति अविध में इसमें गिरावट आ गई । घरेलू उद्योग लगाई गई पूंजी पर निरंतर अच्छी आय प्राप्त कर रहा है । स्टीयरिंग नुक्कल्स के मामले में वर्ष 2011-12 तक लाभ, नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ और लगाई गई पूंजी पर आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और उसके बाद क्षिति अविध में इसमें गिरावट आ गई । हालांकि घरेलू उद्योग इस क्षेत्र में अभी भी लाभ अर्जित कर रहा है लेकिन जांच अविध के दौरान लाभांश और लगाई गई पूंजी पर होने वाली आय में काफी गिरावट आई है ।

(ग) बाजार के हिस्से पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

105. जैसे कि पहले बताया गया है घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में फ्रंट एक्सिल बीम के लिए मांग में गिरावट आई है तथा आधार वर्ष से जांच अविध तक के दौरान स्टीयिरंग नुक्कल्स के लिए बाजार हिस्से में बढोत्तरी हुई है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने के कारण क्षिति की जांच अविध के दौरान चीन से होने वाले आयात की मात्रा बहुत कम रही है। ऐसे उत्पाद की मांग में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। ऐसी स्थिति में क्षिति के प्राचल के रूप में घरेलू बाजार में विभिन्न उद्योगपितयों के बाजार हिस्से, घरेलू उद्योग की सही स्थिति को नहीं दर्शा सकते हैं।

(घ) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

106. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के बहु-उत्पादक कंपनी होने के नाते उसकी एक ही इकाई में अनेक प्रकार के उत्पादों का उत्पादन होता है, इसलिए संबद्ध माल के पाटन का प्रभाव, घरेलू उद्योग के रोजगार और मजदूरी कारकों में परिलक्षित नहीं हो सकता है । जहां तक उत्पादकता का संबंध है, यह उत्पादन की दिशा की ओर ही उन्मुख हुआ है ।

रोजगार और मजदूरी	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
प्रवृति		100	115	101	99
वेतन और मजदूरी	रुपए लाख	***	***	***	***
प्रवृति		100	125	127	142
उत्पादन की प्रत्येक इकाई पर मजदूरी	रुपए/कि.ग्रा	***	***	***	***
प्रवृति		100	98	141	150
प्रति व्यक्ति उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
प्रवृति		100	112	90	96
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी	109.54	140.40	99.07	103.69
प्रवृति		100	128	90	95

(ङ) मालस्चियों पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

107. चूंिक विचाराधीन उत्पाद, आदेश दिए जाने पर निर्मित किए जाने वाली मदे हैं, इसलिए घरेलू उद्योग की ऐसे उत्पाद की विशिष्ट माल सूचियां नहीं हैं तथा ऐसी माल सूचियां, मौजूदा मामले में तथ्य स्वरूप संबद्ध प्राचल नहीं हैं।

(च) घरेलू कीमतों का प्रभावित करने वाले कारक

108. आंकडों की जांच करने से ऐसा पता चलता है कि हालांकि संबद्ध देश से पाटित आयात की मात्रा कम रही है, फिर भी ये ऐसी कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं जो कि घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत और बिक्री कीमतों से कम हैं जिसके कारण भारतीय बाजार में कीमतों में काफी कटौती हुई और माल कम कीमत पर बेचा जा रहा है। घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में अपनी बिक्री की मात्रा में होने वाली पर्याप्त कमी को रोकने के लिए अपनी कीमत सीमा क्रम को बनाए रखा हुआ है। विश्व भर के ऑटोमोबाईल क्षेत्र में ऐसी सामान्य स्थितियां बनी रहने के कारण इसकी मांग में विशेष गिरावट आई है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि मंदी होने के साथ-साथ पाटन के संभावित प्रभावों के कारण मांग में गिरावट आने से ऑटोमोबाईल क्षेत्र में ऐसे उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की कीमतें प्रभावित हुई हैं।

(छ) वृद्धि पर पडने वाले वास्तविक और संभावित प्रभाव

109. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विभिन्न वास्तविक और वित्तीय प्राचलों में मांग की वृद्घि में विशेष गिरावट आने की स्थिति, पाटित आयातों के कारण होने वाली क्षिति का निर्धारण करने में कोई सार्थक मार्गनिर्देशन करेगी। तथापि, आधिकारी ने यह नोट किया है कि जांच अविध के दौरान घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन, मात्रा और कीमत प्राचलों दोनों ही रूप में हानिकर रहा है। इस अविध के दौरान बिक्री, उत्पादन, बाजार हिस्सा, लाभ, निवेश पर आय और नकदी प्रवाह विशेष रूप से नकारात्मक रहा है।

(ज) पुंजी निवेश बढाने की क्षमता

110. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकादाता एक बहु- उत्पाद कंपनी है जो कि अनेक क्षेत्रों में अनेक फोर्जड और यंत्रित उत्पादों को विनिर्मित करती है। इसलिए उसकी पूंजी जुटाने की क्षमता, संबद्ध माल की उत्पादन शृंखला के कार्य-निष्पादन द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तथापि, पाटन की विद्यमान और संभावित स्थिति के साथ-साथ ऑटोमोबाईल क्षेत्र की मंदी के कारण कंपनी की नए निवेश करने और संबद्ध माल की उत्पादन शृंखला का विस्तार करने की क्षमता संभवत: प्रभावित हो सकती है।

(झ) पाटन और पाटन मार्जिन का स्तर

111. क्षिति का निर्धारण करने के लिए एक कारक के रूप में पाटन का मार्जिन यह संकेत देता है कि संबद्ध देश के लिए निर्धारित पाटितआयातों का पाटन मार्जिन, उपरोक्त न्यूनतम स्तर से अधिक और विशिष्ट है।

ट. मौजूदा क्षति और अनियत संपर्कों का समग्र मूल्यांकन

112. विभिन्न कारकों के उपरोक्त विश्लेषण यह संकेत देता है कि संबद्ध माल के उत्पादन और घरेलू बिक्री के बतौर घरेलू उद्योग के वास्तिविक कार्य-निष्पादन के साथ-साथ उनके घरेलू प्रचालनों में आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में सुधार हुआ था लेकिन उसके बाद सभी प्राचलों में गिरावट आ गई जिससे क्षिति होने का पता चलता है। तथापि, हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को होने वाली ऐसी क्षिति अन्य कारकों के कारण हैं जैसे कि ऑटोमोबाईल क्षेत्र में मंदी आना और इसका चीन से होने वाले आयात से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों के आलोक में अन्य अनिवार्य कारकों की यह देखने के लिए जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को होने वाली क्षिति के लिए अन्य कारक जिम्मेदार हैं।

(1) अन्य स्रोतों से आयात की मात्रा और कीमतें

113. जांच किए गए आयात के आंकडों से ऐसा पता चलता है कि केवल संबद्ध देश से ही संबद्ध माल का आयात हुआ है । इसलिए अन्य देशों से होने वाले आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है ।

(ii) मांग में संकुचन और/अथवा खपत के पेटर्न में परिवर्तन

114. जैसे कि पहले नोट किया गया है घरेलू बाजार में संबद्ध माल की मांग की स्थिति और उनकी खपत का पेटर्न यह दर्शाता है कि क्षिति अविध के दौरान संबंधित उत्पादों की मांग में विशेष गिरावट आई है जिसके लिए ऑटोमोबाईल क्षेत्र में होने वाली मंदी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है । हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि यदि कोई क्षिति हुई है तो उसका कारण मांग में गिरावट आना हो सकता है और न कि संबद्ध देश से होने वाला नगण्य आयात । प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विश्व भर के ऑटोमोबाईल उद्योग में मंदी आई हुई थी तथा क्षिति की जांच किए जाने की अविध के दौरान भारत में वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन और खपत में भी गिरावट आई है जिसके फलस्वरूप संबद्ध उत्पादों की मांग में गिरावट आई । इसलिए मांग ऐसे प्रमुख कारकों में से एक कारक है जो कि उत्पादन की मात्रा और बिक्री के रूप में घरेलू उदयोग को प्रभावित कर रहा है।

115. प्राधिकारी ने याचिकादाता के इन तर्कों को भी नोट किया है कि पाटन रोधी शुल्क को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को ऐसी स्थिति में और अधिक क्षति होगी जबिक इस समय ऐसे उत्पादों की मांग भारत और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में कम है। यह भी तर्क दिया गया है कि ऐसी स्थिति में जब कि भारतीय और चीन की कीमतों के बीच काफी अंतर व्याप्त है, ऐसे शुल्कों के समाप्त होते ही भारत में उपभोक्ता, चीन के उत्पादों का आयात करने के लिए उन्मुख होंगे।

(iii) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापारित प्रतिबंधित प्रक्रियाएं और प्रतिस्पर्खा

116. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध माल के कुछ अन्य उत्पादक हैं जो कि संबद्ध माल का उत्पादन कर रहे हैं और उनको घरेलू बाजार में बेच रहे हैं अथवा संबद्ध माल को अपने पास केप्टिव रख रहे हैं । हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि यदि कोई क्षित हुई है तो वह भारतीय बाजार में पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा होने अथवा घरेलू उद्योग के अंतर्भूत कारणवश है । यह तर्क दिया गया है कि क्षिति होने की अविध के दौरान अन्य भारतीय उत्पादक अपनी बिक्री को स्थिर बनाए रखे हुए हैं और वास्तव में उन्होंने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को हथिया लिया है । तथापि, विगत खंडों में विश्लेषित आंकडों से ऐसा पता चलता है कि वे इसका समर्थन नहीं करते हैं । आंकडों से ऐसा पता चलता है कि इस अविध के दौरान अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियों में भी पर्याप्त गिरावट आई है। इन उत्पादकों के बीच किसी भी प्रकार की कोई अनुचित प्रतिस्पर्द्धा होने अथवा घरेलू बाजार में किसी प्रकार की ऐसी व्यापारिक प्रतिबंधित प्रक्रियाओं के व्याप्त होने का पता नहीं चलता है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षिति हुई हो । प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विदेशी उत्पादक भी घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं और उनके खिलाफ पाटन किए जाने के आरोप की पुष्टि हुई है ।

117. इच्छुक पक्षकारों ने प्रकटीकरण के उपरांत के अपने अनुरोधों में इस बात को दोहराया है कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग को क्षिति, यदि कोई हो, का कारण अन्य घरेलू उतपादकों से परस्पर प्रतिस्पर्धा का होना है न कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण और यह तर्क दिया गया है कि अन्य उत्पादक घरेलू बाजार में कम कीमतें प्रस्तुत कर रहे हैं और इससे घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है तथा याचिकाकर्ता के बाजार अंश पर कब्जा हो रहा है । तथापि, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, इसके समर्थन में कोई आंकड़े नहीं हैं । इसलिए इस संबंध में इच्छुक पक्षकारों के तर्क मजबूत नहीं हैं ।

(iv) प्रोद्योगिकी में विकास

118. उत्पादों के उत्पादन की प्रोद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, न ही भविष्य में इसमें कोई परिवर्तन होने की संभावना है। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा ऐसा कोई तर्क नहीं दिया गया है कि एक कारक के रूप में प्रोद्योगिकी, घरेलू उद्योग को प्रभावित कर रही है। चीन के उत्पादकों द्वारा यह दावा किया गया था कि उत्पादन की प्रक्रिया में कुछ अंतर है जिस पर विधिवत् विचार किया गया है और यह पाया गया है कि भारतीय उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त प्रोद्योगिकी और उत्पादन की प्रक्रिया एक स्थापित प्रोद्योगिकी है और और उसे क्षति का कारण होना नहीं माना जा सकता है। इसलिए प्रोद्योगिकी में विकास होना क्षति होने का कारक नहीं है।

(V) घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन

119. याचिकादाता ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का विशेष निर्यात किया है जिसका उल्लेख नीचे तालिका में किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि याचिकादाता निरंतर निर्यात बाजारों पर ध्यान संकेन्द्रित किए हुए है जबिक वह भारत के बाजार में अपनी विद्यमानता को बढाने के कदम उठा सकता है। यह तर्क भी दिया गया है कि याचिकादाता यह बहाना नहीं कर सकता है कि वह अपनी मालसूचियोंको निर्यात बाजार में इसलिए खपा रहा है क्योंकि याचिकादाता की संबद्ध उत्पाद की कोई मालसूची नहीं है। आईर देने पर ही संबद्ध उत्पादों को निर्मित किया जाता है। इच्छुक पक्षकारों ने प्रकटीकरण के उपरांत के अपने अनुरोधों में इन तर्कों को दोहराया है। इस संबंध में प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन की जांच की है जो कि निम्नानुसार है:

निर्यात	इ काई	2010-11	2011-12	2012-13	जांच अवधि
फ्रंट एक्सिल बीम	एमटी	***	***	***	***
प्रवृति	स्चक	100	180	133	167
कुद्दित	एमटी	***	***	***	***
यंत्रित	एमटी	***	***	***	***
स्टीयरिंग नुक्कल्स	एमटी	***	***	***	***
प्रवृति	सूचक	100	114	86	86
कुद्दित (फोर्जड)	एमटी	***	***	***	***
यंत्रित	एमटी	***	***	***	***

120. उपरोक्त आंकडों से ऐसा पता चलता है कि याचिकादाता द्वारा उत्पादित एफएबी के निर्यात में आधार वर्ष की तुलना में जांच अविध के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई है, हालांकि वर्ष 2011-12 की तुलना में उसमें लगभग 10 % की मामूली गिरावट आई है। तथापि, स्टीयरिंग नुक्कल्स के मामले में आधार वर्ष की तुलना में निर्यात में लगभग 14 % की गिरावट आई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यात बिक्री के लेनदेन में याचिकादाता ने घरेलू बिक्री की तुलना में निर्यात से निरंतर बेहतर लाभ अर्जित किया है। ऐसी स्थिति में जबिक ऐसे उत्पादों की मांग कम है और कीमत पाटित आयातों से प्रभावित है, उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और निर्धारित लागत को वसूल करने के लिए घरेलू उद्योग के पास निर्यात बाजार का फायदा उठाने के सिवाय शायद कोई और विकल्प नहीं है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की क्षति की जांच, उसके घरेलू प्रचालनों तक ही सीमित है, तथा निर्यात प्रचालनों से यदि उसको किसी प्रकार की कोई क्षति हुई है, तो उसको ध्यान में नहीं रखा गया है।

121. इन अनिवार्य गैर-आरोपण कारकों के अतिरिक्त हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि प्राधिकारी को इस मामले से संबंधित अन्य कारकों को भी ध्यान में रखना चाहिए जैसे कि मंदी के कारण उत्पादन और बिक्री में गिरावट आना और विनिमय दर के परिफल । विभिन्न खंडों में ऑटोमोबाईल के क्षेत्र में मंदी के प्रभाव का पहले ही उल्लेख कर दिया गया है । जहां तक विनिमय की दर में उतार-चढाव होने का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच अविध के दौरान विभिन्न कारकों की जांच, उस समय व्याप्त परिस्थितियों के अनुसार झटपट की जाने वाली जांच है । इसलिए उस समय प्रचलित विनिमय की दर, ऐसे निर्धारण में प्रयुक्त किए जाने के लिए सही विनिमय दर है।

122. उपरोक्त विश्लेषण से ऐसा पता चलता है कि ऑटोमोबाईल उद्योग में व्याप्त मंदी की प्रवृति और मांग में गिरावट आने की परिस्थित में पाटित आयातों, हालांकि इनकी मात्र कम है, के कीमत पर पडे प्रभाव के कारण मांग में आई गिरावट से घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हुआ है। पाटित आयात घरेलू कीमतों का निरंतर अधोरदन किए हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मांग में गिरावट आने की स्थिति में घरेलू बाजार ने संबद्ध देश से पाटित आयातों के संभावित अंतर्प्रवाह की रोकथाम करने के लिए ही कीमतों का दमन किया हुआ है क्योंकि ऐसे आयात के फलस्वरूप क्षिति होती है।

ठ. क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

123. प्राधिकारी द्वारा शुल्क संबंधी नियम का कम अनुपालन किए जाने को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देश से संबद्ध माल का आयात होने के संबंध में क्षिति के अंश का भी निर्धारण किया गया है। क्षिति के अंश का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमों के अनुबंध - 3 में निर्धारित क्रियाविधियों के अनुसार घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षिति कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि एनआईपी का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त की गई आय से अधिक आय की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि गैर-क्षिति कीमत (एनआईपी) का निर्धारण करते समय सुसंगत प्रक्रिया के अनुसार पाटन-रोधी नियमों के अनुबंध-3 में निर्धारित क्रियाविधियों का अनुपालन किया गया है। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विगत में घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त की गई वास्तविक आय, प्राधिकारी द्वारा गैर-क्षिति कीमत (एनआईपी) का निर्धारण करते समय स्वीकृत की गई उचित आय से अधिक है।

124. प्रकटीकरण के उपरांत की टिप्पणियों में घरेलू उद्योग ने पूर्व खंड में यथाउल्लिखित गैर-क्षित कीमत के निर्धारण के संबंध में कई मामले उठाए हैं । घरेलू उद्योग के इन तर्कों के संबंध में कि घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की कीमतें और लागतें स्वीकार की जाए और सामान्य क्षमता उपयोग के आधार पर ऊपिर लागत को समायोजित किया जाए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस प्रकार का दृष्टिकोण पाटनरोधी नियमों के अनुसार अनुमत्य नहीं है । इसके अलावा, निवल पिरसंपित्तयों के नियतन के आधार पर और प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के अनुसार एस जी ए व्ययों का गोपनीय आधार पर घरेलू उद्योग को प्रकटीकरण किया गया है । अतः गैर क्षिति कीमतों के संबंध में घरेलू उद्योग के तर्क व्यवहारिक नहीं पाए गए ।

125. संबद्ध माल की गैर-क्षिति कीमत (एनआईपी) का निर्धारण, पाटन-रोधी नियमों के अनुबंध-3 में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार आवेदक घरेलू उद्योग के बारे में जांच की अविध के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकडों को ध्यान में रख कर किया गया है। चूंकि जांच अविध के दौरान केवल यांत्रिक उत्पादों का ही आयात किया गया है, इसलिए उचित तुलना करने के लिए उपयुक्त विशिष्ट किस्म के उत्पादों के लिए गैर-क्षिति कीमत (एनआईपी) का निर्धारण, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित किए जा रहे इसी प्रकार के उत्पादों को ध्यान में रख कर किया गया है।

126. इस प्रकार से निर्धारित की गई गैर-क्षति कीमत (एनआईपी) की तुलना, डीजीसीआईएंडएस के आंकडों के अनुसार जांच अविध के दौरान आयातित माल के भारित औसत पहुंच मूल्य से की गई है । तदनुसार संबद्घ देश से आयातित विचाराधीन उत्पादों के लिए क्षति का मार्जिन निम्नानुसार है :

विवरण	यूओएम	एफएबी	एसके
भारित औसत एनआईपी	अमरीकी डालर/कि.ग्रा.	***	***
डीजीसीआईएस आंकडों के अनुसार भारित औसत पहुंच	अमरीकी डालर/कि.ग्रा		
कीमत		1.946	3.040
क्षति मार्जिन	अमरीकी डालर/कि.ग्रा	***	(***)
क्षति मार्जिन	%	***%	(***)%
सीमा (रेंज)		0-10%	(0-10)%
टीआरए और टीआरएफ की पह्ंच कीमतें	अमरीकी डालर/कि.ग्रा	***	***
क्षति मार्जिन	अमरीकी डालर/कि.ग्रा	***	(***)
क्षति मार्जिन	%	***%	(***)%
सीमा (रेंज)		0-10%	(5-15%)

127. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से किए गए आयात की कुल मात्रा के साथ-साथ जांच अविध के दौरान प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात की मात्रा कम थी और इसलिए पहुंच कीमतों को इस अविध के दौरान पाटन और क्षिति के मार्जिन का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता है । इसलिए प्राधिकारी ने पाटन और क्षिति के मार्जिन के संभावित स्तरों का मूल्यांकन करने के लिए कीमत के स्तरों का विश्लेषण करने के लिए प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा तृतीय देशों को किए गए निर्यातों की मात्रा और उनके मूल्यों की भी जांच की है । तथापि, प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा तृतीय देशों को किए गए निर्यातों की मात्रा बहुत कम है जिससे कि कीमत के स्तरों का किसी भी प्रकार का सार्थक संकेत नहीं मिलता है । प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह एक निर्णायक समीक्षा है, शुल्क लागू होने पर भी वर्तमान क्षिति मार्जिन, घातक आयातों के भावी स्तरों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं कर सकता है क्योंकि हालांकि ऐसे आयात की मात्रा कम है, फिर भी अनुमानित पाटन मार्जिन विशेष रूप से सकारात्मक है । इसलिए प्राधिकारी ने निम्नलिखित पैराग्राफों में विभिन्न अन्य प्राचलों के माध्यम से पाटन और क्षिति के निरंतर बने रहने अथवा उनकी प्नरावृति के संभावित पहल्ओं की जांच की है।

ड. पाटन और क्षति के निरंतर बने रहने अथवा उनकी पुनरावृति होने की संभावना की जांच

128. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हालांकि शुल्क प्रभारित किए जाने के बाद आयात की मात्रा में पर्याप्त रूप से गिरावट आई है, फिर भी भारतीय बाजारों में संबद्ध माल के पर्याप्त रूप से पाटित कीमतों पर निरंतर प्रवेश करते रहने की संभावना है। नियमों में ऐसी अपेक्षा की गई है कि प्राधिकारी को इसकी जांच करनी चाहिए कि यदि शुल्कों को रद्द कर दिया जाता है तो क्या उसे स्थिति में पाटन के निरंतर बने रहने की संभावना है अथवा उसकी पुनरावृति होती है और क्या घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होने की संभावना है या क्षति की पुनरावृति होती है।

इ.1 घरेलू उद्योग के विचार

129. घरेलू उद्योग ने अपने निवेदन में यह तर्क दिया है कि -

- चीन से विचाराधीन उत्पादों का निरंतर पाटन हो रहा है, हालांकि ऐसे पाटित आयातों की मात्रा में गिरावट आई
 है, फिर भी पाटन का मार्जिन काफी अधिक है तथा संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पादों के पाटन का गहन प्रभाव
 पडने की संभावना है, भले ही वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को रद्द कर दिया जाए ।
- चीन में उत्पादकों/निर्यातकों के पास काफी बेशी क्षमताएं उपलब्ध है और यदि शुल्कों को रद्द कर दिया जाता है तो निर्यातक बेशी क्षमता को भारत में गहनता से पाटन करने का प्रयास करेंगे ।
- घरेलू उद्योग को इस बात की चिंता है कि सरकार के समर्थन से चीन के उत्पादक अनुचित पाटन पद्धतियों
 का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि चीन में कृत्रिम रूप से कम कीमतों पर इस्पात उपलब्ध है।

- मूल जांच के दौरान उनके इस तर्क को खारिज नहीं किया गया है कि चीन में इस्पात की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमत से कम हैं और तथ्य यह है कि चीन में जिन कीमतों पर इस्पात उपलब्ध है, वह ऐसी कीमत नहीं है, जिससे उसका आयात चीन से किया जा सके । घरेलू और निर्यात के लिए कीमतों में अंतर है । इसलिए यदि शुल्कों को रद्द भी कर दिया जाता है तो भी पाटन की निरंतर संभावना बनी रहेगी ।
- संबद्ध देश से पाटित आयात होने के कारण घरेलू उद्योग की स्थिति संवेदनशील है और उसके निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । यह तो तब है जब कि पाटन-रोधी शुल्क लागू है तथा घरेलू उद्योग को पाटन और उससे होने वाली परिणामी क्षति संभवतः निरंतर जारी रहेगी और भविष्य में और गहन होगी, भले ही इस समय लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाए ।
- हालांकि शुल्क लगाए जाने के बाद संबद्ध देश से होने वाले आयात की मात्रा में गिरावट आई है, जांच अवधि के दौरान हुए काफी आयात हुआ है और यदि लगाए गए पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो ऐसे आयात की विशेष रूप से बढ़ने की संभावना है।
- संबद्ध माल का आयात जिन कीमतों पर किया जा रहा है, वह पर्याप्त रूप से उस कीमत से कम है, जिस पर घरेलू बाजार में माल को बेचा जाता है । इसलिए शुल्क के समाप्त होने पर भी निर्यातक अपने आउटपुट को भारतीय बाजार में और अधिक भेजने के लिए सरणीबद्ध होंगे क्योंकि उनके पास पहले से ही इनकी अतिरेक क्षमता उपलब्ध है और वास्तव में वे ऐसे संबद्ध माल को तृतीय देशों में पर्याप्त रूप से कम कीमतों पर बेच रहे हैं ।
- पाटन-रोधी शुल्क नहीं होने की स्थिति में संबद्ध देश से होने वाले आयात से घोर कीमत अधोरदन होगा । घरेलू और आयातित उत्पाद की कीमत में विशेष अंतर होने के फलस्वरूप विचाराधीन उत्पादों के आयात में विशेष वृद्धि होगी । इसलिए वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को अपने बिक्री मूल्यों को बनाए रखने के लिए या तो अपनी कीमत को कम करना पडेगा अथवा यदि घरेलू उद्योग वर्तमान बिक्री मूल्य को बनाए रखता है तो उसकी मात्रा में विशेष कमी आएगी । ऐसी किसी भी स्थिति में उसे सामग्री की क्षिति होगी ।
- पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त किए जाने से बाजार की कीमतों पर विशेष प्रतिकूल प्रभाव पडेगा और उससे घरेलू
 उदयोग को निरंतर क्षिति होती रहेगी तथा यह आगे और गहन होगी ।
 - 130. घरेलू उद्योग ने प्रकटीकरण के उपरांत के अपने अनुरोधों में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में अपनी स्थिति पुनः स्पष्ट की है।

ड. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

- 131. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने विभिन्न निवेदनों में निम्नोक्त विचार प्रकट किए हैं:
 - निर्णायक समीक्षा में समग्र जांच का संकेन्द्रण इस तथ्य पर है कि क्या पाटन-रोधी शुल्क को रद्द किए जाने के फलस्वरूप पाटन की पुनरावृति होगी अथवा उससे घरेलू उद्योग को क्षित होगी । इस प्रकार निर्णायक समीक्षा में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि पाटन और क्षित का वर्तमान स्तर क्या है बल्कि उसमें संभावित पाटन और क्षिति अधिक जरूरी है । इसलिए जांचकर्ता प्राधिकारी को पाटन अथवा क्षिति की संभावना का निर्धारण करने के लिए भावी घटनाओं का विश्लेषण करना होगा । तथापि, मौजूदा जांच में याचिकादाता ने पाटन की पुनरावृति और क्षिति होने की संभावना का पता लगाने के लिए जांच अविध के पश्चात् किसी भी प्रकार के ऐसे आंकडे प्रदान नहीं किए हैं जिनसे यह पता चल सके पाटन निरंतर बना हुआ है अथवा उससे उसको कितनी क्षिति हुई है।
 - इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2004 (170) ई.एल.टी. 144 (ट्राई डेल) के मामले में यह निर्णय दिया गया है कि <u>बेशी उत्पादन क्षमता होने को यह नहीं माना जा सकता है कि उससे स्पष्ट रूप से क्षित होने की संभावना और क्षिति होना सन्निकट है</u> / याचिकादाता ने अतिरेक क्षमता की कथित

विद्यमानता और क्षिति की पुनरावृति के बीच कोई संपर्क तय नहीं किया है। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी यह कल्पना करते हैं कि अतिरेक क्षमता विद्यमान है, तो भी ऐसे आंकडों की विद्यमानता स्वतः पाटनरोधी शल्कों को आगे बनाए रखने का आधार नहीं हो सकती है, जैसा कि प्राधिकारी ने यूएसए से एनीलाईन और जापान के मामले की निर्णायक समीक्षा के बारे में दिनांक 17 जनवरी, 2012 में अंतिम निर्णय दिया है।

132. अन्य इच्छुक पक्षकारों ने प्रकटीकरण के उपरांत के अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि इनके जांच अविध के उपरांत के विश्लेषण के अनुसार घरेलू उद्योग के मुनाफे में जांच अविध के उपरांत पर्याप्त सुधार आया है और गिरती मांग में भी सुधार आया है क्योंकि संबद्ध उत्पाद के लिए मांग में जांच की अविध के उपरांत मीडियम और हैवी कॉमिशियल वाहनों की बेहतर मांग के कारण पर्याप्त वृद्धि हुई है । यह तर्क दिया गया है कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और इस बात की प्रबल संभावना है कि आयात पाटित मूल्यों पर नहीं होंगे और यिद पाटनरोधी शुल्क हटा लिए जाते हैं तो घरेलू उद्योग को इससे कोई नुकसान नहीं होगा । साथ ही वर्तमान तथ्य भी पाटनरोधी शुल्कों के हटाए जाने के कारण पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति होने की ओर इंगित नहीं करते ।

ड. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

133. मौजूदा जांच, चीन जन. गणराज्य से विचाराधीन उत्पादों के आयात पर पहले से लगाए गए पाटन-रोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है । नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी को यह निर्धारित करना होता है कि यदि इन शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है तो क्या उससे पाटन के निरंतर जारी रहने या उसकी पुनरावृति और क्षिति होने की संभावना है । पूर्व खंडों में की गई जांच से यह सिद्ध हो गया है कि शुल्कों के लगे होने के बावजूद संबद्ध माल भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहा है और उससे घरेलू बाजार को पाटित आयातों की विद्यमानता से क्षिति होने के साथ-साथ मांग में विशेष गिरावट आने की स्थिति का सामना करना पड रहा है । इसलिए प्राधिकारी को इस तथ्य की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किए जाने से ऐसे उत्पादों का निरंतर पाटन होने की संभावना है और घरेलू उद्योग को उससे होने वाली परिणामी क्षिति को निरंतर सहना पडेगा।

134. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन से प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा अपनी प्रश्नावली के उत्तरों में प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार यह सिद्ध हो गया है कि उक्त देश से पाटित कीमतों पर ऐसे माल का निरंतर निर्यात जारी है, हालांकि उसकी मात्रा कम है। वस्तुत: प्रतिवादी निर्यातकों ने अपने निवेदन में यह बताया है कि वे चीन में संबद्ध माल के सबसे बड़े उत्पादक हैं तथा हालांकि पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने से भारत को उनके निर्यात में कमी हुई है, फिर भी भारतीय ग्राहक उनके उत्पाद की बेहतर कोटि होने तथा भारतीय उत्पादकों की मांग को पूरा नहीं किए जाने की असमर्थता के कारण उनसे विचाराधीन उत्पादों का निरंतर आयात कर रहे हैं।

135. ऐसे सहयोगी निर्यातकों जो कि चीन में संबद्ध माल के सबसे बड़े उत्पादक और साथ ही भारत के लिए निर्यातक माने जाते हैं, की क्षमताओं और उत्पादन की जांच करने पर ऐसा पता चला है कि इन उत्पादकों के पास ढलाई और यांत्रिक दोनों उत्पादों के लिए विशेष बेशी क्षमता (लगभग 15 %) विद्यमान है, जिसका उपयोग संबद्ध माल का उत्पादन और निर्यात करने के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि भारत उनके लिए अपने बाजार खोल दे। इन निर्यातकों के माल के बिक्री पेटर्न से पता चलता है कि ऐसे उत्पादक मुख्यत: अपने घरेलू बाजार पर निर्भर है और तृतीय देशों को उनके निर्यात बहुत कम होते हैं। क्षिति की जांच करने की अविधि के दौरान इन निर्यातकों की घरेलू बिक्री भी बहुत सपाट है अथवा मामूली गिरावट दर्शाती है। इस अविधि के दौरान विश्व भर में ऑटो उद्योग के निकृष्ट निष्पादन के दौरान वैश्वक बाजार में मांग भी कमजोर थी।

136. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा निर्यातित संबद्ध माल पर लागू शुल्क निम्नोक्त अनुसार थे :

निर्यातक	उत्पाद	श्ल्क
एचटीआरए	एफएबी	0.35 अमरीकी डालर/कि.ग्रा.
एचटीआरएफ	एस के	0.64 अमरीकी डालर/कि.ग्रा.

- 137. संबद्ध माल के वर्तमान कीमत स्तर से पता चलता है कि हालांकि कीमतों में वृद्घि, शुल्कों को रद्द किए जाने के बाद वर्तमान पाटन रोधी शुल्क के स्तर की सीमा तक हुई है, फिर भी माल का निर्यात अब भी पाटित कीमतों अथवा उन कीमतों पर किया जा सकता है जो कि घरेलू बाजार की कीमतों में कटौती करती हैं और कम कीमत पर बेचती हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत को निर्यातित माल की पहुंच कीमत, पाटनरोधी शुल्क लगाए बिना घरेलू बिक्री की कीमतों में अत्यधिक कटौती कर रही है।
- 138. अन्य देशों के निर्यात की मात्रा और मूल्य: प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार तृतीय देशों को उत्पादों के निर्यात की मात्रा और उनके मूल्य बहुत कम हैं। इसलिए यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है, तो चीन में कम घरेलू मांग होने के कारण इन उत्पादों के निर्यातकों को भारत को अपने उत्पादों का बहुताधिक निर्यात करने का अवसर प्राप्त होगा।
- 139. जहां तक क्षिति के निरंतर बने रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग, मांग में गिरावट आने के साथ-साथ पाटित आयातों की कीमत के प्रभाव के कारण निरंतर नुकसान उठा रहा है। जिस कीमत पर चीन जन. गणराज्य से भारत को संबद्ध माल का निर्यात किया जा रहा है, वह एक ऐसा सूचक है जिससे ऐसा पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने पर चीन से इसी संभावित कीमत पर ऐसे माल का निर्यात किए जाने की संभावना है। भारत को निर्यातित माल की पहुंच कीमत, पाटन रोधी शुल्क के बिना ही घरेलू बिक्री कीमतों में अत्यधिक कटौती कर रही है।
- 140. जांच अविध पश्चात् मांग की स्थिति : प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग संबद्ध माल का प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता है और इसका घरेलू बाजार में प्रभुत्व स्थापित है। घरेलू उद्योग की बेवसाईट में उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे मध्यम और भारी स्तर के वाणिज्यिक वाहनों की, जिन पर संबद्ध माल प्रयुक्त किया जाता है, वैश्विक और घरेलू दोनों की मांगों में जांच अविध के पश्चात् उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में अमरीका के ट्रकों की बिक्री में लगभग 20% की वृद्धि हुई है । वर्ष 2014-15 में भारत में ट्रकों की बिक्री में लगभग 21% की वृद्धि हुई है । इसलिए हालांकि घरेलू उद्योग का निष्पादन, क्षति की जांच करने की अविध में मांग में गिरावट आने से प्रभावित हुआ है, फिर भी जांच अविध पश्चात् की प्रवृतियों के अनुसार इसकी स्थिति सकारात्मक है ।
- 141. इच्छुक पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि चूंकि मांग परिदृश्य में जांच की अविध के उपरांत सुधार आया है, इसिलए यिद शुल्कों को हटा लिया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षिति होने की कोई संभावना नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पूर्व जांच में यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो चुका है कि अच्छी वैश्विक मांग के परिदृश्य में भी घरेलू बाजार के महत्वपूर्ण अंश को किनारे करके पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई थी जिससे उद्योग को क्षिति पहुंची थी। यद्यि, जांच की अविध के दौरान आयातों की मात्रा कम थी, लेकिन यह पाटित कीमतों के कारण थी। कम मात्रा स्पष्ट रूप से शुल्क लगाए जाने के कारण थी। शुल्क हटाए जाने के बाद ऐसा कोई कारण नहीं है कि आयातों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि न हो। उस मूल्य स्तर पर और शुल्क के संरक्षण के बिना घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य होगा जिससे सामग्री की क्षिति होगी।
- 142. चीन में मांग परिदृश्यट और उसके संभावित प्रभाव: प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रतिवादी निर्यातक चीन में संबद्ध वस्तुओं के प्रमुख उत्पादक और आपूर्तिकर्ता हैं और जांच की अविध के दौरान उनका 95% से अधिक उत्पादन घरेलू बाजार में बेचा गया था। केवल भारत ही दूसरा प्रमुख बाजार है जिसे उनके उत्पादन का लगभग 15% क्षिति जांच की शुरुआत में ही बेचा गया था, जो जांच की अविध में काफी नीचे गिरकर 5% से भी कम तक आ गया। अन्य: देशों को निर्यात नगण्यक है। अत: चीन में प्रमुख उत्पादक काफी हद तक अपने घरेलू बाजार और

भारतीय बाजार पर निर्भर करते हैं । चीन में वाणिज्यिक वाहनों के लिए मांग के संबंध में उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि चीन में वाणिज्यिक वाहनों के बाजार का विकास अवसंरचना और परियोजना निर्माण में धीमी गित होने के कारण प्रभावित रहा है । चीन की वाणिज्यिक वाहन उद्योग की रिपोर्ट और ऑटो उद्योग क्षेत्र की वैश्विक समीक्षा में केवल वर्ष 2014-17 के दौरान चीन की मैक्रो इकॉनोमी के निरंतर संरचनात्मिक समायोजनों के कारण इस क्षेत्र के लिए मध्यौम और निम्नतर विकास अनुमानों का उल्लेकख किया गया है और चीन में अवसंरचना क्षेत्र का शीघ्र ही पुनरुदार होने की संभावना नहीं है । अतः एक प्रभावित घरेलू मांग के परिदृश्यत के साथ चीन में उत्पादकों के लिए आकर्षक बाजार के रूप में केवल भारतीय बाजार ही होगा, जिसमें कि उनका पहले से ही काफी हिस्सा है और उनके उत्पादन का बड़ा हिस्सा भारतीय बाजार के लिए ही था । यदि शुल्क को हटा लिया जाता है तो चीन के उत्पादकों के लिए चीन से बाहर प्रमुख बाजार के रूप में चीन के निर्यातकों के लिए भारी मात्रा में केवल भारत को पाटित कीमतों पर निर्यात करना काफी आकर्षक होगा। इससे भारत में घरेलू उत्पादकों पर महत्वमपूर्ण मात्रा संबंधी प्रभाव पड़ने की संभावना है । शुल्क हटाने के बाद, यदि चीन में प्रभावित बाजार परिदृश्यम अनुमान के अनुसार ही जारी रहता है तो कीमतों में काफी परिवर्तन हो सकता है । अतः इससे घरेलू उत्पादकों पर काफी कीमत संबंधी प्रभाव भी पड़ सकता जिसके कारण क्षति की पुनरावृत्ति हो सकती है ।

143. जांच अविधि पश्चात् आयात की मात्रा और आयात का मूल्य : जांच अविधि के पश्चात् के आयात के आंकडों की भी जांच यह देखने के लिए की गई है कि आयात की प्रवृतियां क्या हैं । इच्छुक पक्षकारों ने जांच की अविधि के पश्चात् के आयात संबंधी आंकड़ों में कुछेक त्रुटियों का उल्लेख किया है । तद्नुसार, अप्रैल से सितंबर, 2014 तक की अविधि के आयात संबंधी ठीक किए गए हैं और आंकड़े निम्नान्सार हैं :

	अप्रैल से सितंबर, 2014							
विवरण	मात्रा	मूल्य	कीमतें	पहुंच कीमत	पहुंच कीमत			
Idatol	एमटी	लाख रुपए	रुपए/किलोग्राम	रुपए/किलोग्राम	अमरीकी डालर/कि.ग्रा.			
एफएबी	44	46	106	117	1.91			
एसके	148	244	165	182	2.97			

आंकडों का स्रोत : आईबीआईएस

144. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस अवधि के दौरान पाटन-रोधी शुल्क लागू थे और इसलिए इस अवधि के दौरान आयातों की प्रवृति, शुल्क से प्रभावित हो सकती थी । लेकिन इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि भारतीय बाजार में आयात निरंतर प्रवेश करते रहे हैं और कीमतें विशेष रूप से भिन्न नहीं हैं ।

145. इस प्रकार पाटन-रोधी शुल्कों को समाप्त करने से संबद्ध देश में निर्यातकों के लिए भारतीय कीमतों के आकर्षक होने की संभावना है और जैसा की ऊपर उल्लेख किया गया है, ऐसी भी प्रबल संभावना है कि भारतीय उपभोक्ता, क्षित की जांच किए जाने की अविध के पश्चात हुई मांग में वृदिध के कारण पर्याप्त रूप से आयात करने लगेंगे। निर्यातक भी भारतीय बाजार में अपने उत्पादन को सरणीबद्ध करने के लिए प्रोत्साहित होंगे क्योंकि उनके पास अतिरेक क्षमताएं विद्यमान हैं और वे अपने उत्पादों को पहले से ही कम कीमतों पर बेच रहे हैं। उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि यदि मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, भारतीय बाजार में कीमत के आकर्षण, निर्यातकों के पास अतिरेक बेशी क्षमताएं होने और तृतीय देश के बाजार की पर्याप्त कमी होने के कारण जैसा कि उनके वर्तमान निर्यात निष्पादन से पता चलता है, प्रवृतियों के अनुसार भारत में मांग में वृद्धि होने के कारण संबद्ध देश से पाटित आयात में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

146. चीन जन. गणराज्य से भारत को जिस कीमत पर संबद्ध माल का निर्यात किया जा रहा है, वह ऐसी संभावित कीमत का सूचक है, जिस पर पाटन-रोधी शुल्क के समाप्त किए जाने की स्थिति में भी चीन से संबद्ध माल का निर्यात होते रहने की संभावना है । उपरोक्त कारक यह स्पष्ट करते हैं कि शुल्कों को रद्द किए जाने पर भी संबद्ध देश से पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने की संभावना है ।

147. जहां तक क्षिति के निरंतर जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मांग में गिरावट आने के साथ-साथ पाटित आयातों के कीमत दबाव के कारण घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट आई है । भारत में निर्यातित माल की पहुंच कीमत का घरेलू बिक्री कीमतों पर दमनकारी प्रभाव पड़ा है और पाटन-रोधी शुल्क के बिना पहुंच कीमतों में निरंतर कटौती हो रही है । ऐसी स्थिति में यदि वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में कीमत प्राचलों के संबंध में भौतिक रूप से गिरावट आने की संभावना है क्योंकि घरेलू उद्योग कीमतों को आयात कीमतों के समान बनाए रखने के लिए कीमतों का और दमन करने के लिए बाधित होगा । यदि एडीडी को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग आयात की समान कीमतों पर उत्पादों को बेचता है, तो घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के और कम हो जाने की संभावना है, जिसके फलस्वरूप भौतिक क्षिति होगी ।

148. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यहिनष्कर्ष है कि चीन से निरंतर पाटन हो रहा है, हालांकि उसकी मात्रा कम है और वर्तमान पाटन के प्रभाव के साथ-साथ ऑटोमोबाईल क्षेत्र में मंदी आने के कारण वर्तमान क्षिति अविधि में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट आई है। यदि वर्तमान पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो भी पाटन के निरंतर बने रहने और घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट आने की संभावना है जिससे भारी क्षिति होगी।

ढ. निष्कर्ष:

- 149. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने तथा प्राधिकारी के पास उपलब्ध कराए गए तथ्यों पर विचार करने के बाद जैसा कि इस निष्कर्ष में रिकार्ड किया गया है, प्राधिकारी का निष्कर्ष यह है कि :-
 - (i) संबद्ध देश से संबद्ध माल ने अपने सामान्य मूल्यों से कम कीमतों पर भारतीय बाजार में निरंतर प्रवेश किया है और पाटन का मार्जिन पर्याप्त है तथा यह न्यूनतम से अधिक है ;
 - (ii) मांग में गिरावट आने और क्षिति की जांच किए जाने की अविध में पाटित आयातों की विद्यमानता के कारण घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट आई है लेकिन पाटित आयातों के कारण जांच की अविध के दौरान घरेलू उद्योग को क्षिति का सामना नहीं करना पड़ा है;
 - (iii) पाटन-रोधी शुल्क के समाप्त किए जाने की स्थिति में ऐसे माल को पाटन कीमतों पर निर्यात किए जाने की संभावना है तथा पाटन के निरंतर जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने की संभावना है; तथा
 - (iv) पाटन-रोधी शुल्क के समाप्त किए जाने की स्थिति में भी संबद्ध देश से संबद्ध माल का निरंतर पाटन होते रहने के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के निरंतर बने रहने अथवा उसकी पुनरावृति होने की संभावना है।

ण. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

150 प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध माल का आयात ऑटोमोबाईल विनिर्माताओं द्वारा किया जाता है और संबद्ध माल की लागत, भारी और मध्यम स्तर के वाणिज्यिक वाहनों की लागत का बहुत छोटा घटक होती है। इसलिए पाटन-रोधी शुल्क को जारी रखने से ऑटो क्षेत्र अथवा सामान्य उपभोक्ताओं पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबिक इससे पाटन की अनुचित व्यापारिक प्रक्रियाओं से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति अवश्य दूर होगी और देश के सामान्य हित में भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति बहाल की जा सकेगी। पाटन-रोधी उपायों को लागू करने से किसी भी तरीके से संबद्ध देश से होने वाले आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए इनसे उपभोक्ताओं को संबद्ध माल की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

त. सिफारिशें

- 151. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जब यह निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की गई थी तब इसके बारे में सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षिति और आकस्मिक संपर्कों तथा शुल्कों को समाप्त किए जाने की स्थिति में भी पाटन और क्षिति के निरंतर बने रहने की संभावना के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक जानकारी और सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिए गए थे। निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार जांच करने और इस तथ्य की पृष्टि हो जाने से कि पाटन निरंतर जारी है तथा शुल्कों को रद्द किए जाने पर भी पाटन और क्षिति के निरंतर बने रहने अथवा उनकी पुनरावृति होने की संभावना है, प्राधिकारी का विचार है कि यह आवश्यक और उचित होगा कि मूलत: संबद्ध देश से उत्पन्न होने वाले आयात अथवा उससे निर्यात किए जाने वाले संबद्ध माल पर पाटन-रोधी शुल्क को, जैसा कि सीमा शुल्क विभाग की दिनांक 12 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना संख्या 50/2010-सीमा शुल्क के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की आगे की अविध के लिए निरंतर लगाए रखा जाए।
- 152. इस सिफारिश से जारी किए जाने वाले केन्द्रीय सरकार के आदेशों के खिलाफ अपील, अधिनियम के संबद्ध उपबंधों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपील ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर की जा सकेगी।
- 153. प्राधिकारी इस संबंध में अधिनियम के संबद्ध उपबंधों और समय-समय पर जारी किए गए सार्वजनिक नोटिसों के अनुसार समय-समय पर संस्तुत सुनिश्चित उपाय को जारी रखने, उनमें संशोधन करने अथवा उनको समाप्त करने की आवश्यकता की पुनरीक्षा कर सकते हैं । प्राधिकारी द्वारा ऐसी पुनरीक्षा करने के किसी भी अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे हितबद्ध पक्षकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय सीमा के अनुसार दाखिल नहीं कर दिया जाता है ।

ए. के भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September 2015

FINAL FINDING

Subject:- Sunset Review (SSR) Anti-dumping investigation concerning imports of 'Front Axle Beam' and 'Steering Knuckles' meant for heavy and medium commercial vehicles originating in or exported from China PR.

No.15/11/2014-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof;

A. Background of the Case

WHEREAS, on the basis of an application filed by certain domestic producers of the 'Front Axle Beam' (FAB) and 'Steering Knuckles' (SK) meant for heavy and medium commercial vehicles (herein after referred to as subject goods), the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) had initiated an antidumping investigation into the imports of the subject goods originating in or exported from China PR vide Notification No. 14/19/2008-DGAD dated 8th December, 2008. The Preliminary Finding was issued by the Authority vide Notification No. 14/19/2008-DGAD dated 24th April, 2009 and the provisional anti-dumping duties were imposed by the Department of Revenue, Govt. of India, vide Notification No. 65/2009-Customs dated 15th June, 2009. The Final Finding was notified by the Authority vide Notification No. 14/19/2008-DGAD dated 5th March, 2010, recommending imposition of

definitive antidumping duties on the subject goods originating in or exported from China PR. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duties were imposed by the Department of Revenue vide Notification No. 50/2010-Customs dated 12th April, 2010 on the imports of the of the subject goods, originating in or exported from China PR.

- 3. Whereas, in pursuance to the orders of the Hon'ble Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT), vide order No. AD/31-51/2011-AD dated 11th August, 2011, a post-decisional hearing was held on 23rd January, 2012, and after examining the submissions of the interested parties, the Authority confirmed its earlier recommendation for imposition of the definitive anti-dumping duties on the subject goods, from the date of notification issued in this regard by the Central Government, on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject country vide Order No. 14/19/2008-DGAD dated 10th April, 2012.
- 4. Whereas, M/s Bharat Forge Ltd., the domestic producer of the subject goods, filed a duly substantiated application before the Authority, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from China PR and consequent injury to the domestic industry and requested for initiation of a sunset review investigation for continuation and enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR.
- 5. On the basis of duly substantiated application filed on behalf of the domestic industry and in accordance with section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated this sunset review investigation vide Notification No. 15/11/2014-DGAD dated 13th June 2014 to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
- 6. The validity of the antidumping duty on the imports of the subject goods from the subject country was extended by the Central Government up to 14th June 2015, vide Notification No. 30/2014-Customs (ADD) dated 23rd July 2014. On the request of the Designated Authority, the Central Government had extended the time for completion of the above Investigation by three months, i.e., up to 12th September, 2015, in terms of Rule 17 of the AD Rules.
- 7. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

B. Procedure

- 8. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:
 - (a) In terms of sub-Rule 5 of Rule 5, the Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the application for initiation of sunset review antidumping investigation.
 - (b) The Embassy of the subject country in New Delhi was also informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2).
 - (c) The Designated Authority sent copies of initiation notification dated 13th June 2014 to the Embassy of the subject country in India, known exporters from the subject country, known importers and other interested parties, and the domestic industry, as per the information available with it. Parties to this investigation were requested to file questionnaire responses and make their views known in writing within prescribed time limit. Copies of the forwarding letter, petition and questionnaire sent to the exporters, were also sent to the Embassy of subject country along with a list of known exporters/producers with a request to advise the exporters/producers from the subject country to respond to the questionnaire within the prescribed time.
 - (d) Copies of the non-confidential version of the petition filed by the domestic industry were made available to the known exporters and the Embassy of the subject country in accordance with Rules 6(3) supra.
 - (e) Exporters' Questionnaires were sent to the following known exporters from subject country in accordance with the Rule 6(4) to elicit relevant information.
 - (i) M/s. Hubei Tri-Ring Forging Co Ltd.
 - (ii) M/s. Hubei Tri-Ring Auto Axle Co Ltd.
 - (iii) M/s. Hubei Tri-Ring Motor Steering Co. Ltd.

- (f) The People's Republic of China being a Non Market Economy Country, the Authority informed the known exporters from China PR to furnish necessary information/ evidence, as mentioned in subparagraph (3) of paragraph 8 of the Annexure-1 to the Rules to enable the Authority to consider whether market economy treatment should be granted to such cooperating exporters/producers who could demonstrate that they operate under market economy conditions.
- (g) The following producers/exporters exporting the subject goods originating in or exported from the subject country have filed questionnaire responses:
 - (i) M/s. Hubei Tri-Ring Forging Co Ltd.
 - (ii) M/s. Hubei Tri-Ring Auto Axle Co Ltd.
- (h) Questionnaires were sent to the following known importers and consumers of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4):
 - Ashok Leyland Ltd.
 - (ii) Mahindra Trucks and Buses Ltd.
 - (iii) VE Commercial Vehicles Ltd.
 - (iv) Tata Motor Ltd.
 - (v) AMW Motors Ltd.
- (i) Only M/s Ashok Leyland Ltd has filed the importer's questionnaire response as well as certain legal submissions.
- (j) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period, including the POI. The Authority has relied upon the transaction-wise import data reported by DGCI&S source in the present investigation.
- (k) The Authority made available non-confidential versions of the evidences presented by interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Pursuant to the Judgment of the Hon'ble Delhi High Court in the SanDisk matter, and without prejudice to the Appeal filed by the Authority against the said judgment in the Hon'ble Supreme Court, transaction-wise data received from DGCI&S has been placed in the public files after deleting the details of the importers.
- (I) Optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India, based on the information furnished by the petitioner and on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), was worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry;
- (m) The confidentiality claims of various interested parties in respect of the data submitted by them have been examined. The information, which is by nature confidential or which has been provided on a confidential basis by the interested parties, along with non-confidential summary thereof, has been treated as confidential.
- (n) The Authority held a public hearing on 05.03.2015 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of the domestic industry and other interested parties. The interested parties were asked to file their written submissions and rejoinders thereon. The written submissions and rejoinders received from interested parties have been considered in the findings to the extent they are relevant and supported by evidence.
- (o) Consequent upon the change in the Designated Authority another public hearing was held on 11th August 2015 to provide an opportunity to all interested parties to present their views before the new Designated Authority and views expressed by the parties to the investigation in their written submissions subsequent to the public hearing and rejoinders thereon have been taken on record and considered to the extent they are relevant and supported by evidence.
- (p) The Authority carried out verification of the data submitted by the domestic industry as well as the responding exporters in the subject country through on-the-spot verification to the extent considered necessary and feasible.

- (q) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for the findings were disclosed to known interested parties on 28.09.2015 and comments received on the same have been considered in the Final Findings
- (r) Investigation was carried out for the period starting from 1st April, 2013 to 31st March, 2014 (POI). However, the injury investigation covers the period 2010-11, 2011-12, 2012-13 and the POI.
- (s) *** in this disclosure represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- (t) The Authority has taken weighted average exchange rate for the POI (April 2013- March 2014) as Rs 60.85= 1 US\$.

C. Scope of Products under consideration and Like Article

- 9. The products under consideration in the original investigation and as notified in the initiation notification in this review investigation are "Front Axle Beams (FAB) and Steering Knuckles (SK) used in medium and heavy commercial vehicles, whether forged or machined".
- 10. Front axle beam is a safety critical item as it carries the load of the vehicle and also keeps the steering in place. The function of the Front axle beam is to carry the front weight of the vehicle, to carry the horizontal and vertical loads on bumpy roads and acts as a cushion through spring leaves for a comfortable ride. The steering knuckle is a very critical component and fits on the axle beam through the arms to control the steering of the vehicle.
- 11. Front axle beam and Steering knuckles are in the category of "parts or accessories of vehicles" falling under Chapter 87 of the Customs Tariff Act under subheading 8708.10.90. These products can also be imported under several other customs classifications also. Therefore, the customs classifications given here are only indicative, and are no way binding on the scope of the investigation.
- 12. The products, FAB and SK, are first forged out of the steel billets/bars and then machined into the finished product to be fitted into the vehicles. However, the products are sold to the vehicle manufacturers both in forged or machined conditions. While the machined products go directly to be fitted in the vehicles, if the product is supplied in forged conditions, the customer / vehicle manufacturer has to get the forged product machined before fitting into the vehicles. The only difference between the forged and machined product types is the additional machining which is done on the forged product.
- 13. Responding exporter has submitted that the product under consideration and the like article should be selected in such a manner that an apple-to-apple comparison is possible. It has been argued that domestic industry's data shows no imports of forged FAB and forged Steering Knuckles, therefore, it is not understood on what basis the same is included in the product under consideration and how the domestic industry is suffering any injury in absence of any imports of the forged products. It has been further argued that the Designated Authority should examine if the domestic industry is actually producing machined FAB and machined Steering Knuckles. If the domestic industry is not even producing machined subject product, then the entire assertion of injury due to imports of machined subject product is frivolous and should be rejected. The Designated Authority may decide on the correct product scope in light of the above arguments.
- 14. In their post disclosure submissions the exporters and importers have reiterated their position that the forged and machined products cannot be treated as technically and commercially substitutable and therefore, not like products. It has been further argued that the products are custom made as per users' requirements and the domestic industry and the imports cater to different customers.
- 15. The petitioner has claimed that the goods are produced by each producer based on the specifications given by the consumers / automobile manufacturers. There is no significant difference between the products manufactured by them and the subject goods imported from the subject country, which can have any impact on price, usage, quality etc. The petitioner also claims that there is no material difference in the production process between the petitioner and exporters from the subject country. Therefore, the domestic industry has claimed that imported product under consideration and the goods manufactured by the domestic industry are "like articles" within the meaning of the term as per the Rules. It has been claimed that the Designated Authority has come to the same conclusion in the final findings of the original investigation and the present investigation being a sunset review investigation the scope of the products under consideration should be the same as that of original investigation.

- 16. The Authority notes that the domestic industry produces and supplies both forged as well as machined FABs and SKs though during the POI only machined products have been imported. The Authority also notes that the subject goods are first forged and then machined before being used in the medium and heavy commercial vehicles. Some consumers/OEMs buy the forged goods and machine them into finished goods in house or buy the machined product and directly fit them into automobiles. Therefore, forged products are basically one prior stage of the finished machined products and both forged and machined goods are technically and commercially substitutable to that extent. It is a fact that the products are customs made depending upon the models of the vehicles where it is required to be fitted. Depending upon technical and commercial considerations the user industry buys the forged or machined products either from the domestic producers or imports the same. Therefore, irrespective of whether the goods are imported in forged form or machined form they would replace the market for the domestically produced goods. In the earlier investigations the domestically produced and imported goods were treated as like articles *inter se*. Therefore, the Authority holds that front axle beams and steering knuckles manufactured and supplied by the domestic industry and imported from the subject country are like articles for the purpose of this sunset review investigation.
- 17. Front Axle Beams and Steering Knuckles are supplied by the producers and consumed in the automobiles in terms of numbers. However, weight of various types of FABs and SKs vary depending upon type of Automobiles and design specifications and therefore, the cost per piece/unit varies to a very significant extent though per unit cost in terms of weight tends to remain more or less same. Therefore, the Authority had, in the earlier investigation, considered weight as the appropriate common unit of measurement for the purpose of various determination and fair comparison. Same method has been adopted in this investigation also.

D. Domestic Industry and Standing

- 18. The petition has been filed by Bharat Forge Ltd., Pune. The applicant is one of the leading manufacturers of the subject goods in India and supplies the goods to several countries. Other than the petitioner, Tata Motors and Amtek India also produce Front axle beams. In case of Steering Knuckles, the other Indian producers are Mahendra CIE Automotive Ltd., Amtek India and Happy Forging.
- 19. The responding exporters and importers, in their submission, have argued that as per Rule 23(3) read with Rule 11 of the AD Rules, the Designated Authority is required to determine injury to the 'domestic industry'. A prerequisite to this determination is that there exists domestic industry as defined under Rule 2(b) of the AD Rules. Satisfaction of this prerequisite is necessary in a sunset review. Therefore, Designated Authority may examine the standing of the domestic industry in the present case.
- 20. Further responding exporter has argued that production of captive producers cannot be excluded from total Indian production. Captive producers are also domestic producers for the purposes of Rule 2(b) of the AD Rules and what is of importance is the production of the product concerned and not what a producer does with such production. It is immaterial if producer captivity uses its production. In this regard, the exporters have drawn attention to the WTO Appellate Body affirmative ruling in United States Cotton Yarn case, wherein it has been held that captive producers cannot be excluded from the definition of the domestic industry merely because they chose not to sell their full production in the domestic market but used it for their internal consumption
- 21. It has been further argued by the exporters that Petitioner's production does not constitute major proportion of the total domestic production of the subject product and therefore, cannot be regarded as comprising major proportion in the total Indian production for the purposes of Rule 2(b) of the AD Rules. The responding exporters have reiterated their position in their post-disclosure submissions.
- 22. Authority notes that this a sunset review and the requirement under the Rules is to determine the likelihood of continuation or recurrence of injury with respect to the 'domestic industry'. Therefore, the proportion of the domestic producer before the Authority has been examined in the light of the above arguments.
- 23. The petitioner domestic producer is one of the major producers of the subject goods in India. Tata motor is also a major producer of the subject goods but consumes the entire production captively in its automobile line. The subject goods produced by Tata Motors do not enter the commerce of the country and therefore, are not affected by the alleged dumped imports. Therefore, an injury determination with reference to this producer would not carry any meaning. However, without prejudice to this, even considering the captive consumption of Tata motors the share of production of the petitioner company in the total domestic production accounts for over 75% for FAB and over 40% for SK. No other domestic

producers of the subject goods in India, captive or otherwise, have opposed the petition. Therefore, the petitioner clearly commands a major proportion of the domestic production without any opposition from any other domestic producer for the review application. Accordingly, for the purpose of examination of injury and likelihood of continuation or recurrence of injury the petitioner i.e. M/s Bharat Forge Limited has been held to constitute domestic industry in terms of Rule 2(b).

E. Interested Parties to the investigation

- 24. The Authority notes that response to exporter's questionnaire and market economy treatment questionnaire has been submitted by the following two producers from China:
 - (i) M/s Hubei Tri-Ring Forging Co Ltd.
 - (ii) M/s Hubei Tri-Ring Auto Axle Co Ltd.
- 25. Ashok Leyland Ltd. has filed importer's questionnaire and certain legal submissions. The authority has considered petitioner, the two Chinese producers-exporters and Ashok Leyland as the interested parties participating in the present investigations.

F. Miscellaneous issues raised by the interested parties

26. The interested parties to this investigation have raised several general issues with regard to the procedural as well as substantive determination in this investigation. For the sake of brevity the general issues have been summarized below and have been examined to the extent they are relevant. Other issues have been dealt in relevant sections in this disclosure.

F.1 Views of the exporters and importers (other interested parties)

- 27. The exporters and importers (other interested parties) and the domestic industry have raised several issues with respect to the present investigation, including methodologies of dumping determination and injury claims of the domestic industry. While the issues regarding the dumping and injury determination have been dealt in the appropriate places in this disclosure, the general issues raised by the parties to the investigation have been examined hereunder. For the sake of brevity, the submissions of the parties and issues raised therein have been summarized as follows:
- 28. M/s Lakshmikumaran & Sridharan, representing the responding exporters and importer in this case, have *inter alia* raised the following legal and other issues:
 - (a) That the anti-dumping duty in the present case, which expired on 14.06.2014, could not have been revived after its expiry by Notification No. 30/2014-Customs (ADD) dated 23 July 2014, 40 days after expiry of the anti-dumping duty. It has been argued that the parent notification did not contain any saving clause. It did not automatically extend duty by virtue of any provision in the notification. It has been further argued that Delhi High Court judgment in Kumho Petrochemicals Co. Ltd. v. Union of India, 2014 (306) ELT 3 (Del.) has expressly conforms to the above legal principle with regard to extension of anti-dumping duty pending a sunset review. Thus, the notification expired with efflux of time. This investigation is possible, only when there is an anti-dumping duty in force, whose expiry may lead to recurrence. However, where there is no anti-dumping duty in existence, there can be no examination of likelihood of recurrence of dumping and injury.
 - (b) In their post disclosure submissions the interested parties have argued that even though there is a stay on the Hon'ble Delhi High Court's ruling, the principle of law that emanates from the Hon'ble Supreme Court's ruling in *Babu* Verghese & *Ors. v. Bar Council of Kerala & Ors.*, AIR 1999 SC 1281 is still applicable. In the said case Supreme Court categorically held that if a specified time period is to be extended, then an order of extension of time must be passed before the expiry of the original term in order to maintain continuity. It has been argued that in the said matter the Hon'ble Supreme Court further held that on the expiry of the specified time period, any jurisdiction that was previously vested ceases to exist and therefore, the extension is invalidated. This legal principle is squarely applicable in the present case, as the Ministry of Finance had lost its power to extend the anti-dumping duty after expiry of the parent notification on 14 June 2014.
 - (c) That the petition is not duly substantiated since the petition does not contain any evidence with respect to Normal Values and Export Prices. As against express requirement under the law, Petitioner has simply stated that it could not find any price details with respect to the prices in a market economy third country or the constructed normal value in a market economy third country.

Without any submissions on the price or constructed normal value in a market economy third country, the application was clearly incomplete.

- (d) That the Designated Authority acted in violation of Article 5.3 of the WTO ADA by not examining the sufficiency of evidence presented along with the petition and accepting the claims of the domestic industry in respect of construction of the normal value.
- (e) That the consumption norms of the participating exporters must be considered in the present investigation for determination of normal value.
- (f) That the Petitioner has not provided any post POI data to indicate continuance of dumping or injury being caused to it, in order to claim likelihood of recurrence of dumping and injury. Designated Authority may direct Petitioners to file post POI information, and the Designated Authority may examine the same, while carrying analysis on likelihood of continuation or recurrence of injury.
- (g) That no evidence has been provided by the petitioner with respect to various deductions/adjustments for estimation of export prices.
- (h) That the petitioner has stated in the petition that the imports of the subject products are in numbers but the same has been converted into weight. However, no explanation on the methodology adopted in sorting import data and converting import statistics for subject product from numbers to weight has been provided by the petitioner.
- (i) That if the Designated Authority relies on other sources of import data in this investigation, such as DGCI&S or DG Systems, then raw and sorted import data from such sources should also be placed in the public file and provided to interested parties in MS Excel format for proper examination and comments. In this connection these parties have drawn the attention of the Authority to the recent judgment of the Hon'ble Delhi High Court in SanDisk International Ltd. v The Designated Authority & Others case.
- (j) That the petitioner has refrained from providing any meaningful summary of information provided by it on confidential basis. In addition, the petitioner has failed to provide a statement of reasons why information provided on confidential basis is not susceptible to summarization. This has restrained the respondent in providing meaningful comments on the injury aspects.
- (k) That information in Format A and Format CI can easily be provided in indexed form so as to indicate a trend for POI and previous years. Certain parameters in Proforma IVA such as investment, net worth, and capital investment for expansion, sale value and cost of sales for exports have been kept confidential and no indexed figures have been provided for such parameters.
- (I) That no information is provided in the petition with respect to non-injurious price or price underselling analysis. It is very much likely that Petitioner has not determined non-injurious price based on principles enunciated under Annexure III of the AD rules.

F.2 Views of the Domestic industry

- 29. The domestic industry, in its various submissions, has refuted the arguments of the interested parties. The submissions of the domestic industry have been summarized as follows:
- (a) That the contentions of the interested parties, such as insufficient disclosure in the petition or consideration of surrogate country or insufficiency of evidence/information in the petition etc., are preliminary issues and should have been raised while responding to the initiation notification. The opportunity of post hearing written submissions cannot be used to raise these issues for the first time. These issues were not raised in the oral hearing. This is clearly an abuse of the liberty for written submissions granted by the authority Therefore, the Authority should reject all such submissions. In this connection the domestic industry has drawn the attention of the Authority to the WTO Panel decision in US-Hot Rolled Steel matter in which the Panel observed that the 'ample' and 'full' opportunities guaranteed by Articles 6.1 and 6.2, respectively, cannot extend indefinitely and must, at some point, legitimately cease to exist. This point must be determined by reference to the right of investigating authorities to rely on deadlines in the conduct of their investigations and reviews.
- (b) That the judgment of the Delhi High Court on the issue that the duty cannot be extended after expiry of existing duty, has been challenged in the Hon'ble Supreme Court and has been stayed.

- (c) That the investigations were initiated on the basis of duly substantiated request for initiation of a sunset review. The law certainly does not require the domestic industry to provide such detailed information which is required for final determination at the stage of application or initiation. Only prima facie evidence of dumping, injury and causal link is required for initiation of investigations or reviews. The Designated Authority is not required to have in record all such information as is required for making a determination at the stage of initiation itself. It has been further argued that in certain jurisdictions the Authorities initiate the investigations suo moto. Such being the case, there is no substance in the arguments.
- (d) That both the exporter and the importer have responded to the Authority. It is not the argument of the exporter or importer that the volume and price of imports reported by the petitioner is exaggerated. In fact, the factual position would perhaps be that these are understated, as it is normally found that the volume of imports reported in Indian data sometimes does not include some import transactions.
- (e) As regards the contention that the petitioner has not specified the weight adopted by petitioner, the import data enclosed with the petition clearly contains information with regard to both numbers and weight.
- (f) That the petitioner has claimed only such information as confidential, confidentiality of which is protected under the law.
- (g) That the Designated Authority should direct the exporter and importer to disclose import information to all interested parties on actual basis with respect to Import date, Import description, Import volume, Import value and Port. Further, any party can seek information from DGCI&S under RTI. The domestic industry can also seek the above information from DGCI&S after obtaining consent of the Designated Authority. Such being the case, there is no basis for claiming this information as confidential information.
- (h) With regard to the contention that Section VI Costing information has been claimed confidential, the petitioner submits that the exporter has also claimed all these information as confidential.
- (i) That as far as investment and net worth are concerned, petitioner has provided information with regard to capital employed and return on capital employed. The parameter laid down under the law is return on capital employed and that information has been provided by the petitioner. As regards sale value, the same as injury parameter is not adopted by the Authority. As regards cost of sales for exports, the same is entirely irrelevant for injury assessment. As regards capital employed for expansion, the petitioner has made submissions in this regard.
- (j) That the application performa nowhere requires the petitioner to provide information with regard to non injurious price and price underselling. The application Performa merely requires the petitioner to provide costing information. In fact, non injurious price is required to be determined by the Authority and not by the domestic industry in the same manner as the exporter questionnaire does not require the exporters to determine dumping margin. Even if the petitioner had determined injury margin in the petition, the same does not create an obligation on the domestic industry to determine the same at every stage of the proceedings.
- (k) That as regards the standard of evidence at the time of initiation, in many jurisdictions the sunset reviews are initiated suo moto by the Authorities concerned without any substantiated petition and do not prescribe an elaborate procedure for initiation of such investigations. Therefore, the arguments of the interested parties are frivolous and without merit.

F.3 Views of the Authority

- 30. Various miscellaneous issues raised by the interested parties have been examined and addressed as follows:
 - a. The interested parties have contended that anti-dumping duty cannot be continued by Ministry of Finance after expiry of existing anti-dumping duty. The Authority notes in this regard that the decision of Hon'ble Delhi High Court was challenged before Hon'ble Supreme Court and the Hon'ble Court has granted an interim stay on the operation of the orders of the Hon'ble Delhi High Court. In the present case, the investigation was initiated before expiry of the duty. In similar situations the Hon'ble Delhi High Court has upheld initiation and continuation of the sunset review investigations. As far as the application of the ratio of the judgment in Babu Verghese case, as citied by the interested parties in their post disclosure statements, is concerned, the Authority notes that the matter is pending before the Hon'ble Supreme Court and this issue may be agitated by the interested parties before the Hon'ble Court.

- b. As regards, the contention that the petition was not duly substantiated and did not contain the evidence of normal value in market economy third country, the Authority notes that there was sufficient prima facie evidence in the petition showing continued dumping of the product under consideration and likelihood of continuation of dumping and injury to justify initiation of the sunset review investigation.
- c. As regards import data and the methodology applied for sorting the import data, Authority notes that the producer /exporter from China and the importer in India are participating in the present investigation. Majority of the import transaction pertains to the exports made by Chinese producer/exporter and Indian importer. The description mentioned in the import data enclosed in the petition should have itself enabled these parties to offer their comments on the volume and value of imports. However, the Authority has taken note of the actual volume and value of imports reported by the responding producer/exporters in the subject country for the examination. Transaction-wise import data used by the Authority has also been placed in the public folder, notwithstanding the appeal pending before the Hon'ble Supreme Court in this regard, which has provided adequate opportunity to the Authority to comment on the volume and value of imports.
- d. As regards the contention that the petition did not contain the conversion factor used for converting imports on weight basis, it is noted that import data submitted by the petitioners shows both numbers and weight and therefore, it was possible for the interested parties to know the conversion factor adopted by petitioner and comment on it. In any case the unit weights of the products as reported by the cooperating exporters have been used for such conversion.
- e. As regards submissions of both opposing parties concerning confidentiality of information, the Authority notes that the claims of confidentiality, by the parties supplying information, have been admitted considering the legal provisions in this regard, and justification given by the parties claiming confidentiality and the past practice of the Authority in this regard. The information which is by nature confidential or disclosure of which will adversely affect the interests of the party supplying the same have been treated as confidential.
- f. As regards absence of NIP figures in the petition, the authority notes that NIP claimed by the petitioner is confidential business information of the domestic industry which could not have been disclosed by the petitioner. Final NIP is determined by the Authority taking into account the principles laid down in the Rules even though the domestic industry has liberty to make a claim in this regard.
- g. As regards historical return on capital employed, the Authority notes that the historical return on capital employed earned by the domestic industry is in fact significantly higher than the actual return earned by the domestic industry in the POI and reasonable return on capital employed allowed by the authority. Both domestic industry and opposing parties have claimed adoption of the past return on capital employed. The Authority has however, adopted 22% return on capital employed as per its consistent practice.
- h. As regards the contention that the petition has frivolous basis for normal value, export price and dumping margin, the Authority notes that this being a sunset review investigation what is material is the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. The petition contained sufficient information with regard to continuation of dumping and injury to justify initiation of sunset review. The quality of data and standard of determination improves as the investigation progresses.
- i. As regards various price adjustments claimed in the petition, the Authority notes that even if the preliminary information provided by the petitioner were estimated values, these expenses have now been considered on the basis of questionnaire response filed by the Chinese producer/exporter. It is noted in this regard that petition contains only prima facie information and evidence to allow Authority to determine whether there is sufficient justification for initiation. Final determination is based on factual information made available to the Authority by the interested parties during the course of the investigation.
- 31. All other issues raised by the parties to the investigation have been dealt in the respective sections in this finding to the extent they are relevant.

G. Methodology of Determination of current Dumping

G.1 Legal Positions

32. Section 9A (5) of Customs Tariff Act, 1975 provides that:-

"The anti-dumping duty imposed under this Section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition:

Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension:

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the Antidumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year."

- 33. Accordingly, in a sunset review investigation the Authority is required to examine:
 - Whether the dumping continues after imposition of the antidumping duty and if so, whether it is likely to continue;
 - In cases where dumping did not continue, whether the dumping would recur in the event of revocation of anti-dumping duties;
 - Whether the domestic industry continued to suffer material injury and if so, whether injury to the domestic industry is likely to continue if the duties are removed;
 - In cases where the domestic industry has not suffered continued injury, whether injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti-dumping duties.
- 34. Therefore, the Authority has first proceeded with the examination whether dumping of the subject goods continues from the subject countries and whether the domestic industry continues to suffer material injury on account of such dumped imports before examining whether dumping is likely to continue or recur if the duties are revoked, and injury is likely to continue or recurrence in such a situation.

G.2. Examination of Continuation of Dumping: Determination of Normal Values, Export Prices and Dumping Margins

35. The Authority notes that two producing exporters from China have submitted their questionnaire responses and have claimed market economy status. The views of the exporters with regard to determination of dumping margins have been summarized below.

G.2.1 Views of exporters and Importers / other Interested Parties

- 36. The responding exporters and importers, in their various submissions, including their post disclosure submissions, have disputed the claims of dumping and methodology proposed by the domestic industry and adopted by the Authority for determination of normal value in China and have *inter alia* argued as follows:
 - (a) That though the responding exporters demonstrated their market economy status in the original investigation the Designated Authority decided not to grant MET status to Responding exporters on two grounds i.e., there is significant State share-holding in the Hubei Group and therefore Government interference cannot be ruled out; and Price of steel in China PR does not reflect market values. It has been argued that a mere Government shareholding would not by itself mean that the Government is interfering in the affairs of the company. The WTO Appellate Body in the case of United States Definitive Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Hot Rolled Products from China, DS379/AB/R dated 11.03.2011 has categorically held that a mere shareholding by Chinese government in an enterprise does not by itself prove that there existed government control in the enterprise.
 - (b) That the phrase 'state interference' in the statute should be interpreted to mean interference of the Government as a Legislator. The Chinese Government, in holding shares in the exporter companies, is acting as an investor and not as a legislator. The fact that the Chinese Government has appointed directors in its capacity as an investor and not as a legislator shows that there was no legislative interference in appointment of directors.

- (c) That the price of steel in China PR reflects market values. In fact, in earlier investigations, the Designated Authority has regarded the prices of steel in China PR to be at par with international prices and accorded market economy treatment to Chinese producers that use steel as raw material.
- (d) that Hon'ble Supreme Court in Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. v. Exide Industries Ltd. and others, (2005) observed with affirmation that the Designated Authority can resort to the last alternative in Para 7 of Annexure I of the AD Rules, only when the first two methods have been exhausted. Therefore, the Designated Authority is mandated to arrive at normal value in cases of exports from non-market economy countries such as China in this case, by first exhausting the main options of using the price or constructed value in a market economy third country or the price from such a third country to other countries including India. Only when the first two options have been exhausted, the Designated Authority may apply any other reasonable basis to arrive at the normal value including prices paid or payable in India giving due account to reasonable adjustments.

G.2.2. Views of the Domestic Industry

- 37. The petitioner domestic industry has submitted that China being a non market economy, normal value of the subject goods in that country cannot be determined on the basis of price prevailing in that country and therefore, needs to be constructed. With regard to determination of a normal value in China the domestic industry has *inter alia* argued that:
 - a. China is a non-market economy and has been treated as such by European Union and United States as well as by this Authority in the past three years. Even China agreed in the accession treaty that WTO Members could use an NME presumption till December 11, 2016.
 - b. That AD Rules have prescribed certain conditions that have to be satisfied in order to establish the claim of market economy treatment. It is to be noted that each and every condition must be fulfilled by a responding exporter in order to claim market economy treatment. Except where the responding Chinese exporters confirm to each of these standards, the Designated Authority is required to determine normal value in accordance with Para 7 of Annexure-I to the AD Rules.
 - c. That based on various pronouncements relating to examination of market economy status by India and other investigating authorities, certain jurisprudence has clearly emerged and Market economy status cannot be granted unless the responding exporters satisfy/establish certain conditions, which inter alia include:
 - i. That there is no major state ownership/control;
 - ii. That the prices of major inputs substantially reflect market values prevailing in the international market;
 - iii. That their books are audited in line with international accounting standards
 - d. That market economy status cannot be granted to a responding exporter in China unless Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the rules. It is for the responding Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions. Market economy status cannot be granted unless the responding company and its group as a whole make the claim. If one or more companies forming part of the group have not filed the response, market economy status must be rejected.
 - e. That in the original investigations, two exporters, Hubei Tri-ring Auto-Axle Co., Ltd. (manufacture and exporter of 'Front axle beam') and Hubei Tri-Ring Forging Co., Ltd. (manufacture and exporter of 'Steering knuckles'), had responded and claimed market economy treatment. However, the Authority had not granted market economy to these exporters in view of significant State-share holding, inability of the Chinese companies to establish that inputs price substantially reflect the market values and also considering that prices of steel in China cannot be stated to be reflecting the market values. The factual matrix remains the same since the original investigations. Therefore, the Chinese companies should be considered as not entitled for market economy treatment.
 - f. That in the original investigations, the Authority had not granted market economy treatment to these exporters from China and determined the normal value in China on the basis of the constructed normal value based on the estimated cost of production of the subject goods in China with reasonable profit in terms of Para 7 & 8 of the Annexure 1 to the said Rules as amended. Authority

should consider the same methodology to calculate the normal value for China PR in the current investigation.

- g. That the Authority further noted in the previous investigation that while disputing the claim of the domestic industry to treat Chinese producers as non market economy, the Chinese producers, or importers or any other interested party made no claim nor advanced any evidence either with regard to price or constructed value in a market economy third country.
- h. Price actually paid in India could not have been considered for the reason that the same were below cost of production. Thus, the only option with the Authority is to consider cost of production in India, duly adjusted, to reflect international raw material prices and optimum conversion costs, selling, general & administrative expenses and reasonable profit. This approach has been upheld by the appellate Tribunals and Courts. Therefore, there is no merit in the arguments of the interested parties.
- i. That the petitioner has not stated that the Designated Authority should not adopt cost or price in market economy third countries. Petitioner has in fact proposed market economy third countries.
- j. That in the original investigation the Authority noted that Prices from market economy third country to India could also not be adopted for the reasons that (a) the product under consideration involved a number of different types which vary in associated costs & prices; (b) price adjustments to determine ex-factory prices were not available, (c) these prices could not be considered representative given the claims that prices from third countries to India were inappropriate due to dumping from China.
- k. That the Authority had provided adequate opportunity to the interested parties to provide information for determination of Normal value as per alternative methods in the Rules. None of the interested parties has provided any positive information in this regard. Therefore, the conduct of the interested parties is clearly to impede the process of investigations rather than cooperating with the Authority in this regard.
- Therefore, normal value in China can be determined on the basis of (a) price in India, and (b) cost of
 production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and profit.
 Normal Value in China should be determined on the basis of cost of production in India, duly
 adjusted.
- m. The normal value in China may be constructed by considering international price of the raw material and adopting the consumption norms and conversion cost as per the best information available, including that of the domestic industry.
- n. The domestic industry has strongly disputed that the consumption norms of the exporters must be accepted. It has been submitted that this argument is highly flawed unless the Authority comes to a conclusion that the exporter is entitled to market economy treatment.
- o. As regards various adjustments the domestic industry has submitted that petitioner has provided information on the basis of estimates as the relevant information is with the exporter or the importer and is therefore not publically available. It is absurd to expect such evidence from the domestic industry when the relevant documents are in possession of the exporter or importer.
- p. The petitioner has estimated separate dumping margins for forged and machined products owing to significant cost and price difference between the two. However, both the products have been imported in machined form only in the current injury period and the dumping margins are significant and above *de minimis* levels.

H. Examination of the issues and Determination of Normal Value

38. The Authority notes that as per the import data analyzed, China has exported only 279 MTs of Front Axle Beam (Machined) and 181 MTs of Steering knuckles (Machined) to India during the POI. M/s Hubei Triring Forging Co. Ltd. (HTRF) has filed the questionnaire response as an exporter of Steering Knuckles and M/s. Hubei Tri-ring Auto Axle Co. Ltd. (HTRA) has filed a questionnaire response as exporter of Front Axle Beams. Both the producing exporters are related and have filed Market Economy Treatment Questionnaire Response claiming MET and determination of normal value on the basis of sales in the home market. During the POI HTRF has exported ****MT of Steering knuckles to India and HTRA has exported *****MT of Front axle beam to India. The responding producing exporters in their submissions have inter alia claimed that

- a. They are the largest producers in China in respect of FAB and SK. Though exports to India have reduced due to imposition of antidumping duty, Indian customers continue to import the product under consideration from the exporter because of better quality of the product and inability of the Indian producers to meet the demand.
- b. Their manufacturing process differs from the petitioner's manufacturing process.
- c. HTRA has claimed that they combine 'roll forming' with 'hot press' to manufacture FAB on a large scale. The difference in product exported to India and sold in domestic market or to other countries by HRTA is in respect of material, load, weight or difficulties of process.
- d. HTRF has claimed that the investment required for the process used by them to manufacture Steering Knuckles is lower and the cost is also lower. HTRF has also claimed that they use advance die repair method using different welding material that enhances the life of the die resulting into lower running cost per unit of finished product. Further, the steel specification used by Indian manufacturer is costlier.
- 39. Verification of the Market economy claims of both the producing exporters and other data submitted by them was carried out through on-spot investigation.

H.1 Examination of Market Economy Claims of the responding exporters

- 40. As per Paragraph 8, Annexure I to the Anti-dumping Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China provide(s) information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 and prove to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:-
 - a) The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
 - b) The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
 - c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and
 - d) The exchange rate conversions are carried out at the market rate.
- 41. The Authority notes that these two producing exporters are related and operate under common ownership. These Companies had claimed market economy treatment in the original investigations also. But they were not granted market economy status treatment because of several reasons. However, Market economy claims of the responding exporters in this investigation have been examined afresh with reference to the above Rules.

(i) M/s Hubei Tri-ring Auto Axle Co., Ltd., China PR (HTRA)

42. The market economy claims of HTRA have been examined and it has been noted that during the POI, two major shareholders i.e., M/s Hubei Tri-ring Heavy Industry Co. Ltd. and M/s Tri-ring Group Company Ltd. owned ***% and ***% shares of HTRA respectively. It is further noted that Tri-ring Group Company Ltd. wholly owns Hubei Tri-ring Heavy Industry Co. Ltd. Tri-ring Group Company Ltd. in turn is a state owned company. Individuals owned the remaining ***% shares of TRA. However, post POI, this situation has changed, as Hubei Tri-ring Heavy Industry Co. Ltd and Tri-ring Group Company Ltd. now own ***% shares of TRA. Post POI, Hubei Tri-ring Heavy Industry Co. Ltd owns ***% shares of TRA, as it bought ***% shares that were earlier held by individuals. But Tri-ring Group Company Ltd. still maintains ***% shares in TRA. Therefore, the Company is now a wholly State owned enterprise. It is also noted that out of 7 Directors on the board of TRA six are appointed by Tri-ring Group Company Ltd. which is a State Owned Enterprise. Therefore, the Company is fully owned and controlled by the Government. It is also

further noted that the major raw material i.e., steel is procured by HTRA from two related State-owned entities along with other unaffiliated private entities.

(ii) M/s Hubei Tri-ring Forging Co., Ltd., China PR (HTRF)

- 43. The Authority notes that during the POI, M/s Hubei Tri-ring Heavy Industry Co. Ltd. owned ***% shares in HTRF and the labour union of HTRF owned ***% shares in HTRF. It is further noted that M/s Tri-ring Group Company Ltd. wholly owns Hubei Tri-ring Heavy Industry Co. Ltd. Tri-ring Group Company Ltd. in turn is a state-owned company. Individuals owned the remaining ***% shares in TRF. This situation has not changed Post POI. It was also noted that out of seven directors on HTRF's board, six were appointed by Tri-ring Group Company Ltd. The seventh director, a private individual, owns certain shares and is also the chairman of the board. Therefore, the Authority notes that the Company continues to a State controlled and managed company though few shares are in the hands of one private individual as per records.
- 44. The major raw material for production of SK is alloy steel bar and one of the major suppliers for this is M/s ***Co., Ltd. who is the agent of M/s ***Co., which is the subsidiary of Tri-ring Group Co., Ltd. The company is responsible for cooperating with another related company M/s *** Co., Ltd to purchase raw materials for Group subsidiaries. Two other Private Companies also supply the steel bars to TRF. However, the procurement of raw materials is skewed in favor of the State-owned related companies.
- 45. The above examination shows that both the responding exporters are under state ownership and control. The Authority notes the arguments of the interested parties that mere State holding *per says* would not amount to State interference in the affairs of the Company. It has also been argued that earlier the Authority had accorded market economy status to certain Steel producers in China. Therefore, it cannot be held that the main raw material in China does not reflect true market condition.
- 46. In this connection the Authority notes that examination of market economy condition is an overall assessment taking into account several factors including ownership and decision-making process of the Company and other such other issues such as prices of raw material prices etc. Though the ownership per se is not the determining factor, it is an important factor which is examined along with the decision making process in the commercial activities. In the instant case the board is overwhelmingly occupied by the Govt. nominees without any independent member. The Authority also notes that in the recent investigation in hot rolled steel products the producers in China have not been given market economy status thereby clearly establishing that the raw material prices in China does not reflect true market condition. The exchange rates and interest rates continue to be largely managed by the Government and do not reflect true market condition.
- 47. In view of the above the Authority notes that there is significant State control in the responding producing exporters and the prices of major raw materials used in the production of the subject goods by the above Companies does not reflect true market values due to affiliated purchases as well as existence of general non-market economy condition in the country. Therefore, the Authority holds that the cost and prices of the Company in the domestic market do not reflect market economy condition and cannot be used for determination of normal values of the subject goods in China. These arguments reiterated by the exporters in their post disclosure submissions have not been found to be tenable in view of the above analysis.

H.2. Determination of Normal Values

- 48. Since the Authority holds that the cost and prices of the responding exporter in the domestic market do not reflect true market situation the Authority turns to the other alternative provisions in the Rules for determination of the Normal Values in China.
- 49. Para 7 of the Annexure I to the Anti-dumping Rules. Para 7 of Annexure-I reads as follows:
 - "7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection.

Account shall also be taken within time limits, where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

- 50. In this connection the Authority notes the arguments of the interested parties that the Authority should first examine the first and second option in Para 7 of Annexure-I of the AD Rules before exercising the third alternative. In this regard the Authority notes that none of the interested parties have provided any meaningful information for selection of an appropriate third country as a surrogate for construction of the normal value on the basis of cost and prices in that country or price from such country to other countries, including India, as the normal value in China as per the first two alternatives in the Para-7 referred above. The Authority also notes that there is no import of the subject goods from any other country during the POI. Therefore, prices from no other country could be adopted for determination of the Normal value in China as per the above provision.
- 51. In view of the above, the Authority has determined the normal value in China as per the third alternative provided in the Rules referred above. The Authority notes that the domestic industry has argued that the consumption norms of the exporter cannot be considered for construction of cost of production and normal value unless the exporter is granted full market economy treatment. In this connection the Authority notes that the consumption is a factor of technology used and efficiency achieved and has nothing to do with the commercial aspects which are affected by non-market economy condition. Therefore, if the consumption norms of the responding exporter are found to be properly documented and verified from the records of the exporter it cannot be ignored while constructing the costs by adopting the other factors from other sources.
- 52. The Authority notes that the responding exporters have claimed certain difference in production process used by them compared to the production process adopted by the domestic industry. HTRA employs prerolling in the production process, which brings the hot round bar into a preliminary shape of an axle beam. Thereafter, at pressing stage, only 2500 MT press is employed to bring the hot bar to the final shape. It has been claimed that this roll forging process significantly reduces the requirement of using a heavy press during pressing stage and also reduces the consumption of material due to less scrap generation in the form of trimmings. HTRF's production process of the subject goods involves use of a 250 KJ program-controlled hydraulic hammer. TRF has claimed that there are three advantages of using hydraulic hammer for forging: (i) A wide product range of steering knuckles could be forged in hammer forging; (ii) It uses lesser energy; and (iii) Investment required for the process is low compared to conventional press forging process.
- 53. As regards contention of the exporter concerning the difference in manufacturing process, the Authority notes that though the production process used by the responding exporter has certain differences as outlined above it could not be demonstrated whether it actually translates to savings in terms of unit cost of production. However, the savings in terms of less wastage as verified and reflected in its consumption norms has been considered for determination of the normal values. To that extent the differences in production process have been given due consideration. In any case, the normal value has been determined in terms of per kg for fair comparison and there is not much difference in the input/output ratio/consumption norms of the domestic industry and the exporter.
- 54. In their post disclosure submissions the exporters have argued that the consumption norms and raw material prices of the responding exporters should be considered for construction of the normal value as the domestic industry also procures the raw materials from the same suppliers in China. It has also been argued that interest costs and packaging costs should be excluded from the construction of the normal values. In this regard the Authority notes that the normal values have been constructed as per the consistent practice of the Authority. As far as raw materials is concerned, if the domestic industry procures the goods from the same supplier in China at similar prices the raw material prices of the exporters have been captured in the constructed normal value to that extent.
- 55. Accordingly, the Normal value of the product types of FAB and SK imported during the POI has been determined after due consideration of the consumption norms of the responding exporters and the domestic industry's most efficient norms achieved during the injury period for the imported FAB and SK in machined conditions. Wherever, a particular model was not produced by the Domestic Industry during the POI consumption norms of the exporter have been adopted. Main raw material used in the production

of the subject goods is carbon steel/alloy steel of specific grades for which reliable international prices were not available. Therefore, the raw material purchase prices of the domestic industry have been adopted. Cost of utilities has been considered as per the best consumption norms of the domestic industry. All other elements of cost are based on the optimum production of the domestic industry. A normal profit of 5% on constructed cost has been provided to arrive at the Constructed Normal Value as per the consistent practice of the Authority.

56. During the period under consideration the exporters from China had exported only two types of FAB and SK i.e., FA90 and FA99 in machined form. Since only machined products have been exported during the POI normal values for these two types of FAB and SK in machined form have been determined for like to like comparison with the export products. The constructed normal values have been worked out as follows:

CNV USD/Kg	SK (Machined) FA90	SK (Machined) FA99	FAB (Machined) FA90	FAB (Machined) FA99
	US\$/Kg	US\$/Kg	US\$/Kg	US\$/Kg
Raw Material cost as per International Prices	***	***	***	***
Cost of Utilities	***	***	***	***
SGA including Interests (net of credit of scrap value)	***	***	***	***
Cost to make and sale	***	***	***	***
Profit	***	***	***	***
Constructed Normal Value (US\$/Kg)	***	***	***	***

H.3. Export Prices

Export Price of M/s Hubei Tri-ring Auto Axle Co., Ltd., China PR (HTRA)

57. During the POI HTRA had exported only Machined Front Axle Beams directly to only one customer in India i.e., Ashok Leyland Ltd. and 3915 Pcs of FAB weighing 331.210MT were exported to India. Two different types of FABs have been exported to India during this period i.e., FA90 and FA99/FVDP. The transactions were in CNF term. The transactions and the adjustments required to bring them to ex-works were verified during the on-spot investigation. It is noted that VAT refund rate on export of the subject goods is 17%. Therefore, no adjustment towards VAT is required. Accordingly, the net ex-works export price for FAB has been determined as follows:

Product Code	Sum of Quantity in Kgs Net weight	Sum of Net invoice value USD	Sum of Inland transport (USD)	Sum of Port and other export related expenses USD	Sum of Non- returnable wooden packing cost (USD)	Sum of Ocean Freight (USD	Sum of Bank Charges USD	Sum of Credit cost (USD)	Net Realisation in USD	Net EP USD/Kg
FA90	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
FVDP/ FA99	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Grand Total	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

58. In their post disclosure comments the exporter has submitted that Designated Authority is requested to adopt inland transportation, ocean freight and bank charges as reported by the cooperating exporter in determining the ex-factory export price for FAB. In this connection the Authority notes that the direct selling expenses, as reported by the exporter and verified has been duly converted to US\$ adopting daily exchange rate as reported in the questionnaire response and the same has been correctly adopted for determination of the export prices.

Export Price of M/s Hubei Tri-ring Forging Co., Ltd., China PR (HTRF)

59. During the POI TRF had exported only Machined Steering Knuckles to only one customer in India i.e., M/s Ashok Leyland Ltd. *** Pcs of Steering Knuckles weighing ***MT were exported during the POI. Two types of Knuckles i.e., FA90 and FA99 were exported to India during this period. The transactions were in CNF term. The transactions and the adjustments required to bring them to ex-works were verified during the on-spot investigation. It is noted that VAT refund rate on export of the subject goods is 17%. Therefore, no adjustment towards VAT is required. Accordingly, the net ex-works export price for Steering Knuckles has been determined as follows:

Row Labels	Sum of Product weight (kg)	Sum of Net invoice value (USD)	Sum of Inland transport ation (USD)	Sum of Packing expenses (USD)	Sum of Port and other export related expenses (USD)	Sum of Ocean Freight (USD)	Sum of Bank charges (USD)	Sum of Credit Cost (USD)	Net Export Value USD	Net EP USD/Kg
FA90 Steering Knuckle	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
FA99 Steering Knuckle	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Grand Total	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

H.4. Dumping Margin

60. The ex-works constructed normal values and the net-ex-works export prices, so determined, have been compared to determine the dumping margin for the responding exporters from China as follows:

Dumping Margin TRA

Product Type	Qty in Kgs	NV US\$/MT	EP US\$/MT	DM US\$/MT	DM value	DM%	DM Range
FA90	***	***	***	***	***	***%	
FA99	***	***	***	***	***	***%	
Total	***	***	***	***	***	***%	10-20%
Dumping Margin	n TRF	<u> </u>					
Product Type	Qty in (kg)	NV US\$/Kg	EP US\$/Kg	DM US\$/Kg	DM Value	DM %	DM Range
FA90 Steering Knuckle	***	***	***	***	***	***%	
FA99 Steering Knuckle	***	***	***	***	***	***%	
Grand Total	***	***	***	***	***	***%	0-10%

H.5. Dumping Margin for other Exporters from China

61. Dumping Margins for other exporters from China PR has been determined on facts available basis as follows:

	NV US\$/MT	EP US\$/MT	DM US\$/MT	DM%	DM Range	
FAB	***	***	***	***%	40-50%	
SK	***	***	***	***%	5-15%	

62. The current dumping margins determined for both the products are above de minimis and significant.

I. Methodology and Determination of Injury and Causal Link

63. As noted earlier, in a sunset review investigation, with regard to injury examination, the Authority is required to examine:

- Whether the domestic industry continued to suffer injury and if so, whether injury to the domestic industry is likely to continue;
- In cases where the domestic industry has not suffered continued injury, whether injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti-dumping duties.
- 64. The domestic industry has *inter alia* submitted that there is continued dumping of the product under consideration from China PR though the volume of dumped imports has declined as a result of current anti-dumping duties and dumping is likely to intensify should the current anti-dumping duty be revoked.
- 65. Therefore, the Authority has first examined whether the domestic industry continues to suffer material injury on account of dumped imports from the subject country before proceeding to examine the likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry in the event of revocation of the duties from the subject country. Examination of material injury to the domestic industry is in accordance with the Article 3 of the AD Agreement and Annexure II to the AD Rules, 1995.
- 66. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure –II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, ".... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
- 67. The Authority notes that the application for continuation of antidumping duty has been filed by M/s Bharat Forge Limited, who commands a major proportion of total production of the subject goods in India. In terms of Rule 2(b) of the Rules, the petitioner has been treated as the domestic industry for the purpose of this investigation. Therefore, for the purpose of this determination the cost and injury information of the petitioner, constituting the domestic industry, as defined in Rule 2(b), has been examined.

I.1. Views of the responding Exporters and Importers on the injury claims of domestic industry

- 68. The responding exporters and importer, in their various submissions, have inter alia argued
 - That in a sunset review the focus of the entire investigation is on the fact whether revocation of antidumping duty will lead to recurrence of dumping or injury to the domestic industry. Thus, it is not the present level of dumping and injury, which is important but the likely dumping and injury, which is more essential in a sunset review investigation. Thus, an investigating authority has to conduct an analysis of future events to determine likelihood of dumping or injury. However, in the present investigation, petitioner has not provided any post POI data to indicate continuance of dumping or injury being caused to it, in order to claim likelihood of recurrence of dumping and injury.
 - That the petitioner has failed to substantiate likelihood of recurrence of dumping & injuries in future, if the anti-dumping duties are revoked.
 - That the DA should determine non-injurious price based on principles enunciated under Annexure III of the AD rules. The DA should consider the best capacity utilization over the past three years and period of investigation, while arriving at the non-injurious price. Further, it would be quite unjustified on the part of the domestic industry to claim an exorbitant rate of return and the Designated Authority to allow such return. Only historical return of the domestic industry should be considered to determine the RoCE which should be adopted in arriving at the non-injurious price. Only those loans that relate to or may be apportioned to subject product should be taken into account while determining non-injurious price.
 - That the import data on Front Axle Beams and Steering Knuckles makes it abundantly clear that imports of the subject product are declining sharply and there is no indication that this trend will change. Imports of Front Axle Beams comprise a meager 3.12% of domestic sales and only 1.48% of total Indian demand in the POI. Similarly, imports of Steering Knuckles comprise only 1.98% of total Indian demand in the POI. It is not understood how such low volumes of imports can cause injury to the Domestic Industry.

- That the data from the petition clearly reveals that prices of imports have been rising both for Front
 Axle Beams and Steering Knuckles. However, it is surprising that the Domestic Industry is not able to
 increase its prices despite low volume and high prices of imports. It is inconceivable to think that
 extremely low volumes of the subject product had anything to with the low prices of the Domestic
 Industry.
- That there is no causal link with respect to low imports volume and the prices of the Domestic Industry. Respondents submit that only due to certain intrinsic factors, the Domestic Industry is suffering injury. But such injury cannot be attributed to imports of the subject product. Further, the Domestic Industry has already admitted that it was due to recession that demand of the subject product reduced. Injury due to recession cannot be, therefore, attributed to imports of the subject product.
- That the Petitioner's Profit/Loss, cash profit and PBIT are declining even though imports of the subject products have considerably declined over the injury period. In light of the above, causal link is not established in the subject investigation. Further, other domestic producers have taken considerable share in the domestic market, thereby reducing Petitioner's market share considerably.
- That the Petitioner continues to focus on export markets, while it could have taken steps to increase
 its market presence in India. Petitioner cannot take the plea that it is disposing its inventories in the
 export market because Petitioner does not have any inventory of the subject product, as the subject
 product is made to order.
- That there is a high burden upon the Designated Authority to discharge with regard to fulfilling the standard of analysis required under Article 11.3. More specifically, post POI data must be taken into consideration while undertaking an analysis under Article 11.3. It is crucial that this requirement is complied with in the present matter because no injury has been proven to exist and the Designated Authority must carry out the due projections to justify any extension of duty. Any review carried out without fulfilling this basic requirement in the present matter would be a contravention of all regulations and laws pertaining to sunset reviews.
- That the petitioner has failed to demonstrate certain other additional factors that could have caused injury and therefore, DA should examine those factors such as decline in production and sales due to recession; and exchange rate considerations.
- That despite adequate protection, the Domestic Industry is deceptively claiming likelihood of recurrence or continuation of dumping and injury in the present case without any supporting data. Domestic Industry does not require any unfair protection and therefore, the Designated Authority should terminate the present sunset review.
- That the injury, if any, is either due to *inter se* competition in the Indian market or due to reasons intrinsic to the Domestic Industry. Other Indian producers are able to maintain their sales steadily over the injury period and have, in fact, captured the market share of the Domestic Industry.
- That another reason for Domestic Industry's declining sales is recession in the automobile sector.
 Decline in sales of machined subject product is due to weak demand for machined subject product.
- That the Domestic Industry's claim of injury due to imports of forged subject product is unfounded and should be rejected, as there are no imports of forged subject product.
- The prevailing exchange rate is higher than that of POI. Imports into India currently are priced significantly higher than what they used to be during the POI. It is important that prevailing exchange rate is considered for an accurate picture of the level of price undercutting and price underselling.

I.2. Views of the domestic industry

- 69. The domestic industry, in its submissions, has inter alia argued as under:
 - That the dumped imports are suppressing the prices of the domestic industry and preventing the price increases that would have occurred in the absence of dumping.
 - That performance of the domestic industry has deteriorated in terms of production, domestic sales, profits, return on investments, cash flow, etc.

- That the performance of the domestic industry continues to be fragile. Impact of dumping is coupled
 with decline in demand owing to recession in the automobile sector which has already caused injury
 to the domestic industry.
- That the producers/exporters in China are having excessive production capacities. In case of
 cessation of the present duty, dumping from China would definitely increase and ultimately cause
 intensified volume and price injury to the Domestic Industry.
- That Dumping Margins determined in previous investigations and estimated in the present investigation are significant and clearly show likelihood of dumping and consequent injury in the event of cessation of anti-dumping duty.
- That in case of expiry of duty, exporters would further channelize their output in the Indian market as
 they are already holding excessive capacities and are in fact selling subject goods to third countries
 at substantially lower prices.
- That the price undercutting without anti-dumping duty is quite significant. Significant price difference
 between the domestic and imported product would motivate the consumers to once again look for
 Chinese imports in large scale. Given the significant demand in India and significant unutilized
 capacities with the Chinese producers, the Chinese producers would readily supply large scale
 volumes in the Indian market at dumped prices.
- That cessation of anti-dumping duty shall lead to continuation and intensified injury to the domestic industry. Given that price undercutting is positive, the domestic industry shall be forced to reduce the price in a situation of cessation of duty, or loose sales volumes. If the domestic industry reduces its price, it shall imply intensified price injury in the form of deterioration in profits, return on capital employed and cash flow. If the domestic industry does not reduce the prices, it shall imply loss of sales volumes and consequently, adverse effect on production and capacity utilization.
- That demand for products under consideration has declined in India and globally because of significant recession in automobile industry. Under these circumstances, should the present duty cease, it is evident that the injury to the domestic industry shall intensify.
- That even if domestic industry is suffering injury from some other source or due to some other factor, the Authority is required to examine whether injury to the domestic industry shall continue in the event of cessation of anti-dumping duty. Thus, the legal requirement with regard to continuation of injury implies continuation of injury that is being already suffered by the domestic industry.
- That the importer has given contradictory and misleading submissions. While Ashok Leyland has been asking for "better prices", in the legal submissions made on their behalf surprise has been expressed as to why the petitioner has not been able to increase its prices.
- That there is a direct link between import volumes and the price of domestic industry. Since the
 domestic industry offered a low price, the import volumes declined to low levels.
- That the fact that petitioner has significant exports does not imply that the petitioner is not entitled to
 protection under dumping law. In fact, the Designated Authority has held in the past that even EOU
 and SEZ units are entitled to protection under the law.
- That the Designated Authority may kindly consider (a) capacity with the exporter, (b) their domestic
 consumption and (c) current exports. This alone will clearly establish significant likelihood of injury in
 the event of cessation of anti-dumping duty.
- That the rules do not have any additional condition that the Designated Authority is required to determine whether Domestic Industry has received adequate protection since the imposition of provisional duty in the original investigation. The domestic industry has sought protection against unfair dumping. It is for the exporter to justify that they have not resorted to dumping. If the price at which goods have been exported to India is below the normal value, it must be held that the exporter is resorting to unfair practice of dumping.

- With regard to the contention that the exchange rate has fluctuated since the POI, it is submitted that the fact of dumping causing injury is determined for the period of investigation and, therefore, information prevalent in the period of investigation alone is relevant.
- That the Designated Authority has established practice of considering 22% return on capital employed. If the Designated Authority wishes to adopt return based on past return, the Designated Authority may kindly adopt the past best achieved ROCE for the purpose of determination of non-injurious price.
- The rules provide for information of capacity utilization only if Designated Authority finds that the
 domestic industry has suffered injury due to inefficient utilization of production capacities." In the
 instant case, there is no inefficient utilization of production capacities.
- The Designated Authority may kindly examine reasonableness of interest cost, details of term loans, cash credit limits, short term loans, deposits and other borrowings taken by the company and determine price undercutting and injury margin after including excise duty.
- That the anti-dumping duty is required to be extended further for a period of five years and enhanced taking into account the revised dumping and injury margins and the form of measure is required to be kept as fixed quantum.

I.3. Examination of the issues raised

- 70. The Authority notes the arguments of the other interested parties and various issues raised therein with regard to the claims of injury and causal link and the counter arguments of the domestic industry on the issues raised by the interested parties. All the issues have been addressed hereunder and in relevant places in the finding to the extent relevant.
 - a. As regards the contention that the petition did not contain evidence of likelihood of injury, the Authority notes that post POI data analysis is not a mandatory requirement under the law. The developments in the injury investigation period and the period of investigation are relevant in an antidumping investigation. However, the information for the post POI period becomes relevant and looked into in a situation where the information for the POI establishes no dumping & no injury and no likelihood of dumping & injury, to make an assessment of the likely scenario taking into account these developments. In a situation where the information for the POI is sufficient to determine likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, information for the post POI is not relevant and therefore, not required to be mandatorily examined. However, the Authority has examined the post POI information to the extent necessary and relevant.
 - b. As regards the contention that the present volume of imports is low and does not support the need for continuation of anti-dumping duty, the Authority notes that the legal requirement at the stage of sunset review is likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. Even if import volumes are low at present, the same does not imply absence of any likelihood of dumping and injury in the event of cessation of anti-dumping duty.
 - c. As regards the contention that injury to the domestic industry is due to *inter se* competition between the domestic producers the Authority notes that there is no such evidence provided by the interested parties. It is noted in this regard that Ashok Leyland is a major consumer of the products and therefore, was in a position to assist the Authority in establishing existence of *inter-se* competition to demonstrate the lack of causal link. However, no such information has been provided by Ashok Leyland.
 - d. As regards increase in market share of other domestic producers, the Authority notes that in a scenario of declining demands, changes in market share does not provide a clear position with regard to *inter se* competition. The Authority also notes that the domestic industry has not claimed that it has suffered injury solely because of Chinese imports in India. The present investigation is to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury in the event of cessation of anti-dumping duty taking into account all other factors also which has been addressed adequately.
 - e. As regards absence of causal link claimed by the interested parties, the Authority notes that absence of causal link in the present period is relevant only in a situation where the Authority concludes that the present injury to the domestic industry is because of current dumped imports into the country. The findings in the succeeding sections would establish that the investigation focuses on the

likelihood of injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty. Therefore, what is relevant in the present investigation is whether situation of the domestic industry is likely to deteriorate in the event of cessation of anti-dumping duties. Accordingly, the Authority has examined whether cessation of anti-dumping duty shall lead to continuation or recurrence of dumping and deterioration in performance of the domestic industry.

- f. As regards the arguments that petitioner's main focus is exports, the Authority notes that though the petitioner has significant exports of the product the petitioner has retained its leading position in the domestic market also. It has not been established that the domestic industry has not been able to supply the product because of its export commitments. Further, the data indicates that overall capacity utilization of the domestic industry declined very significantly though it maintained its export performance thereby indicating that the domestic industry could have undertaken significant sales in the domestic market without sacrificing /compromising on its exports.
- g. As regards the arguments of the interested parties that the current exchange rate should be used in all computations, the Authority notes that average exchange rate of the period of investigation is considered for conversion of various values in injury investigation for a fair comparison of cost and prices during that period as a consistent practice of the Authority. Adoption of current exchange rate for conversion of cost and prices of the POI would distort these figures for comparison and therefore, is not appropriate.
- 71. All other issues raised by the interested parties have been addressed in the relevant sections in this finding.

I.4 Post Disclosure Comments of Domestic industry and other interested parties

- 72. In their post disclosure comments the exporters/importers and other interested parties have further submitted that
 - That the correct legal position as per Section 9A(5) of Customs Tariff Act, 1975 is that anti-dumping may be continued pursuant to a sunset review only when (a) dumping and injury is continuing, or (b) there is a likelihood that dumping and injury will recur if the anti-dumping duties are revoked. Anti-dumping duty can be continued in the present case only when the above legal standard is met.
 - That there is a significant inter se competition between different Indian producers which is evident from the data submitted by Ashok Leyland. It has been argued that other producers in India are actually offering the subject product at very low prices and Ashok Leyland has in fact purchased significant quantities from Indian producers other than the domestic industry at prices much lower than the prices offered by the petitioner domestic industry. Therefore, other Indian producers are severely undercutting the prices of the domestic industry rather than imports, and therefore, injury to domestic industry is due to severe *inter se* competition and not imports of the subject product. The other Indian producers have aggressively captured the market share of the domestic industry.
 - That in light of the decline in the domestic industry's sales due to recession in the automobile sector as admitted by the domestic industry and correctly observed by the Authority and severe inter se competition, it would not be correct to state that injury to the domestic industry is due to imports when imports have been miniscule (only 2% in demand) during the POI. The domestic industry itself has admitted that the reason for injury is other factors. Blaming imports for injury to the domestic industry will not alleviate or change the domestic industry's position.
 - That it is an undisputed fact that share of the domestic industry has reduced for FAB, as other Indian producers have been aggressively capturing this market. Further, it is an undisputed fact that the domestic industry's market share for steering knuckles has improved despite recession in the automobile sector and stiff competition from other Indian producers. These aspects are relevant to demonstrate that the domestic industry is actually facing inter se competition from other Indian producers for both FAB and steering knuckles and not imports of the subject product, which comprise merely 2% of the Indian demand during the POI. In fact, if market share of imports had been increasing in a situation of declining demand, then, it would have made sense to continue the antidumping duty. However, when the market share of imports is declining in a situation of falling demand, it shows that imports are not able to make a place for them in the Indian market and are not able to cope up with Indian producers. Therefore, market share is an important parameter which cannot be ignored in injury analysis.

- That for the purpose of price undercutting and underselling analysis Designated Authority should adopt landed value based on the data submitted by the cooperating exporters or Ashok Leyland and not the DGCI&S Data.
- That the argument that domestic industry is not able to increase its prices because of alleged dumped imports would stand only if the domestic industry and the exporters from the subject country were catering to the same buyers. In this case, cooperating exporters from the subject country are catering to only one buyer in India, Ashok Leyland.
- That the only one reason for price depression/price suppression is the *inter se* competition between the domestic industry and other Indian producers and this should be taken into account in the injury analysis. It has been further argued that the import volumes are too low for causing price suppression or depression.
- That many of the injury parameters of the domestic industry show improvement and domestic industry remained in profits despite decline in demand due to recession in the automobile sector and aggressive *inter se* competition. Further, the domestic industry's return on capital employed has also remained healthy throughout the injury analysis period. The domestic industry was making exceptional profits till 2011-12, and then its profits slightly declined in the subsequent period. It has to be appreciated that the domestic industry itself has attributed this fall in profits to decline in demand due to recession in automobile sector. *Inter se* competition is also the reason of decline in profits after 2011-12. Therefore, any comparison of profitability for the POI with 2011-12 will only give a skewed picture.
- That there does not appear to be any likelihood or recurrence of dumping and injury to the domestic industry if anti-dumping duty is revoked. In this regard, Imports of steering knuckles during the POI have in fact been at prices above the non-injurious price of the domestic industry. Therefore, it is incorrect to state that the subject products have been entering the Indian market at dumped prices when the reality is opposite.
- That as per the post POI analysis carried out by the interested parties the domestic industry's
 profitability has significantly improved in the post POI period; its performance across all economic
 parameters has also improved. The domestic industry's claim of injury due to sluggish demand has
 also been alleviated as demand for the subject product has significantly increased due to better
 demand of medium and heavy commercial vehicles in the post POI period.
- That imports caused no injury to the domestic industry and there is a strong likelihood that imports
 will not be at dumped prices and shall not cause any injury to the domestic industry if the antdumping duty is revoked. The present facts also do not indicate recurrence of dumping and injury if
 the ant-dumping duty is revoked.
- That the Authority has erred in arriving at the volume of imports for steering knuckles and its
 corresponding prices. As per Respondents' analysis, import volume of steering knuckles is low in the
 post POI period, while landed value of imports of steering knuckles as is very high as compared to
 the analysis conducted by the Designated Authority. In light of this, the Designated Authority is
 requested to re-examine the post POI data for volume and value of imports of the subject product.
- That it is evident from the statement given by the petitioner in its Annual Report for 2014-15 that the Petitioner is thriving as a result of resurgence in the demand of medium and heavy commercial vehicles in India and abroad. Petitioner's financial performance has also considerably improved.
- That the present sunset review be terminated, as there is no injury to the domestic industry due to alleged dumped imports and dumping and injury is neither continuing nor is there any likelihood of dumping and injury if anti-dumping duty is revoked.
- That without prejudice to the above, if the Designated Authority decides to continue anti-dumping duty in the present case, the Authority should levy anti-dumping duty based on the lower of dumping margin or injury margin calculated in this sunset review and not at the rate calculated at the time of original investigation.
- 73. In its post disclosure comments the domestic industry has inter alia submitted as follows:
 - a) That the original investigation has shown that market share of Chinese imports in case of FAB increased from 0% in 2006-07 to 23.78% in that POI and 61.80% in post POI. Similarly, market share

of steering knuckle increased from 0% in 2006-07 to 17.47% and 19.98% respectively in POI and post POI of that case. The domestic industry lost market share to the proportionate extent very rapidly and the profitability of the domestic industry declined steeply over the injury period. In the present case the price undercutting are significant while the demand for the products has declined in the current injury period. Therefore, if the anti-dumping duties ceases, the domestic industry shall suffer significant adverse volume and price effects.

- Though the products are produced and sold in numbers, for the purpose of cumulating different types of PUC, the Authority considered, at the time of original investigations, that it was appropriate to express different types of PUCs on weighted average basis. While it may be appropriate, in fact necessary/imperative, to express various types of product on weight basis, the price analysis on weight basis is now quite misleading. Therefore, the dumping margin and injury margin are now required to be determined after converting the data back to numbers before comparison. This is for the reason that in this investigation, the Chinese producers have sold two types of steering knuckle and two types of Front Axle Beams. While petitioner has sold both types of Front Axle Beams, the petitioner has not supplied FA-99 type of steering knuckles either in forged or in machined form. Further, the raw and finished weight of FA-99 knuckles is significantly different. Even the consumption of raw materials significantly differs depending on the type of knuckle.
- Since there is no inefficiency in production process the NIP should be determined by considering the
 actual cost of production. At worst the incidence of overhead costs may be adjusted for the lower
 production in the present POI.
- In the absence of actual disclosure how Authority has determined capital employed, petitioner is not
 in a position to comment on the appropriateness of the figures relating to capital employed adopted
 for determining NIP. It is, however, very clear that the Authority has adopted very low level of profits
 for determining NIP.
- That the Authority has substantially reduced the SGA expenses and has adopted an amount which is substantially lower than the amount of SGA reported by the petitioner.
- That it is evident that the Authority has excluded some expenses which are not disclosed in the
 disclosure statement. Now that the DA has specific Rule laid down for determination of NIP, it would
 be grossly inappropriate to go beyond the Rules and exclude some expenses, exclusion of which is
 not specifically provided under the rules.
- That Imports from China PR have continued to enter at dumped prices after imposition of antidumping duty. The volume of imports has declined drastically, which is due to the duty imposed. The low volume of imports clearly establishes that the current import volumes and prices are not representative of the likely situation in the event of cessation of ADD and the Chinese producers are likely to intensify dumping both in terms of volume and price in the event of cessation of ADD.
- That in a peculiar demand decline situation like this and sporadic imports during the injury investigation period, the higher import price or lower market shares are not sufficient and appropriate indicators of the situation of the domestic industry in the event of cessation of ADD.
- That though the landed prices of the dumped imports have increased over the injury investigation period they have remained significantly below the selling prices of the domestic industry throughout the injury investigation period.
- That the performance of domestic industry during the investigation period was adverse, both, in terms of volume and price parameters. Therefore, cessation of ADD shall result in intensified injury to the domestic industry, given significant price difference between the domestic and imported product. There is no reason why a large consumer such as Ashok Leyland will give higher prices to the domestic industry and place orders for the same volumes when they can source the product at much lower prices.
- That the volume of imports from the subject country has declined to low levels because of ADD. Such
 low volumes will not be reflective of the likely dumping margin or injury margin in the event of
 revocation of duties. The anti-dumping duty based on such margins will not be able to curb dumping
 and consequent injury to the domestic industry.

- That the purpose of the sunset review is to consider likely situation in the event of cessation of ADD
 and therefore, the present prices are not reflective of likely situation. Even the Chinese exporter and
 Indian importer/consumer have heavily contended throughout the course of the investigations that the
 volume of imports during the present period has been negligible. ADD quantum cannot be based on
 negligible volumes.
- That imposing anti-dumping duty on the basis of the margins determined in the original investigation, when the volume of imports was significantly high would be more appropriate and reflective to their actual price and would be able to curb dumping.
- That the exporters and producers should not be rewarded with the lower anti-dumping duty which
 would result in intensified dumping.
- That the Rules provide for a determination of whether the anti-dumping duties should be extended further. This implies a decision on whether or not to extend the duties further. While the Designated Authority in practice has also utilized this opportunity to modify the quantum of anti-dumping duties, such opportunity is not available where the case is based on likelihood of dumping and injury. In the present case, extension of ADD is based on the grounds of likelihood and therefore in any case the volume and price of imports should not be benchmark for deciding on the quantum of ADD.
- That the practice being followed by third countries such as Canada, US and Europe is to decide whether or not to extend the anti-dumping duties. These countries do not at all alter the quantum of anti-dumping duties even if there are significant imports in the POI and the dumping margin & injury margin (EC) is quite lower than existing anti-dumping duties.
- That there is past precedence available wherein the Designated Authority has extended the same quantum of duty as has been recommended in their respective original investigations in spite of dumping margin in review cases being lower than what was been determined in the original investigations. Therefore, the quantum of duty should remain same as has been recommended by the Designated Authority in the original investigation.
- That the duty may be continued to be expressed as fixed quantum of anti-dumping duty expressed as duty in US\$/kg.
- 74. For the sake of brevity the issues raised in the post disclosure comments of the parties have been addressed in the respective sections in this finding and therefore, not being repeated here.

J. Examination of current Injury and Causal Link

- 75. Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
- 76. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or investments have been considered in accordance with Annexure II of the Rules. All economic parameters affecting the Domestic Industry as indicated above have been examined as under:

J.1 Volume Effects of Dumped imports

(a) Import volumes & market share

77. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or

- consumption in India. The Authority has examined the volume of imports of the subject goods from the subject country and other countries based on the transaction-wise import data provided by DGCI&S.
- 78. The Authority notes that DGCI&S reports the imports of the subject goods in numbers. As per the questionnaire response filed by the cooperating exporters from China, who are reportedly the only exporters from that country, only machined products have been exported to India during this period. Therefore, the import weight has been converted taking into account the unit weight of the machined products as reported by the exporters. Accordingly, volume of imports of the subject goods are as follows:

(a)

Volume of Imports	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Front Axle Beam					
Subject Country-China	MT	2,143	2,143	1,417	279
Other Countries	MT	-	-	-	-
Total Imports	MT	2,143	2,143	1,417	279
Steering Knuckles					
Subject Country-China	MT	669	1,089	790	181
Other Countries	MT	-	-	-	-
Total Imports	MT	669	1,089	790	181

(b)

79. The DGCI&S import data when compared to the export data of the cooperating exporters show some variation in quantities apparently due to the time lag between the exportation from the subject country and importation into India. Therefore, the DGCI&S data has been adopted for this investigation. The data indicates that the subject goods are being imported only form China and the imports have significantly declined after imposition of anti-dumping duty over the injury period after imposition of duties.

(b) Assessment of Demand/Apparent Consumption

80. Demand or apparent consumption of the product in India has been assessed based on the domestic sales of Indian producers, and imports from all sources. The estimated consumption of the captive producers has also been considered. Accordingly, estimated demand of the subject goods in the domestic market is as follows:

Product- Front Axle Beam	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Sales of Domestic Industry	MT	20,191	19,175	11,531	9,233
Subject Country- China	MT	2,143	2,143	1,417	279
Sales of other Indian producers	MT	3,338	3,020	3,704	2,780
Demand/consumption excluding captive	MT	25,672	24,338	16,652	12,292
Demand/consumption excluding captive	Trend	100	95	65	48
Estimated Captive Consumption	MT	5,901	6,065	4,809	6,199
Demand/consumption including captive	MT	31,573	30,403	21,461	18,491
	Trend	100	118	84	72
Product- Steering Knuckles	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Sales of Domestic Industry	MT	718	1,048	1,285	1,250
Subject Country- China	MT	669	1,089	790	181
Sales of other Indian producers	MT	5,904	5,873	4,257	3,333
Demand/consumption excluding captive	MT	7,291	8,010	6,331	4,764
Demand/consumption excluding captive	Trend	100	110	87	65
Estimated Captive Consumption	MT	5,764	6,634	4,461	3,902
Demand/consumption including captive	MT	13,055	14,644	10,792	8,666
	Trend	100	112	83	66

81. The above data indicates that the demand for both the products have declined significantly over the injury period. The petitioner has submitted that this decline in demand is due to decline in the consumption pattern of the automobile industry in India. The petitioner has further submitted that production and sales of heavy and medium commercial vehicles has declined globally over the injury period due to general macroeconomic factors and significant recession in automobile industry leading to decline in the demand for the products under consideration. Under these circumstances, should the present duty ceases, the

injury to the domestic industry shall intensify. In this connection the data on production and sale of commercial vehicles in last 4 years have been presented as given below.

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
Local Sales	Nos	323,059	348,701	268,689	200,627
Export Sales	Nos	28,349	27,917	19,524	28,813
Total Sales	Nos	351,408	376,618	288,213	229,440
Production	Nos	345,818	383,277	280,677	221,626

Source: SIAM (Society of Indian Automotive Manufacturers)

82. The above data indicates a significant drop in production and sale of commercial vehicles in India. Therefore, the decline in demand for the subject goods, which are major fitment items in automobiles have also declined during this period. The responding exporters have contended that the injury, if any, suffered by the domestic industry is due to this decline in demand and recession in Automobile industry and has nothing to do with the imports from China which is very insignificant. The Authority recognizes the fact that decline in demand in auto-industry is a global phenomenon and some of the injury suffered by the domestic producers is because of this demand situation. But impact of the dumped imports and likelihood of increased dumped imports form the subject country, on the face of decline in global demand, needs to be addressed, while not attributing the injury caused by decline in demand to dumped imports.

(c) Market Share in demand

83. Effects of the dumped imports on the domestic sales and market shares have been examined as follows:

Front axle beam	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Market Share in Demand- excluding Capt	ive			•	•
Sales of Domestic Industry	%	79%	79%	69%	75%
Subject Country-China	%	8%	9%	9%	2%
Other Producers	%	13%	12%	22%	23%
Market Share in Demand- including Capti	ve				
Sales of Domestic Industry	%	64%	63%	54%	50%
Subject Country-China	%	7%	7%	7%	2%
Other Producers	%	29%	30%	40%	49%
Steering knuckles	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Market Share in Demand- excluding Capt	ive		·		•
Sales of Domestic Industry	%	10%	13%	20%	26%
Subject Country-China	%	9%	14%	12%	4%
Other Producers	%	81%	73%	67%	70%
Market Share in Demand- including Capti	ve				
Sales of Domestic Industry	%	6%	7%	12%	14%
Subject Country-China	%	5%	7%	7%	2%
Other Producers	%	89%	85%	81%	83%

- 84. It is noted that the demand of the subject goods has declined during the injury period. As far as FAB is concerned, the market share of the petitioner as well as the imports have declined whereas the share of the other producers has increased though in absolute term the sale of other producers has also declined. However, in case of Steering knuckles the market share of the domestic industry has increased from the base year to the POI while the share of others has declined. The Authority notes that in a peculiar demand decline situation like this and sporadic imports during the injury investigation period, the market shares may not be an appropriate indicator of the situation of the industry.
- 85. The interested parties, in their post disclosure submissions, have argued that there is a severe *inter se* competition in the domestic market and other domestic producers are selling the goods are competitive prices, thereby capturing the market share of the petitioner domestic industry. However, this argument is not borne out of above data. In case of FAB the market-share of the other producers, without considering captive consumption, has increased, but at the cost of imports from China. The petitioner commands 75% of the commercial sales in the domestic market. In case of SK the other producers have significantly lost market share and the petitioner domestic industry has in fact gained that share. Therefore, the

arguments of the interested parties that the *inter se* competition and price undercutting by the other producers is the main cause of injury, if any, to the domestic industry do not stand.

86. It has been further argued by the interested parties that if market share of imports had been increasing in a situation of declining demand, then it would have made sense to continue the anti-dumping duty. However, when the market share of imports is declining in a situation of falling demand, it shows that imports are not able to make a place for them in the Indian market and are not able to cope up with Indian producers. Therefore, market share is an important parameter which cannot be ignored in injury analysis. The Authority notes that the decline in volume of imports and market share of the dumped imports indicate that the antidumping duty imposed was effective in checking the impacts of dumped imports and if the duties are removed it may adversely affect the domestic industry.

J.2. Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

- 87. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. Therefore, both price undercutting and underselling effects of dumped imports have been examined though the volume of import is low.
- 88. The domestic industry, in its post disclosure submissions, has argued that all price related comparisons must be carried out on piece basis for the reasons that the goods are sold in pieces and weighted average comparisons in terms of weights are throwing up skewed results as the domestic industry has not produced and sold certain product types. The Authority notes that in the previous investigation and in the current investigation the analysis of dumping and injury were carried out in terms of weight as suggested by the domestic industry. Therefore, the basis of comparisons cannot be changed at this late stage of investigation only because it might be giving certain skewed results in respect of certain product types because of various factors.
- 89. The exporters, in their post disclosure submissions, have argued that the Authority should adopt the landed value of the responding exporters instead of the landed values as per DGCI&S data for the price analysis. In this connection the Authority notes that the price effect analysis is done based on the volume and value of dumped imports entering the market of the importing country, not the dumped exports leaving the exporting country, during the period of investigation. Therefore, it is necessary to analyse the total volume and value of imports during this period. Accordingly, DGCI&S data has been adopted for this analysis.

(a) Price undercutting

90. For the purpose of examination of the price undercutting effect of dumped imports the net sale realization of the domestic industry for both the products have been compared with the landed values of imports of the corresponding products as per DGCl&S data. In determining the net sales realization of the domestic industry, the rebates, discounts and commissions offered by the domestic industry and the central excise duty paid have been rebated. Only machined form of the products have been imported from China and therefore, selling price of machined products produced and sold by the domestic industry has been considered for determining price undercutting. The price undercutting effect of dumped imports from the subject country have been examined as follows:

Front axle beam- Machined	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Landed price without ADD	Rs/Kg	94.80	106.36	116.01	118.44
Net Selling Price of DI	Rs/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting without ADD	Rs/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	Range	25-35%	15-25%	10-20%	10-20%
Landed price with ADD	Rs/Kg	110.96	123.21	135.14	139.74
Price Undercutting	Rs/Kg	***	***	***	(***)
Price Undercutting with ADD	Range	15-25%	5-15%	0-10%	(0-10)%

Steering knuckles- Machined

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Landed price Without ADD	Rs/Kg	140.29	148.24	163.66	185.79
Net Selling Price of DI	Rs/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting without ADD	Rs/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	Range	20-30%	10-20%	10-20%	5-15%
Landed price with ADD	Rs/Kg	169.84	179.05	198.64	224.73
Price Undercutting with ADD	Rs/Kg	***	(***)	(***)	(***)
Price Undercutting	Range	5-10%	(0-10)%	(0-10)%	(5-15)%

- 91. The above data indicates that though the landed prices of the dumped imports have increased over the injury investigation period they have remained significantly below the selling prices of the domestic industry throughout the injury investigation period. Price undercutting has been significant both in absolute and in percentage term. The duty-paid landed values have negative undercutting. This indicates that while the antidumping duty paid imports do not have undercutting effect on the domestic prices the import without duty continues to be significantly below the selling price of domestic industry. In this connection the Authority notes that it is important to examine whether the domestic prices are already suppressed in response to these import prices leading to negative undercutting of the duty paid imports.
- 92. The interested parties have argued that while prices of imports have been rising both for Front Axle Beams and Steering Knuckles it is surprising that the Domestic Industry is not able to increase its prices despite low volume and high prices of imports. The domestic industry contends that while the buyer, i.e., Ashok Leyland has been asking for better prices, arguments have been made on behalf of the same importer as to why the petitioner has not increased its prices. The interested parties have further argued in their post disclosure submissions that the other domestic producers are offering lower prices and thereby actually affecting the prices of the domestic industry. These arguments of the interested parties are mutually contradictory. The Authority notes that as long as the dumped imports continue to significantly undercut the domestic prices it would be difficult for the domestic producers, including the petitioner domestic industry, to increase the prices. In fact low volume of imports could be because of tight price policy adopted by the domestic industry in order to retain its market share.

(b) Price underselling effects of dumped imports

93. For the purpose of price underselling determination the landed prices of imports of both the products from subject country as per DGCI&S data have been compared with the Non-injurious selling price of the domestic industry for the corresponding products determined in accordance with the norms prescribed in Annex-II to the Rules. Price underselling effects of dumped imports are as follows:

Particulars	UOM	FAB	SK
Weighted Average NIP	Rs/Kg	***	***
Weighted average Landed Price without ADD	Rs/Kg	118.44	185.95
Price Underselling	Rs/Kg	***	(***)
Price Underselling	%	0-10%	(0-10)%
Weighted Average Landed Price with ADD	Rs/Kg	139.74	223.90
Price Underselling	Rs/Kg	(***)	(***)
Price Underselling	%	(5-15)%	(25-30)%

94. It is seen that the imports of FAB from the subject country are entering the Indian market significantly below the non-injurious price of the domestic industry indicating significant price underselling. However, with the antidumping duty in force the price underselling is negative. As far as SK is concerned, the price underselling without duty is marginally negative and with duty the underselling is significantly negative. The Domestic industry has argued that the price underselling is becoming negative because of the skewed comparison on weight terms since they have not produced and supplied one product type of steering Knuckles. The Authority notes that in the absence of matching product types only reasonable method available is to compare it with the closest product type or resort to weighted average comparison which has been adopted in this case. However, price underselling factor may not be deterministic and needs to be examined along with the price suppression/depression analysis as noted earlier.

(c) Price suppression/depression

95. To examine the price suppression or depression effects of the dumped imports on the domestic prices the trend of net sale realization of the domestic industry has been compared with the cost of production of the domestic industry and the landed price of the dumped imports as follows:

Product- Front axle beam- Machined

Particulars	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Cost of sales	Rs/Kg	***	***	***	***
	Trend	100	85	88	88
Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
	Trend	100	99	103	102
Landed Price	Rs/Kg	95	106	116	118
	Trend	100	112	122	125
ADD Paid landed price	Rs/Kg	111	123	135	140
	Trend	100	111	122	126

Product- Steering knuckles- Machined

Particulars	UOM	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Cost of sales	Rs/Kg	***	***	***	***
	Trend	100	90	92	105
Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
-	Trend	100	97	105	111
Landed Price	Rs/Kg	140	148	164	186
	Trend	100	106	117	132
ADD Paid landed price	Rs/Kg	170	179	199	225
	Trend	100	105	117	132

- 96. The above data indicates that in case of FAB the cost of production has considerably declined during the injury investigation period by about 12% compared to the base year. The landed price of imports, which was extremely low in the base year, have gone up by about 25% compared to the base year but still remains significantly below the cost of sales as well as the selling price of the domestic industry. The selling price has marginally improved.
- 97. As far as Steering Knuckles is concerned, the cost of sales of the Domestic industry has marginally increased by about 5% compared to the base year. The landed value of imports which was very low during the base year has improved by about 32% over the base year but still continues to be significantly below the cost of production of the domestic industry. Selling price has improved but remains below cost of sales.
- 98. Interested parties have argued that such small volume of imports could not have suppressed or depressed the prices of the domestic industry and the only one reason for price depression/price suppression is the *inter se* competition between the domestic industry and other Indian producers. However, the data indicates that the domestic industry is apparently holding on to the price line as the import prices are still far below its costs and prices. Since the domestic industry is apparently holding on to the price line and not increasing the prices in response to the increase in landed values the undercutting and underselling margins are negative. That could be reason for the volume of imports not increasing. Domestic industry has argued that if the duties are revoked the landed price of imports shall continue to be significantly lower than the cost and selling price of the domestic industry and therefore, shall lead to further price suppression and financial losses.

J.3 Examination of Economic parameters relating to the domestic industry

(c) Actual and Potential Impact on Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

99. Information on capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry is given in the table below:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Capacity	MT	240,000	240,000	240,000	240,000

Total Production- Plant	MT	162,930	189,036	144,987	145,333
Plant Capacity Utilization	%	68%	79%	60%	61%
FAB					
Production	MT	34,522	44,885	30,859	32,566
Domestic Sales	MT	20,191	19,175	11,531	9,233
Demand excluding captive	MT	25,672	24,338	16,652	12,292
SK					
Production	MT	5,459	6,360	5,303	5,282
Domestic Sales	MT	718	1,048	1,285	1,250
Demand excluding captive	MT	7,291	8,010	6,331	4,764

- 100. The Authority notes that the domestic industry does not have capacities dedicated for the product under consideration alone. The capacities are common to a number of forging and machining products. Therefore, the authority has considered capacity and capacity utilization after including all the products which are sharing common production capacities. The above data indicates that while the plant capacity to produce all forged and machined products has remained same the production has declined by about 10% compared to the base year after a significant increase in 2011-12. Capacity utilization of the plant increased in 2011-12 and declined thereafter. However, the plant capacity and production shown above is for all products manufactured in the said plant and therefore, may not reflect a correct picture about the product under consideration.
- 101. As far as production is concerned, the data indicates that the production of both FAB and SK, after a substantial jump in 2011-12, has declined to marginally below the base year level. However, the sales of the FABs in the domestic market show a significant decline during this period while sale of Knuckles, after some improvement in 2012-12, has remained flat. The Authority notes that the demand for both the products have declined during this period.
- 102. The Authority notes that since the volume of imports of the subject goods during the injury investigation is low actual impact of imports on the above parameters may not be significant. But the data also indicates that if the volume of imports increases in a scenario where there is a significant decline in demand, it will seriously impact the production and capacity utilisation as well as sales of the domestic industry.

(d) Actual and Potential Impact on Profitability, Profits, return on investment and cash flow

103. On the basis of the detailed examination of the cost of production and other associated costs as well as selling prices carried out by the Authority, profits earned by the domestic industry from the sales of the subject goods in the domestic market has been worked out as follows: -

Front axle beam	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Profit/loss	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend		100	112	89	68
Cash Profit	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend		100	109	95	86
Profit before Interest	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend		100	112	99	79
Return on Capital Employed	%	20-30%	25-35%	15-25%	15-25%
Trend		100	125	96	95
Steering knuckles	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Profit/loss	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend		100	476	457	96
Cash Profit	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend		100	180	175	77
Profit before Interest	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend		100	245	245	89
Return on Capital Employed	%	5-15%	25-35%	25-35%	5-15%
Trend		100	348	320	127

104. The interested parties have argued that the domestic industry's return on capital employed has remained healthy throughout the injury analysis period and the domestic industry itself has attributed this fall in profits to decline in demand due to recession in automobile sector. Inter se competition is also the reason of decline in profits after 2011-12. The above data indicates that in case of FAB profit, cash profit, profit before interest and return on capital employed increased up to 2011-12 and then declined over the injury period. The domestic industry continues to earn a good return on capital employed. In case of Steering knuckles profit, cash profit, profit before interest and return on capital employed have shown significant improvement up to 2011-12 and then declined over the rest of the injury period. Though the domestic industry is still earning profit in this segment the profit margins and return on capital employed has significantly declined in the period of investigation.

(e) Actual and potential impact on Market Share

105. As indicated earlier market share of the domestic industry in demand for Front Axle beam has declined and for Steering Knuckles has increased from the base year to the POI. The Authority notes that the volume of imports from China has been very low during the injury investigation period due to imposition of antidumping duty. The demands of the product also show a significant decline. In this situation market shares of various players in the domestic market, as a parameter of injury, may not give a clear indication of the position of the domestic industry.

(d) Actual and potential impact on Employment, Productivity and Wages

106. The Authority notes that the domestic industry being a multi-product company, producing several products in the same unit, impact of dumping of the subject goods may not be reflected in employment and wage factors of the domestic industry. As far as productivity is concerned, it has moved in the same direction as that of production.

Employment and Wages	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
No of Employees	Nos	***	***	***	***
Trend		100	115	101	99
Salaries & Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend		100	125	127	142
Wages per Unit of Production	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend		100	98	141	150
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
Trend		100	112	90	96
Productivity per day	MT	109.54	140.40	99.07	103.69
Trend		100	128	90	95

(e) Actual and potential impact on Inventories

107. Since the products under consideration are made to order items, the domestic industry does not have significant inventories of the product and inventories is not a relevant parameter in the facts of the present case.

(f) Factors affecting domestic prices

108. The examination of data indicates that the dumped imports from the subject country, though low in volume, are still entering the Indian market at prices much below the cost of production and selling prices of the domestic industry causing significant price undercutting and underselling in the Indian market. The cost of production of the domestic industry has also undergone change. The domestic industry, in order to prevent significant erosion of its sales volume in the domestic market, appears to have maintained its price line. There is a significant decline in demand due to general conditions of the automobile sector globally. Therefore, decline in demand owing to recession in the automobile sector for the product, coupled with potential effects of dumping, appears to have affected the prices of the domestic industry.

(g) Actual and potential impact on Growth

109. The Authority notes that in a situation of significant decline in demand growth in various physical and financial parameters would not provide any meaningful guidance on determination of injury on account of dumped imports. However, the Authority notes that the performance of domestic industry during the

investigation period has been adverse, both, in terms of volume and price parameters. Growth with regard to sales, production, market share, profits, return on investments and cash flow was significantly negative during this period.

(h) Ability to raise capital investments

110. The Authority notes that the petitioner is a multi product company covering several forged and machined products across sectors. Therefore, their ability to raise capital is not affected by the performance the production line of the subject goods. However, the company's capacity for fresh investment and expansion of the production line of subject goods is likely to be affected in the current and potential scenario of dumping, coupled with the recession in the auto sector.

(i) Level of dumping & dumping margin

111. The margin of dumping as a factor for determination of injury indicates that dumping margins of the dumped imports determined for the subject country are above *de minimis* level and significant.

K. Overall Assessment of current Injury and Causal links

112. The above analysis of various factors indicate that Physical performance of the domestic industry in terms of production and domestic sales of the subject goods as well as profits in their domestic operations improved in 2011-12 compared to the base year but all the parameters have deteriorated thereafter indicating injury. However, the interested parties have argued that this injury to the domestic industry is on account of other factors such as recession in the Automobile sector and has nothing to do with the imports from China. Therefore, the Authority has examined the other mandatory factors in the light of the issues raised by the interested parties to see if other factors are responsible for the injury to the domestic industry.

(i) Volume and prices of imports from other sources

113. Import data examined shows that the subject goods have been imported from the subject country only. Therefore, imports from other countries are not causing or likely to cause injury to the domestic industry.

(ii) Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

- 114. As noted earlier demand scenario and pattern of consumption for the subject goods in the domestic market shows there has been a significant decline in demand of the products concerned over the injury period which has been attributed to recession in the automobile sector. The interested parties have argued that the injury, if any, is due to the decline in the demand and not because of insignificant import from the subject country. The Authority notes that there was a global slowdown in the automobiles industry and production and consumption of the commercial vehicles in India has also declined during the injury investigation period leading to a decline in demand for the subject products. Therefore, demand is one of the major factors affecting the physical performance of the domestic industry in terms of production volume and sales.
- 115. The Authority also notes the arguments of the petitioner that cessation of anti-dumping duty would significantly intensify injury to the domestic industry in a situation where the demand for the products at present are low, both in the Indian and international markets. It has also been argued that given that there is a significant difference between Indian and Chinese prices the consumers in India would switch over to importing the products from China once the duties are revoked.

(iii) Trade restrictive practices and competition between the foreign and domestic producers

116. The Authority notes that there are few other producers of the subject goods in India who are also producing and selling in the domestic market or consuming the subject goods captivity. The interested parties have argued that the Injury, if any, is either due to *inter se* competition in the Indian market or due to reasons intrinsic to the Domestic Industry. It has been argued that other Indian producers are able to maintain their sales steadily over the injury period and have, in fact, captured the market share of the Domestic Industry. However, the data analyzed in the previous sections does not support this. The data indicates that the sales of other Indian producers have also declined substantially during this period. There is no allegation of unfair competition between these producers or any trade restrictive practices in the domestic market which could have contributed to the injury to the domestic industry. The Authority notes that foreign producers are also competing in the domestic market and allegation of dumping has been established against them.

117. In their post disclosure submissions the interested parties have reiterated their arguments that the injury, if any, to the petitioner domestic industry, is on account of *inter se* competition from other domestic producers and not because of the dumped imports from the subject country and it has been argued that the other producers are offering lower prices in the domestic market and thereby undercutting the prices of the domestic industry and capturing the market share of the petitioner. However, as noted earlier this assertion is not supported by the data as recorded earlier. Therefore, the arguments of the interested parties in this regard are not sustainable.

(iv) Development in technology

118. Technology for production of the products has not undergone any change nor are there any likely changes in the coming future. No argument has been made by any interested party alleging technology as a factor affecting the domestic industry. Certain difference in production process claimed by the Chinese producers have been duly considered and it has been found that the technology and production process used by the Indian producer is an established technology and could not be considered as a cause of injury. Development in technology is, therefore, not a factor causing injury.

(v) Export performance of the domestic industry

119. Petitioner has significant export of the products under consideration during the injury investigation period as per the table given below. The interested parties have argued that the Petitioner continues to focus on export markets, while it could have taken steps to increase its market presence in India. It has been argued that the petitioner cannot take the plea that it is disposing its inventories in the export market because petitioner does not have any inventory of the subject product. The subject products are made to order. The interested parties have reiterated these arguments in their post disclosure submissions. In this connection the Authority has examined the export performance of the domestic industry as follows:

Exports	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Front Axle Beams	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	180	133	167
Forged	MT	***	***	***	***
Machined	MT	***	***	***	***
Steering Knuckles	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	86	86
Forged	MT	***	***	***	***
Machined	MT	***	***	***	***

- 120. The data above indicates that the exports of FAB produced by the petitioner has increased substantially in POI compared to the base year though there is about 10% drop compared to 2011-12. In case of Steering Knuckles however, there is about 14% drop in exports compared to the base year. The Authority notes that in export sales transactions the petitioner continues to have better profit compared to the domestic sales. In a scenario where the domestic demand is low and the price is affected by dumped imports, the domestic industry perhaps has no other option but to tap the export market to maintain production level and recover fixed costs. However, the Authority notes that the injury examination of the domestic industry is restricted to its domestic operations only and losses and injury caused on account of export operations, if any, have not been taken into account.
- 121. Apart from these mandatory non-attribution factors the interested parties have argued that the Authority should address other factors relevant to this case such as decline in production and sales due to recession; and exchange rate considerations. The impact of recession in auto sector has already been addressed in the previous sections. As far as exchange rate fluctuation is concerned, the Authority notes that examination of various factors during the POI is a snapshot examination as per the conditions existed at that time. Therefore, the exchange rate prevailing at that time is the correct exchange rate to be used in the determinations.
- 122. The above analysis shows that the performance of the domestic industry has been impacted by the decline in demand due to recessionary trend in the auto industry and the price effects of the dumped imports in a scenario of declining demand though the volume of import is low. The dumped imports continue to undercut the domestic prices. It appears that the domestic industry has kept the prices

suppressed to prevent potential influx of dumped imports from the subject country in a demand decline situation, leading to injury in terms of decline in profitability.

L. Magnitude of injury and injury margin

- 123. Having regards to the lesser duty Rule followed by the Authority, the margins of injury with respect to the importation of the subject goods from the subject country have also been determined. For determination of injury margin the Authority has determined the Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry as per the procedures laid down in Annexure III of the Anti-dumping Rules. The interested parties have argued that for the purpose of determination of NIP the Authority should not grant a return higher than what was achieved by the domestic industry. The Authority notes that as per consistent practice the procedures laid down by Annexure III of the Anti-dumping Rules have been followed while determining Non Injurious Price. However, the Authority notes that actual return earned by the domestic industry in the past is higher than reasonable return allowed by the authority while determining the Non-Injurious Price.
- 124. In its post disclosure comments the domestic industry has raised several issues regarding the determination of non-injurious price as recorded in the previous section. In this respect of the arguments of the domestic industry that the raw material cost and utilities cost of the domestic industry should be accepted and the overhead cost should be adjusted on the basis of below normal capacity utilization, the Authority notes that such an approach is not permissible as per the antidumping rules. Further the basis of allocation of Net fixed Assets and SGA expenses, as per the consistent practice of the Authority have also disclosed to the domestic industry on confidential basis. Therefore, the arguments of the domestic industry in respect of Non-injurious price have not been found to be tenable.
- 125. Non injurious Price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation in respect of applicant domestic industry in terms of the principles outlined in the Annexure III to the AD Rules. Since only machined products have been imported during the POI, for the purpose of fair comparison NIP for those specific product types have been determined taking into account corresponding products manufactured by the domestic industry.
- 126. The Non-injurious price so determined has been compared with the weighted average landed value of the goods imported during the POI as per DGCI&S data. Accordingly, the margins of injury for the products under consideration imported from the subject country are as follows:

Particulars	UOM	FAB	SK
Weighted average NIP	US\$/Kg	***	***
Weighted average Landed Price as per DGCIS data	US\$/Kg	1.946	3.040
Injury Margin	US\$/Kg	***	(***)
Injury Margin	%	***%	(***)%
Range		0-10%	(0-10)%
Landed Prices of TRA and TRF	US\$/Kg	***	***
Injury Margin	US\$/Kg	***	(***)
Injury Margin	%	***%	(***)%
Range		0-10%	(5-15%)

127. The Authority also notes that the total volumes of imports from the subject country as well as volume exported by the responding exporters during the period of investigation were low and therefore, the landed prices may not be representative enough for assessment of dumping and injury margins during this period. Therefore, the Authority has also examined the volume and value of exports to the third countries to analyze the price levels to assess the likely levels of dumping and injury margins. However, the volume of exports of the responding exporters to third countries is also very low for giving any meaningful indication of price levels. The Authority notes that this being a sunset review

investigation while the duties were in force, the current injury margin may not provide a clear indication of the future level of injurious imports because the dumping margins estimated are significantly positive though volumes are low. Therefore, the Authority has looked at the likelihood aspects of continuation or recurrence of dumping and injury through various other parameters in the following paragraphs.

M. Examination of Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping and Injury

128. The Authority notes that the subject goods continue to enter the Indian market at substantially dumped prices though volume of imports have significantly declined after imposition of duties. Rules require the Authority to examine if the dumping is likely to continue or recur if the duties are revoked and whether the injury to the domestic industry is likely to continue or recur.

M.1 Views of the Domestic Industry

- 129. The domestic industry, in its submissions, has argued that
- That there is continued dumping of the products under consideration from China and though the volume
 of dumped imports has declined, the dumping margin is significant and dumping of the products under
 consideration is likely to intensify from the subject country should the current anti-dumping duty be
 revoked.
- That the producer/exporters in China have significant surplus capacities and if the duties are revoked the exporters would use the surplus capacity to intensify dumping in India.
- That concern of the domestic industry is against unfair dumping practices resorted by Chinese producers because of government support i.e. availability of steel to the industry in China at artificially lower prices.
- That their contention in the original investigation that prices of steel in China are lower than international
 price has not been refuted and the fact is that the price at which steel is available in China is not the price
 at which steel can be imported from China. The price is different even for domestic and exports.
 Therefore, the dumping is likely to continue if the duties are revoked.
- That the condition of the domestic industry is vulnerable and their performance has been adversely
 affected due to the presence of dumped imports from the subject country even when the antidumping
 duty is in force and dumping and consequent injury to the domestic industry is likely to continue and
 intensify further, should the current anti-dumping duty ceases.
- That though the volume of imports from the subject country declined after the imposition of duty the
 extent of imports is significant in the investigation period and is likely to increase significantly in the event
 of cessation of anti-dumping duty.
- That the prices at which subject goods are being imported are substantially lower than the price at which
 the goods are being sold in the domestic market. Therefore, in case of expiry of duty, exporters would
 further channelize their output in the Indian market as they are already holding excess capacities and are
 in fact selling subject goods to third countries at substantially lower prices.
- That the imports from the subject country would cause severe price undercutting in the absence of antidumping duty. Significant price difference between the domestic and imported product would lead to significant increase in the imports of the products under consideration. Therefore, in the event of cessation of current antidumping duty, the domestic industry will have to either reduce the price to maintain sales volumes, or if the domestic industry maintains the current selling price, the domestic industry would lose significant volumes. In either case, it will suffer material injury.
- That cessation of anti-dumping duty would have significant adverse effect on the prices in the market and injury to the domestic industry would continue and intensify.
- 130. In its post disclosure submissions the domestic industry has reiterated its position with respect to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.

M.2 Views of other interested Parties

- 131. The other interested parties, in their various submissions, have argued
 - That in a sunset review the focus of the entire investigation is on the fact whether revocation of antidumping duty will lead to recurrence of dumping or injury to the domestic industry. Thus, it is not the present level of dumping and injury, which is important but the likely dumping and injury, which is more

essential in a sunset review investigation. Thus, an investigating authority has to conduct an analysis of future events to determine likelihood of dumping or injury. However, in the present investigation, Petitioner has not provided any post POI data to indicate continuance of dumping or injury being caused to it, in order to claim likelihood of recurrence of dumping and injury.

- That it has been held in the case of *Indian Spinners Association v. Designated Authority* 2004 (170) E.L.T. 144 (Tri. Del.) that 'existence of surplus production capacity cannot be taken as posing a clearly foreseen and imminent threat of injury. Petitioner has not drawn a link between the alleged presence of excess capacities and the recurrence of injury. Even if the Designated Authority were to presume that there existed excess capacities, the presence of such data itself cannot be a ground for the extension of anti-dumping duties as has been held by the Authority in the sunset review investigation of Aniline from USA and Japan, final findings dated 17th January 2012.
- 132. In their post disclosure submissions the other interested parties have argued that as per their post POI analysis the domestic industry's profitability has significantly improved in the post POI period and injury due to sluggish demand has also been alleviated as demand for the subject product has significantly increased due to better demand of medium and heavy commercial vehicles in the post POI period. It has been argued that imports caused no injury to the domestic industry and there is a strong likelihood that imports will not be at dumped prices and shall not cause any injury to the domestic industry if the anti-dumping duty is revoked. The present facts also do not indicate recurrence of dumping and injury if the anti-dumping duty is revoked.

M.3 Examination by the Authority

- 133. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties earlier imposed on imports of the products under consideration from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury if the duties are revoked. The examination in the earlier sections has established that the subject goods are entering the Indian market at dumped prices in spite of the duty being in force and the domestic industry is suffering injury due to the presence of dumped imports coupled with a situation of significant decline in demand. Therefore, the Authority is required to examine whether cessation of anti-dumping duty is likely to lead to continued dumping of the product and consequent continuation of injury to the domestic industry.
- 134. The Authority notes that as per the information submitted by the responding exporters from China in their questionnaire responses it has been established that the goods are still continuing to be exported from that country at dumped prices though volume is low. In fact the responding exporters, in their submissions, have stated that they are the largest producers of the subject goods in China and though their exports to India have reduced due to imposition of antidumping duty, Indian customers continue to import the product under consideration from them because of better quality of the product and inability of the Indian producers to meet the demand.
- 135. Examination of the capacities and production of the cooperating exporters, who are the known major producers of the subject goods in China and also exporters to India, shows that these producers have significant (about15%) spare capacities for manufacturing both forged and machined products which can be used to produce and export the subject goods if the market in India opens up. The selling pattern of the goods of the exporters also indicates that the producers are mainly dependant on their domestic market and exports to third countries are very negligible. The domestic sales of the exporters during the period of injury investigation are also very flat or shows marginal decline. There was a weak demand in the global market due to poor performance of the auto industry in the world during this period.
- 136. The Authority notes that the duties in force on the subject goods exported by the responding exporters were as follows:

Exporter	Product	Duty
HTRA	FAB	0.35 USD/Kg
HTRF	SK	0.64 USD/Kg

137. The current price levels of the subject goods indicate that even if the prices increase to the extent of the current antidumping duty level, after revocation of the duties, the goods could still be exported at dumped prices and at those prices it would still continue to undercut and undersell the domestic

- industry. The Authority notes that the landed price of the goods exported to India is significantly undercutting the domestic selling prices without application of anti-dumping duties.
- 138. **Volume and value of exports to other countries:** The export volumes and values of the products to third countries, as per the information submitted by the responding exporters, are miniscule. Therefore, with a low domestic demand the producing exporters in China will have greater propensity to export to India once the antidumping duties are removed.
- 139. As far as likelihood of continuation or recurrence of injury is concerned, the Authority notes that the domestic industry continues to suffer injury due to decline in demand coupled with the price pressure of dumped imports. The price at which the subject goods are being exported by China PR to India is an indicator of the likelihood of the price at which the goods are likely to be exported from China in the event of cessation of anti-dumping duty. The landed price of the goods exported to India is significantly undercutting the domestic selling prices without anti-dumping duty.
- 140. **Post POI Demand Scenario**: The Authority notes that the domestic industry is a leading global supplier of the subject goods and enjoys the commanding position in the domestic market. As per the information available in the website of the domestic industry both global and domestic demands for medium and heavy commercial vehicles on which the subject goods are mounted have registered significant increase in post POI period. As per information available, the US trucks sales have increased by about 20% in 2014 over 2013. The demand for the commercial vehicles in India also shows upward swing. The growth of truck sales in India in 2014-15 was about 21% over 2013-14. Therefore, though the performance of the domestic industry was affected by the slump in demand in the injury investigation the outlook is positive as per the post POI trends.
- 141. The interested parties have argued that the since the demand scenario has improved in the post POI period as per their own admission the domestic industry is not likely to be injured if the duties are removed. The Authority notes that the previous investigation has clearly established that in a scenario of good global demand also the volume of dumped imports had increased significantly cornering a significant share of the domestic market and thereby injuring the industry. Though the volume of imports during the POI was low it was at significantly dumped prices. The low volume was clearly because of the duty in force. Once the duty is revoked there is no reason why the volume of imports would not increase significantly given the price level. At that price level and without duty protection the domestic industry will be forced to suppress its prices further leading to material injury.
- **Demand scenario in China and likely effect:** The Authority notes that the responding exporters are the major producers and suppliers of the subject goods in China and over 95% of their output was sold in the domestic market during the POI. India is the only other major market to which almost 15% of their output was sold in the beginning of the injury investigation which has drastically come down to less than 5% in the POI. Exports to other countries are negligible. Therefore, the major producer in China is largely dependent upon its own domestic market and Indian market. The information available on the demand for commercial vehicles in China indicates that the growth of commercial vehicle market in China remained depressed due to slower pace in infrastructure and project construction. China Commercial Vehicle Industry Report and Global Review of the Auto Industry Sector indicate only moderate or low growth projections for this sector in China during 2014-17 because of continuous structural adjustments of China's macro economy and the infrastructure sector in China is not expected to revive soon. Therefore, with a depressed domestic demand scenario the only attractive market for the producers in China would be the Indian market in which they already have significant presence and a substantial volume of their output was dedicated to the Indian market. As the only major market outside China for the Chinese producers, it would be too attractive for the exporters from China to export to India at dumped prices in increasingly large volumes if the duties are revoked. This is likely to have significant volume effect on the domestic producers in India. After the removal of duty the price line may change significantly if the depressed market scenario in China continues as projected. Therefore, it may also lead to significant price effect on the domestic producers leading to recurrence of injury.
- 143. Volume and value of imports in the post POI period: The post POI import data has also been looked at to see the trends of imports and likely scenario in the event of revocation of duty. The interested parties have pointed out certain errors in the post POI import data. Accordingly the import data for the period April to September 2014 has been corrected and the data is as follows:

	April to S	April to Sept'14				
Particulars	Qty	Values	Prices	Landed Price	Landed Price	
	MT	Rs Lacs	Rs/Kg	Rs/Kg	US\$/Kg	
FAB	44	46	106	117	1.91	
SK	148	244	165	182	2.97	

Data source: IBIS

- 144. The Authority notes that antidumping duties were in force during this period and therefore, the trend in imports during this period may be affected by the duty. But it establishes the fact that the imports continue to enter the Indian market and the prices are not significantly different.
- 145. Thus, with the cessation of anti-dumping duties, the Indian prices are likely to be attractive to the exporters in the subject country and there is a strong likelihood that Indian consumers would import substantially due to increase in demand witnessed in the post POI period as recorded above. The exporters would also be encouraged to channelize their output in the Indian market as they have excessive capacities and are already selling their products at low prices. The above analysis indicates that if the present antidumping duty is allowed to cease, dumped imports from the subject country is likely to increase significantly because of the increase in demand in India as per the trends indicated above, price attractiveness of the Indian market, spare capacities available with the exporters and lack of sufficient third country market as is evident from their current export performances.
- 146. The price at which the subject goods are being exported by China PR to India is an indicator of the likelihood of the price at which the goods are likely to be exported from China in the event of cessation of anti-dumping duty. The above factors clearly establish the likelihood of continuation or recurrence of dumping from the subject country in the event of revocation of the duties.
- 147. As far as likelihood of continuation or recurrence of injury is concerned, the Authority notes that the performance of the domestic industry has deteriorated due to decline in demand, coupled with the price pressure of dumped imports. The landed price of the goods exported to India has suppressing effect on the domestic selling prices and without anti-dumping duty the landed prices continue to undercut the domestic prices. In that scenario, if the present antidumping duty is allowed to cease, performance of the domestic industry is likely to decline materially in respect of price parameters as the domestic industry would be forced to further suppress the prices to match import price. Should the domestic industry sells the products at import parity prices, in the event of cessation of ADD, the domestic industry's profitability is likely to drop further leading to material injury.
- 148. In view of the above the Authority concludes that there is continued dumping from China, though low in volume, and performance of the domestic industry has declined in the current injury period due to the impact of current dumping coupled with decline in demand owing to recession in the automobile sector. The dumping is likely to continue and the performance of the domestic industry is likely to deteriorate, should the present anti-dumping duty is revoked leading to material injury.

N. Conclusions:

- 149. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority, as recorded in this finding, the authority concludes that:
 - (i) The subject goods have continued to enter the Indian market from the subject country at prices less than their normal values and the dumping margins are substantial and above *de minimis*, though the volume is low;
- (ii) The performance of the domestic industry has declined due to decline in demand and presence of dumped imports during the injury investigation period but the domestic industry has not suffered material injury during the period of investigation due to the dumped imports;
- (iii) The goods are likely to be exported at dumping prices in the event of cessation of anti-dumping duty and dumping is likely to continue or recur; and
- (iv) There is a strong likelihood of recurrence of Injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty because of continued dumped imports from the subject country;

O Indian industry's interest & other issues

150. The Authority notes that the subject goods are imported by the automobile manufacturers and the cost of the subject goods constitute a very small component of the cost of the heavy and medium commercial vehicles. Therefore, continuation of antidumping duty will not significantly impact the auto sector or the general consumers whereas it will eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the subject goods to the consumers.

P. Recommendations

- 151. The Authority notes that this sunset review investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information and verifiable evidence on various aspects of dumping, injury and causal links and likelihood of continuation of dumping and injury in the event of cessation of the duties. Having conducted the investigation as per the procedure prescribed and having established that dumping is continuing, and dumping and injury are likely to continue or recur if the duties are revoked, in the factual matrix of the case the Authority considers it necessary and appropriate to recommend continued imposition of the anti-dumping duty on imports of subject goods originating in or exported from the subject country as notified under Customs Notification No. 50/2010-Customs dated 12th April 2010, for a further period of 5 years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government.
- 152. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.
- 153. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party as per the time limit stipulated for this purpose.

A. K. BHALLA, Designated Authority